फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 01:52 उपरांत द्वितीया विक्रम संवत 2082

एक सम्पूर्ण दैनिक अखबार

अमृत विचार

| कानपुर नगर |

www.amritvichar.com

2 राज्य | 6 संस्करण

लखनऊ ■ बरेली ■ कानपुर ■ मुरादाबाद ■ अयोध्या ■ हल्द्वानी

सोमवार, 2 फरवरी 2026, वर्ष 4, अंक 163, पृष्ठ 16 ■ मूल्य 5 रुपये

आम बजट 2026-27

अहम बातें

एमएसएमई : ग्रोथ फंड बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एलान

एफएंडओ पर एसटीटी 0 .02 से 0 .05 फीसदी की गई

17 कैंसर की दवाएं व 7 दुर्लभ बीमारी की दवाएं होंगी सस्ती

नए संस्थान, हॉस्टल और यूनिवर्सिटी टाउनशिप

नौकरियां, कौशल और बेहतर अस्पताल को मिलेगा बढ़ावा

किसानों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें टेक सपोर्ट देगी सरकार

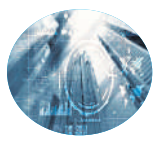

बैंकिंग और निवेश में सुधार पर फोकस

इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

7,84,678.28 रक्षा

2,77,830 रेलवे

1,39,289.48 शिक्षा

1,06,530.42 स्वास्थ्य

2,55,233.53 गृह मंत्रालय

सभी राशि करोड़ रुपये में

टैक्स वही, सोच नई

53.5 लाख करोड़ का बजट वित्त मंत्री ने किया पेश

बजट में लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज किसानों और युवाओं पर फोकस

7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाने के साथ मेगा टैक्सटाइल पार्क किए जाएंगे विकसित

ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट 15% बढ़ाया 2047 तक ग्लोबल लीडर बनने का लक्ष्य

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सहित पांच प्रमुख राज्यों में चुनाव करीब होने के बाद भी उन्होंने लोकलुभावन घोषणाओं से परहेज रखा। साथ ही सुधार एक्सप्रेस को जारी रखते हुए वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए कर छूट और कृषि एवं पर्यटन क्षेत्रों को प्रोत्साहन का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने संसद में कुल 53.5 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। छोटे उद्यमों एवं विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। अब तक के सर्वाधिक 12.22 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ इस बजट को बढ़ते वैश्विक जोखिमों के बीच वृद्धि को बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक रूपरेखा के रूप में देखा जा रहा है। सीतारमण ने छूट को युक्तिसंगत बनाकर सीमा शुल्क व्यवस्था को सरल बनाया है। इसके तहत 17 कैंसर दवाओं पर सीमा शुल्क से छूट दी गई है। बैगेज नियमों में ढील के साथ व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं पर शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

छोटे उद्योगों के साथ कृषि, पर्यटन क्षेत्रों पर जोर

नई दिल्ली। निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार रिकॉर्ड नौवां बजट पेश करते हुए वैश्विक अनिश्चितता के बीच बुनियादी ढांचे पर सरकार के जोर को बनाए रखते हुए पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया जो पिछले वित्त वर्ष में 11.2 लाख करोड़ रुपये था। उन्होंने कहा कि सरकार सात क्षेत्रों औषधि, सेमीकंडक्टर, दुर्लभ-खनिज चुंबक, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र और खेल सामग्री में विनिर्माण को बढ़ावा देने को प्राथमिकता देगी। साथ ही, रोजगार सृजन और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास पर भी जोर दिया जाएगा। बजट में पशुधन, मत्स्य पालन और उच्च मूल्य वाले कृषि क्षेत्रों के लिए भी कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई। वहीं भारत को जैव-औषधि विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। कपड़ा क्षेत्र के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम की भी घोषणा की गई। पर्यटन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पारिस्थितिकी रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्गों के विकास के साथ-साथ 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास का भी प्रस्ताव किया गया। लघु उद्यमों को बढ़ावा देने और भविष्य के 'चैंपियन' तैयार करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई वृद्धि कोष बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करने की बात कही गयी है। बजट में घोषित उपाय पिछले वर्ष आयकर में छूट और जीएसटी कटौती के पूरक हैं। इन उपायों ने बुनियादी ढांचे पर खर्च, श्रम कानून में सुधार और रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती के साथ मिलकर भारतीय अर्थव्यवस्था को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत के शुल्क का सामना करने में मदद की है।

वित्त मंत्री ने बताए 3 कर्तव्य

सीतारमण ने बजट पेश करते हुए सरकार का विकास रोडमैप सामने रखा। उन्होंने तीन मूल कर्तव्यों गिनाए।

- **आर्थिक ग्रोथ :** सरकार का पहला कर्तव्य है भारत की आर्थिक वृद्धि को तेज रखना। वैश्विक हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और सरकार का लक्ष्य है कि वृद्धि दर को लगातार ऊंचा रखा जाए।
- **जनता की उम्मीद :** दूसरा कर्तव्य है जनता की उम्मीदों और उनके भरोसे पर खरा उतरना। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, युवाओं के अवसर, महिला सशक्तिकरण और रोजगार ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार बजट के जरिए सीधे राहत देने और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है।
- **सबका साथ, सबका विकास :** सरकार का तीसरा कर्तव्य है विकास को सबके लिए समान और सुलभ बनाना। सीतारमण ने कहा कि किसी भी नीति या योजना का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे।

यह हुआ महंगा

- इनकम टैक्स में गलत जानकारी देना : टैक्स की रकम के 100% के बराबर पेनल्टी
- चल संपत्ति का खुलासा न करना : अब इस पर पेनल्टी लगेगी
- स्टॉक ऑप्शन और फ्यूचर्स ट्रेडिंग : सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स 0 .02% से बढ़ाकर 0 .05% किया गया
- छाते और उनके पार्ट्स पर 10 प्रतिशत या 25 रुपये प्रति किलो (जो भी ज्यादा हो) ड्यूटी लगेगी
- शराब, मिनरल्स और स्क्रैप की बिक्री पर टीसीएस अब 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2% की
- क्रैनबेरी पर ड्यूटी 5 प्रतिशत और ब्लूबेरी पर 10 प्रतिशत कर दी गई है
- पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड पर ड्यूटी अब शून्य से बढ़ाकर 7 .5 प्रतिशत कर दी गई है।
- चबाने वाला तंबाकू, जर्दा और गुटखा पर एनसीसीडी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 कर दिया

सस्ती हुई चीजें

- माइक्रोवेव ओवन के खास पार्ट्स पर अब बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं
- चमड़े के निर्यात में इस्तेमाल होने वाले कुछ खास इनपुट्स को ड्यूटी-फ्री आयात की सुविधा
- बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर कस्टम ड्यूटी माफ
- सोलर ग्लास बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोडियम एंटीमोनेट पर कस्टम ड्यूटी हटी
- न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए आयात किए जाने वाले सामान पर 2035 तक कस्टम ड्यूटी माफ
- एविएशन सेक्टर के पार्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी माफ
- विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस की दर 5–20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर की गई
- विदेश में पढ़ाई के खर्च पर एलआरएस के तहत अब कम टीडीएस लगेगा।
- एनर्जी ट्रांजिशन से जुड़े उपकरणों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी माफ
- फ्रोजन टर्की मांस और खाने योग्य ऑफल पर टैरिफ 30 से घटाकर 5 प्रतिशत
- आर्टेमिया सिस्ट और कैंसर की कुछ दवाओं पर टैरिफ 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य

एसटीटी बढ़ोतरी से बाजार धराशायी, सेंसेक्स 1,547 अंक टूटा

मुंबई। वायदा सौदों पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने की केंद्रीय बजट में घोषणा के बाद रविवार को घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,547 अंक लुढ़क गया जबकि निफ्टी 495 अंक टूटकर बंद हुआ। मार्केट में भारी बिकवाली के दबाव में निवेशकों के 9 .40 लाख करोड़ रुपये डूब गए। विश्लेषकों के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण में वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) खंड में सौदों पर एसटीटी को बढ़ाने का ऐलान बाजार को पसंद नहीं आया और यह बहुत तेजी से नीचे चला गया। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स शुरुआती बढ़त गंवाते हुए दोपहर के कारोबार में 2,370 .36 अंक यानी 2 .88 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 80,000 अंक के अहम स्तर से भी नीचे फिसलकर 79,899 .42 अंक पर खिसक गया था।

• सात साल में सबसे बड़ी गिरावट, वित्त मंत्री बोलीं- सट्टेबाजी को रोकना है मकसद, निवेशकों के 9.40 लाख करोड़ डूबे

हालांकि, बाद में सेंसेक्स थोड़े सुधार के साथ 1,546 .84 अंक यानी 1.88 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,722 .94 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 495 .20 अंक यानी 1 .96 प्रतिशत गिरकर 24,825 .45 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 748 .9 अंक यानी 2 .95 प्रतिशत लुढ़ककर 24,571 .75 अंक के निचले स्तर तक चला गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) धीरज रेल्ली ने कहा, एसटीटी में प्रस्तावित बढ़ोतरी अल्पावधि में पूंजी बाजार से जुड़ी इकाइयों के लिए दबाव बना सकती है, हालांकि दीर्घावधि में इसके सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं।

140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं वाला बजट

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है और सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है तथा विकसित भारत के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तैयार करता है। मोदी ने कहा कि बजट में अवसरों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि बजट में देश की नारी शक्ति का प्रतिबिंब झलकता है। सीतारमण ने लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मोदी ने कहा कि इस वर्ष का बजट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं को नई गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा की नींव है। इस वर्ष का बजट भारत की सुधार एक्सप्रेस को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेगा। भारत केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं है और यह बजट भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को मजबूत करता है।

विकसित भारत के निर्माण का प्रेरणादायी संकल्प-पत्र

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह विकसित भारत के निर्माण का एक प्रेरणादायी संकल्प पत्र है। उन्होंने कहा यह बजट युवाओं को अवसर, किसानों को सुरक्षा, उद्यमियों को प्रोत्साहन, मध्यम वर्ग को राहत और श्रमिकों को सम्मान प्रदान करेगा। योगी ने कहा यह बजट नवाचार, विनिर्माण और रोजगार को नई गति देने के साथ ही कृषि, ग्रामीण विकास, अवसंरचना, पर्यटन, संस्कृति और ज्ञान परंपरा को सशक्त बनाते हुए 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को साकार करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एमएसएमई, स्टार्टअप और स्वदेशी उत्पादन को समर्थन देकर 'आत्मनिर्भर भारत' की नींव को और सुदृढ़ किया गया है।

वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान

नई दिल्ली। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि 2026–27 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.3 प्रतिशत रहेगा जो चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमानित 4.4 प्रतिशत से कम है। कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष में राज्यों को कर हस्तांतरण राशि के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये प्रदान करेगी जबकि शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष 2025–26 के लिए बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा (सरकारी व्यय और आय के बीच का अंतर) सकल घरेलू उत्पाद (जीडपी) का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

एक लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को शामिल करने और आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान को मजबूत करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने की घोषणाएं इस बार आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए खास हैं। इसी के साथ भारत को चिकित्सा पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित करने में राज्यों को सहायता देने के लिए योजना शुरू करने की घोषणा भी देश के चिकित्सा विशेषज्ञों को काफी भायी है।

स्वस्थ भारत

• स्वास्थ्य मंत्रालय को 1,06,530 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

10% पिछली बार से ज्यादा

निजी क्षेत्र की साझेदारी में बनेंगे पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 2026-27 के बजट में 1,06,530.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो 2025-26 के बजट के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा है। सरकार ने भारत को एक प्रमुख चिकित्सा पर्यटन गंतव्य के तौर पर बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब बनाने में राज्यों की मदद के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि ये हब एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल परिसर के तौर पर काम करेंगे, जिनमें चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं शामिल होंगी। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय दूर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए, बजट आवंटन को 45 करोड़ रुपये से कुछ बढ़ाकर 51 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 350 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। स्वायत्त इकाइयों के लिए बजट आवंटन 2024-25 में 21,901.98 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 22,343.97 करोड़ रुपये हो गया है।

नई दिल्ली स्थित एम्स के लिए आवंटन 5,238.70 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5,500.92 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जबकि आईसीएमआर के लिए 4,821.21 करोड़ रुपये चिह्नित किए गए हैं, जो लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि है।

केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटन 37,100.07 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 39,390 करोड़ रुपये किया

530.42 करोड़ रुपये में से 1,01,709.21 करोड़ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा 4,821.21 करोड़ रुपये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए

आयुष्मान भारत का बजट 5.6% बढ़ा

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए आवंटन 8,995 करोड़ से बढ़ाकर 9,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

अगले पांच साल में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

नई दिल्ली। बजट में अगले पांच वर्षों में बायोफार्मा क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। इस कदम से देश के दवा उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 'बायोफार्मास्युटिकल्स' या 'बायोलॉजिक्स' ऐसे जटिल औषधीय उत्पाद होते हैं, जिन्हें रासायनिक संश्लेषण के बजाय जीवों, कोशिकाओं या ऊतकों से तैयार किया जाता है। वित्त मंत्री ने विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा समेत छह प्रमुख क्षेत्रों के लिए ठोस पहल करने का प्रस्ताव रखा।

दस क्षेत्रों में जोड़े जाएंगे एक लाख स्वास्थ्य पेशेवर

नई दिल्ली। अगले पांच सालों में ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और एप्लाइड साइकोलॉजी समेत अलग-अलग क्षेत्रों में करीब एक लाख सहायक स्वास्थ्य पेशेवरों (एएचपी) को जोड़ा जाएगा। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि एएचपी के लिए मौजूदा संस्थानों को उन्नत किया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्र में नए एएचपी संस्थान बनाए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत के युवाओं के लिए कौशल वाले रोजगारों के नए रास्ते बनेंगे। इसमें ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, एप्लाइड साइकोलॉजी और व्यवहार संबंधी सेहत समेत 10 चुने हुए क्षेत्र शामिल होंगे।

कैंसर के साथ सात अन्य दुर्लभ बीमारियों की दवाओं की कीमतें होंगी कम

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में कैंसर के साथ सात और दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए रियायतों की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर की 17 दवाओं पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी यानी इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा सात और दुर्लभ बीमारियों के उपचार में काम आने वाली दवाओं के आयात शुल्क में भारी छूट दी गई है। मूलभूत सीमा शुल्क वह टैक्स है जो भारत सरकार विदेशों से आयात किए जाने वाले सामान पर लगाती है और यह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत लिया जाता है। इस फैसले का सबसे बड़ा असर कैंसर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के काम में आने वाली दवाओं की कीमत पर पड़ेगा।

- बुजुर्गों और सहायक देखभाल सेवाओं के लिए एक मजबूत देखभाल प्रणाली बनाई जाएगी।

अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान

नई दिल्ली। पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली और दवाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का बजट में प्रस्ताव रखा गया। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद आयुर्वेद को दुनिया भर में पहचान और मान्यता मिली। अच्छी गुणवत्ता के आयुर्वेद उत्पाद जड़ी-बूटियों की पैदावार करने वाले किसानों और इनका प्रसंस्करण करने वाले युवाओं की मदद करते हैं।

वित्त मंत्री ने बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने, प्रमाणन तंत्र के लिए आयुष फार्मेसी और दवा जांच प्रयोगशालाओं को उच्च मानकों पर पहुंचाने और अधिक कुशल लोग उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री ने कहा, प्राचीन भारतीय योग, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही सम्मान है, को तब बड़े पैमाने पर वैश्विक पहचान मिली जब प्रधानमंत्री इसे संयुक्त राष्ट्र में ले गए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बाद, आयुर्वेद को भी वैसी ही वैश्विक पहचान मिली। वित्त मंत्री ने जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र को उन्नत करने का भी प्रस्ताव रखा ताकि पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके।

निमहांस 2.0 के साथ रांची मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के रूप में उभरेगा

रांची। अपने मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के लिए जानी जाने वाली झारखंड की राजधानी रांची को इसका पहला निमहांस मिलने जा रहा है, जो उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को रांची में दूसरे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस 2.0) की स्थापना की घोषणा की।

पहला निमहांस बेंगलुरु में स्थित है। शहर के दो प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में से एक केंद्र द्वारा संचालित रांची तांत्रिका और मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान 100 से अधिक वर्षों से मनोरोग देखभाल, अनुसंधान और पुनर्वास के प्रमुख केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे हैं। सीआईपी अधिकारियों ने कहा कि वे संस्थान को निमहांस की तर्ज पर उन्नत करने की मांग कर रहे थे। इस संस्थान की स्थापना अंग्रेजों ने 17 मई 1918 को रांची यूरोपियन लुनेटिक असाइलम के नाम से की थी। सीतारमण ने कहा, उत्तर भारत में कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं हैं। इसलिए, हम निमहांस 2.0 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नत करेंगे।

शिक्षित भारत

8.27% से ज्यादा वृद्धि

शिक्षा के क्षेत्र के लिए आम बजट 2026-27 में 1.39 लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए 55,727 करोड़ रुपये शामिल

प्रमुख औद्योगिक लॉजिस्टक केंद्रों के पास देश में बनेंगी 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप

नई दिल्ली, एजेंसी

युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का उद्देश्य

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक 'लॉजिस्टिक' केंद्रों के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप स्थापित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाने में राज्यों को सहयोग देगी। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा, 'इन प्रस्तावित शैक्षणिक क्षेत्रों में कई विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, कौशल केंद्र और आवासीय परिसर होंगे।

केंद्र सरकार ने बजट में शिक्षा को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखते हुए इस वर्ष 8.27 प्रतिशत से अधिक धनराशि का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री की ओर से पेश किए गए बजट में शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2025-26 के बजट में कुल 128650 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। सरकार का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। बजट में उच्च शिक्षा और खासतौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (एसटीईएम) को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

हर जिले में बनेगा गर्ल्स हॉस्टल 700 से ज्यादा जिले हैं पूरे देश में

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के हर जिले में एक बालिका छात्रावास (गर्ल्स हॉस्टल) स्थापित करने की घोषणा की। देश में 700 से अधिक जिले हैं। सीतारमण ने पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं के लिए ऋण से जुड़ी पूंजीगत सब्सिडी सहायता योजना का भी प्रस्ताव रखा। मंत्री ने आयुष औषधालयों और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन तथा गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रमुख औद्योगिक ''लॉजिस्टिक'' केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप के लिए भी सहायता प्रदान करेगा।

शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता पर उच्च स्तरीय समिति का होगा गठन

नई दिल्ली। देश को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सरकार ''शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता'' पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्री ने रविवार को बजट पेश करते हुए कहा, मैं ''शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता'' पर एक उच्चस्तरीय स्थाई समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूं, जो विकसित भारत के प्रमुख प्रेरक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेवा क्षेत्र में अग्रणी बनाना है, ताकि वर्ष 2047 तक वैश्विक सेवाओं में हमारी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत हो सके। यह समिति विकास, रोज़गार और निर्यात की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान करेगी। साथ ही, एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के रोजगार और कौशल आवश्यकताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर आवश्यक उपायों का सुझाव देगी।

15,000 स्कूलों, 500 कॉलेजों में स्थापित की जाएंगी 'एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब'

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख पहल 'इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज' के तत्वावधान में 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में 'कंटेंट क्रिएटर लैब' स्थापित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव रखा है।

सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र एक उभरता हुआ उद्योग है, जिसके लिए 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है। वित्त मंत्री ने कहा, मैं 15,000 माध्यमिक स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, मुंबई को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। केंद्रीय बजट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को 4,551.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

एवीजीसी क्षेत्र में प्रतिभा विकास के लिए 250 करोड़ रुपये

इसमें से एक बड़ी राशि भारत के सार्वजनिक प्रसारक 'प्रसार भारती' के साथ-साथ एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभा विकास और सामुदायिक रेडियो के विस्तार को समर्थन देने के लिए निर्धारित की गई है। एवीजीसी क्षेत्र में प्रतिभा विकास के लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसके माध्यम से सरकार देश के युवाओं को कंटेंट क्रिएशन में अग्रणी बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बजट, शिक्षा के प्रति दर्शाता है सरकार की प्राथमिकता को : प्रधान

नई दिल्ली, एजेंसी

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रविवार को पेश केंद्रीय बजट में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में शिक्षा के बजट को बढ़ाया गया है जो सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है।

प्रधान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस बजट में नवजात शिशु से लेकर युवा तक का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि क्वालिटी, स्कूल शिक्षा, स्किलिंग, नर्चरिंग इनोवेशन, इंटरप्रेन्योरशिप और शोध इस बजट के बड़े संकेत है। भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने के लिए बजट में कई कल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल की तुलना में शिक्षा में बजट बढ़ाया गया है। पिछली बार की तुलना में इस बार बजट 8.27 प्रतिशत अधिक है जो सरकार की शिक्षा के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है।

इस बजट में भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने की कल्पना

प्रधान ने कहा कि भारत की लड़कियां विज्ञान, तकनीक और गणित की शिक्षा में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। सरकार ने इसमें और गति देने के लिए हर जिले में लड़कियों के लिए एक छात्रावास बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाए जाएंगे जिसमें शोध,नवाचार और ज्ञान का एक इकोसिस्टम बनेगा। अर्थ नीति को बढ़ाने के लिए उसे ज्ञान से जोड़ना आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई है। देश से बाहर पढ़ने जाने वाले छात्रों को पहले पांच प्रतिशत टैक्स देना पड़ता था उसे दो प्रतिशत किया गया जिससे छात्रों को देश के बाहर शोध करने के लिए जाना आसान होगा। उन्होंने कहा कि बजट में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीआरटी) के बजट में चौदह प्रतिशत की बढोत्तरी की गई है।

2.77 लाख करोड़ में रेलवे करेगा विकास

नई रेल लाइन का निर्माण और लोकोमोटिव, वैगन तथा कोच की खरीद के साथ-साथ होंगे कई अन्य कार्य

नई दिल्ली, एजेंसी

- 2025-26 में 2,52 लाख करोड़ थे आवंटित वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 10.25% ज्यादा
- रेलवे की कमाई 3,85,733.33 करोड़ और खर्च 3,82,186.01 करोड़ होने का अनुमान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 में पूंजी व्यय के लिए रेल मंत्रालय को 2,77,830 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की। बजट आवंटन में नई रेल लाइन का निर्माण और लोकोमोटिव, वैगन तथा कोच की खरीद के साथ अन्य कार्य शामिल हैं। मंत्रालय को वित्त वर्ष 2025-26 में 2,52,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। आने वाले वित्त वर्ष के लिए यह आवंटन 10.25 प्रतिशत ज्यादा है, जो अब तक का सर्वाधिक है। इसके अलावा, मंत्रालय को अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 15,000 करोड़ रुपये मिलेंगे।

बजट दस्तावेज के मुताबिक, रेलवे की कुल कमाई 3,85,733.33 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि खर्च 3,82,186.01 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जिससे वित्त वर्ष के आखिर में 3,547.32 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि क्योंकि रेलवे की कमाई इतनी कम है कि वह परिसंपत्ति बनाने और नए कामों का समर्थन नहीं कर सकती, इसलिए उसे सरकार से धन मिलता है। इसलिए, मंत्रालय को नई लाइन बिछाने, नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने और सिंगल-लाइन वाले मार्गों पर डबल लाइन बनाने जैसे कार्यों के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बजट दस्तावेज में विभिन्न निर्माण कार्यों और संपत्ति निर्माण परियोजनाओं के लिए 2,77,830 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव है। इनमें नई लाइन के लिए 36,721.55 करोड़ रुपये, गेज परिवर्तन के लिए 4,600 करोड़ रुपये, लाइन दोहरीकरण के लिए 37,750 करोड़ रुपये, रोलिंग स्टॉक (लोकोमोटिव, वैगन आदि) के लिए 52,108.73 करोड़ रुपये, और सिग्नलिंग तथा दूरसंचार के लिए 7,500 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस दस्तावेज में 2024-25 में रेलवे की वास्तविक कमाई और खर्च का ब्यौरा भी दिया गया है। साल के दौरान, रेलवे ने 3,35,757.09 करोड़ रुपये कमाए और 3,32,440.64 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे 3,316.45 करोड़ रुपये की आय हुई। उस साल के लिए बजट में 2,51,946.56 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था।

एक अधिकारी ने कहा कि जहां तक वित्त वर्ष 2025-26 की बात है, कमाई और खर्च के असल आंकड़े वित्त वर्ष खत्म होने के बाद ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकतर कमाई और खर्च मामूली बदलावों के साथ उम्मीद के मुताबिक ही हैं। रेलवे के कुल खर्च में से सबसे बड़ा हिस्सा उसके कर्मचारियों को पेंशन देने में जाता है। बजट दस्तावेजों के अनुसार, 2024-25 में पेंशन पर खर्च 58,844.07 करोड़ रुपये था, जिसके 2026-27 में बढ़कर 74,500 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।

सात हाई-स्पीड, एक फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव रखा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को 2026-27 के केंद्रीय बजट में अलग-अलग शहरों के बीच सात हाई-स्पीड कॉरिडोर और पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत के बीच एक नए विशेष फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि पर्यावरण अनुकूल यात्री प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच ग्रोथ कनेक्टर के तौर पर सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे। वित्त मंत्री के मुताबिक, ये प्रस्तावित गलियारे मुंबई और पुणे, पुणे और हैदराबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, चेन्नई और बेंगलुरु, दिल्ली और वाराणसी तथा वाराणसी और सिलीगुड़ी के बीच विकसित किए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि मालवहन के लिए पर्यावरण अनुकूल सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, वह पूर्वी क्षेत्र में डंकुनी को पश्चिमी हिस्से के सूरत से जोड़ने वाला एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रख रही हैं। अभी, अहमदाबाद और मुंबई के बीच एक हाई-स्पीड कॉरिडोर पर काम जारी है। इसी तरह, कई राज्यों और जिलों में दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर - ईस्टर्न और वेस्टर्न का काम जारी है।

राजकोषीय घाटे की भरपाई को 17.2 लाख करोड़ का कर्ज लेगी सरकार

सरकार अगले वित्त वर्ष में 4.3% के अनुमानित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए कुल 17.2 लाख करोड़ रुपये उधार ले सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 में 14.80 लाख करोड़ रुपये के सकल कर्ज का अनुमान लगाया था। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार से कर्ज लेती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए, प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधारी 11.7 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। शेष वित्तपोषण लघु बचत और अन्य स्रोतों से किये जाने की उम्मीद है। सकल बाजार उधारी 17.2 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। कर्ज की राशि अधिक होने के प्रश्न पर, आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा कि शुद्ध बाजार उधारी 11.73 लाख करोड़ रुपये के आसपास है, जो कुछ वर्षों के आंकड़ों के करीब है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी संख्या इसलिए है क्योंकि हमें इस साल 5.5 लाख करोड़ रुपये चुकाने हैं। इसलिए, उस लिहाज से हमें यह कोई बड़ी संख्या नहीं लगती। ठाकुर ने कहा कि प्रतिभूति पुनर्खरीद और अदला-बदली का मुख्य उद्देश्य सरकार पर ऋण चुकाने का बोझ कम करना, एक साथ कई ऋण के जमा होने के प्रभाव को कम करना और लागत को नियंत्रित करना है। उन्होंने कहा कि हमने इस साल उच्च ब्याज वाली प्रतिभूतियों की महत्वपूर्ण अदला-बदली की है। अगले साल इस 5.5 लाख करोड़ रुपये को चुकाना होगा। जैसे-जैसे ये प्रतिभूतियां आती रहेंगी, हम निर्णय लेते रहेंगे। बजट के बाद संवाददाताओं से बातचीत में सीतारमण ने कहा कि केंद्र राज्यों से उनके राजकोषीय प्रबंधन के बारे में बात कर रहा है और उनके ऋणों पर नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र अनुच्छेद 293 (3) के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य है कि राज्यों के कर्ज पर भी नजर रखी जाए। हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन उनके वित्तीय प्रबंधन अधिनियम से ऊपर जाने पर हम उस पर गौर कर सकते हैं।

बजट में राजकोषीय मजबूती, पूंजीगत व्यय बढ़ने से वृद्धि को मिलेगा प्रोत्साहन

नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने बजट 2026-27 में राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रशंसा की। कांत ने एक्स पर कहा कि सीतारमण ने राजकोषीय घाटे को प्रभावशाली ढंग से घटाकर जीडीपी का 4.3 प्रतिशत किया है, जो 2020-21 के 9.2 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से एक बड़ी कमी है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय अनुशासन के वादे को सफलतापूर्वक निभाने के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई! इस उपलब्धि ने न केवल हमारी अर्थव्यवस्था में भरोसे को मजबूत किया है, बल्कि निजी क्षेत्र को कर्ज लेने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण भी तैयार किया है। कांत ने कहा कि इस राजकोषीय मजबूती को पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ जोड़ा गया है, जिससे प्रभावी पूंजीगत व्यय अब जीडीपी का 4.4 प्रतिशत हो गया है।

लड़ाकू दक्षता बढ़ाने के लिए सेना को मिले 7.85 लाख करोड़

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्र सरकार ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7,84,678 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, जो पिछले वर्ष के आवंटन 6.81 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। सरकार का ध्यान खासकर चीन और पाकिस्तान से बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने पर है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के परिप्रेक्ष्य में पूंजीगत खरीद के बजट समेत रक्षा आवंटन में की गई यह वृद्धि हमारी सेना को और अधिक मजबूत बनाने के संकल्प को प्रबल बनाएगी। कुल आवंटन में से 2,19,306 करोड़ रुपये सशस्त्र बलों के पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण खरीदना शामिल है। यह पूंजीगत व्यय 2025-26 के बजट अनुमान की तुलना में 21.84 प्रतिशत अधिक है। पूंजीगत व्यय के तहत, 63,733 करोड़ रुपये विमान और एयरो इंजन के लिए और 25,023 करोड़ रुपये नौसेना बेड़े के लिए आवंटित किए गए हैं। कुल पूंजीगत व्यय चालू वित्त वर्ष के बजटीय अनुमान 1.80 लाख करोड़ रुपये से 39,000 करोड़ रुपये अधिक है। 2025-26 का संशोधित पूंजीगत व्यय 1,86,454 करोड़ रुपये अनुमानित था। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 1.39 लाख करोड़ रुपये (पूंजीगत खरीद बजट का 75 प्रतिशत हिस्सा) वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान घरेलू उद्योगों के माध्यम से खरीद के लिए निर्धारित किए गए हैं।

खरीदे जाएंगे 114 राफेल

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पेश किए गए बजट में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने की रक्षा तैयारियों को आगे बढ़ाने और सेनाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है। बजट में वायु सेना के लिए 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के मद्देनजर पूंजीगत बजट में अच्छी खासी बढोतरी की गयी है जो 2.19 लाख करोड़ रुपये है। सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 1.85 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 24% अधिक है। पेंशन के लिए 1.71 लाख करोड़ दिए गए है जबकि पिछली बार 1.60 लाख करोड़ रुपये था। अनुसंधान और विकास के लिए भी 17250 करोड़ रुपये का प्रावधान है जो पिछली बार 14923 करोड़ रुपये था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आए बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मज़बूत बनाने के सरकार के संकल्प को और सुदृढ़ किया है।

5000 करोड़ में सात सीईआर होंगे स्थापित

सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु, सूरत और वाराणसी सहित सात शहरी आर्थिक क्षेत्र (सीईआर) स्थापित किए हैं। इनके लिए पांच साल में प्रति क्षेत्र 5,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। सीतारमण ने शहरों को भारत के विकास, नवोन्मेष और अवसरों का इंजन बताते हुए कहा कि यह नई पहल मझोली और छोटे शहरों (टियर दो और तीन) के साथ-साथ मंदिर नगरों पर केंद्रित होगी, जिन्हें आधुनिक बुनियादी ढांचे और बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है। सरकार ने बजट में दो नई योजनाओं- शहरी आर्थिक क्षेत्रों और क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों के लिए 2,000 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव रखा है। यह आवंटन सात शहरी आर्थिक क्षेत्रों बेंगलुरु, भुवनेश्वर-पुरी-कटक त्रिपक्षीय क्षेत्र, कोयंबटूर-ईरोड-तिरुप्पुर, पुणे, सूरत, वाराणसी और विशाखापत्तनम के लिए प्रस्तावित किया गया है।

PARAS HEALTH

सेहत का सफर, अब हुआ आसान

पारस हॉस्पिटल की

मुफ़्त बस सेवा

यात्राएँ: प्रति बस प्रतिदिन 2 (सुबह और दोपहर)
संचालन : सोमवार से शनिवार

पहली यात्रा: 10:00 बजे से
दूसरी यात्रा: 12:30 बजे से

दिनांक 3 फरवरी से बस सेवा की शुरुआत की जाएगी

Bus 1: हरजिंदर नगर → रामा देवी → पारस सिटी क्लिनिक (स्वरूप नगर) → हैलट हॉस्पिटल → रावतपुर स्टेशन → पारस हॉस्पिटल

Bus 2: नौबस्ता (केंद्रांचल डिस्पेंसरी) → बर्रा 2 (सचान चौराहा) → फजलगंज → रावतपुर स्टेशन → गुरुदेव → आज़ाद नगर डिस्पेंसरी → पारस हॉस्पिटल

Bus 3: रावतपुर (पाण्डु नगर डिस्पेंसरी) → विजय नगर → भाटिया चौराहा → पनकी मंदिर → अर्मापुर गेट न. 3 → कल्यानपुर → पारस हॉस्पिटल

पारस हॉस्पिटल, बिठूर रोड, कोठारी चौराहा, कानपुर

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0512 352 6969

आयकर में नहीं मिली राहत स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले जैसा

अमृत विचार, बजट डेस्क

केंद्रीय बजट में आमजन की टैक्स से जुड़ी उम्मीदों के मुताबिक, कोई ऐलान नहीं हुआ। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। लोगों को आशा थी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले बजट में सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव किया था। इसके मुताबिक 12 लाख रुपये सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना था। यही सीमा अब 2026-27 में भी लागू रहेगी। इसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी पूर्व की भांति 75 हजार ही रहेगा। ऐसे में मिडिल क्लास के हाथ खाली रह गए।

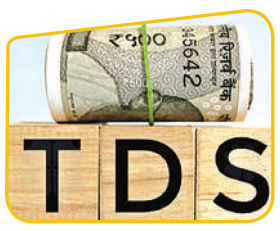

टैक्स में कुछ इन छूट का भी ऐलान

- वित्त मंत्री की बजट घोषणा के अनुसार अब किसी मोटर एक्सीडेंट क्लेम के तहत तय ब्याज को इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी। इस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। लेबर सर्विस को टीडीएस के तहत लाने का प्रस्ताव किया गया है और इन सेवाओं पर 1 से 2 फीसदी की टीडीएस कटौती हो सकती है।

छोटे करदाताओं को राहत

वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया जा रहा है. अब आईटीआर फाइल करने पर कम या जीरो टैक्स कटौती सर्टिफिकेट ले सकेंगे। इसके अलावा, अलग-अलग कंपनियों के शेयर रखने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए डिपोजिट्री, निवेशक के फॉर्म 15जी या फॉर्म 15एच स्वीकार करने और इसे सीधे उन कंपनियों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।

विदेश में घूमना, इलाज और पढ़ाई अब पहले से सस्ती

- सरकार ने विदेश घूमने वालों के लिए बड़ी राहत दी है। विदेशी टूर पैकेज पर लगने वाले टीसीएस जो पहले 5-20 फीसदी लगता था, को घटाकर सिर्फ 2 फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह विदेश में मेडिकल और पढ़ाई पर होने वाले खर्च को लेकर बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने टीसीएस के तहत खर्च पर ब्याज दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया है, यानी आप विदेश में अपना पैसा खर्च करते हैं तो कम ब्याज देना होगा। हालांकि, यह सिर्फ एजुकेशन और मेडिकल खर्च के लिए ही मान्य होगा। इससे विदेश में पढ़ाई और इलाज अब सस्ता हो जाएगा।

आईटीआर के लिए नई डेडलाइन

अब आईटीआर-1 और 2 को भरने के लिए डेडलाइन 31 जुलाई है। नॉन-ऑडिटेड बिजनेस को आईटीआर भरने की डेडाइन 31 अगस्त तय की गई है। वहीं एनआरआई के लिए टैन की जरूरत अब समाप्त कर दी गई है। अब अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती किए जाने पर निवासी खरीदार के पैन पर चालान के जरिए टीडीएस जमा किया जा सकता है।

एक अप्रैल से आयकर अधिनियम 2025

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि आयकर अधिनियम 2025 को एक अप्रैल से लागू किया जाएगा। यह छह दशक पुराने आयकर कानून का स्थान लेगा। आयकर अधिनियम-2025 के नियम तथा 'टैक्स रिटर्न' फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे, ताकि करदाताओं को इसकी आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

63,500- करोड़ रुपये बजट में किसान सम्मान निधि के लिए जारी किए गए हैं। पिछली बार भी इस योजना के लिए इतनी ही धनराशि का आवंटन किया गया था। इस तरह 6000 रुपये सालाना की किसान सम्मान निधि योजना जारी रहेगी।

वित्त मंत्री ने बजट में किया स्मार्ट फार्मिंग एआई टूल 'भारत विस्तार' का ऐलान

खेती में एआई क्रांति से किसान होंगे मालामाल

अमृत विचार, बजट डेस्क

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र के लिए 1,62,671 करोड़ का प्रस्ताव और किसानों की आमदनी में इजाफा करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें कृषि क्षेत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा एआई टूल 'भारत-विस्तार' (वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज) को माना जा रहा है। यह एक बहुभाषीय एआई टूल होगा जो एग्रीस्टैक पोर्टल और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के संसाधनों को एआई प्रणाली से जोड़ेगा। इसका मकसद किसानों को उनकी अपनी भाषा में खास सलाह देना, खेती के जोखिमों को कम करना और पैदावार बढ़ाकर बेहतर फैसला लेने में मदद करना है। इससे किसान आसानी से अपनी आय में इजाफा कर सकेंगे। एग्रीस्टैक भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम है, जिसे भारत सरकार ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य किसानों के लिए एक संपूर्ण डेटाबेस बनाना है जिसमें उनकी पहचान, भूमि रिकॉर्ड, आय, ऋण, फसल की जानकारी और बीमा इतिहास शामिल है। यह खेतों से प्राप्त डेटा और सरकारी एपीआई से मिली जानकारी का उपयोग करता है। एग्रीस्टैक के अंतर्गत विभिन्न डिजिटल उपकरणों और सेवाओं को शामिल किया जाता है। 'भारत विस्तार' का ऐलान सबका साथ विकास कर्तव्य का हिस्सा है। इसके अंतर्गत फसल चयन, मिट्टी स्वास्थ्य, मौसम पूर्वानुमान, बीज-खाद और कीटनाशक की सलाह के अलावा सरकारी योजनाओं की जानकारी, आवेदन तथा ट्रैकिंग जैसी सारी जानकारी एक ही इंटरफेस पर किसान को उसकी अपनी भाषा में मिलेगी। इस तरह यह प्लेटफार्म फसल की उत्पादकता बढ़ाएगा, किसानों के बेहतर निर्णय में मदद करेगा तथा कस्टमाइज्ड एडवाइजरी से जोखिम कम करेगा।

यूनिफाइड सिस्टम और एआई चैटबॉट

भारत विस्तार एआई टूल किसानों के लिए एक बहुभाषी एआई आधारित सिस्टम है, जो मौसम, फसल स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन और बाजार कीमतों की सटीक जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदान करेगा। इसके तहत किसानों को एआई चैट बॉट, यूनिफाइड सिस्टम और टेस्टिंग की जानकारी दी जाएगी। कृषि साथी एआई चैटबॉट के जरिए किसान वॉयस चैटिंग कर सकेंगे और अपनी खेती संबंधित सवाल और समस्याओं के बारे में पूछ सकेंगे।इसमें वे वीडियो के जरिए भी समाधान हासिल कर सकेंगे।

कोकोनट प्रोत्साहन योजना से एक करोड़ किसानों को लाभ

भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक है। एक करोड़ किसानों सहित लगभग तीन करोड़ लोग अपनी रोजी-रोटी के लिए नारियल पर निर्भर हैं। नारियल संवर्धन योजना के माध्यम से नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए पुराने और कम पैदावार देने वाले पेड़ों को नए पौधों और किस्मों से बदलने का काम किया जाएगा।

20 हजार से अधिक पशु चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ेगी

पशुपालन ग्रामीण कृषि आय का करीब 16 प्रतिशत योगदान देता है, जिसमें गरीब और सीमांत किसानों की आमदनी भी शामिल है। इसे देखते हुए वित्त मंत्री ने 20,000 से अधिक पशु-चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऋण-सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी योजना पेश की है। यह योजना पशु चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल, निजी कॉलेज, डायग्नोस्टिक लैब और प्रजनन सुविधाओं की स्थापना को बढ़ावा देगी।

पशुपालन क्षेत्र को मदद मिलने से बढ़ेगी किसान की आमदनी

1,62,671
रुपये कृषि क्षेत्र के लिए कुल आवंटन

7%
अधिक है यह राशि पिछले साल के बजट आवंटन से

पशुपालन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। दुग्ध, पोल्ट्री और पशु व्यवसायों का आधुनिकीकरण होगा तथा वैल्यू चेन में किसान संगठनों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार पशुधन उद्यमों का संवर्धन और आधुनिकीकरण करके डेयरी और मुर्गीपालन के लिए संकेंद्रित मूल्य श्रृंखला का सृजन को संवर्धित करके और पशुधन कृषक उत्पादक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन देगी। बजट में रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना तैयार करने की बात भी कही गयी। इससे रेशम किसानों, भेड़ पालक किसानों और जूट की खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास

- मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास किया जाएगा। इससे अंतर्देशीय मत्स्य पालन मजबूत होगा, तटीय क्षेत्रों में वैल्यू चेन विकसित होगी और स्टार्टअप, महिला समूहों तथा फिश फार्मर प्रोड्यूसर संगठनों के जरिए बाजार से जुड़ाव बढ़ेगा।

कृषि से रोजगार

काजू और कोको 2030 तक बनेगा प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड

- भारत को कच्चे काजू और कोको की पैदावार व प्रसंस्करण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा निर्यात बेहतर करने के उपायों पर जोर देते हुए बजट में भारतीय काजू और भारतीय कोको को वर्ष 2030 तक प्रीमियम वैश्विक ब्रांड में मशहूर करने के लिए एक खास कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।

अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की

- बजट में केसीसी के तहत सब्सिडी वाले अल्पकालिक ऋण की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इससे करोड़ों किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को आसानी से सस्ता ऋण मिलने का रास्ता साफ होने से खेती-किसानी में निवेश बढ़ेगा।

सस्ती खाद को 1.71 करोड़ बनेंगे सब्जी उत्पादन क्लस्टर

- किसानों को सस्ती दरों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए 1.71 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रमुख खपत केंद्रों के पास सब्जियों के बड़े उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे ताकि आपूर्ति श्रृंखला बेहतर हो सके।

उच्च मूल्य वाली फसलों पर जोर

- सरकार ने पारंपरिक फसलों के बजाय उच्च मूल्य वाली फसलों पर जोर दिया है। इसमें नारियल प्रोत्साहन योजना, तटीय क्षेत्रों में काजू, कोको और चंदन की खेती को बढ़ावा। पहाड़ी क्षेत्रों में अखरोट, बादाम और पाइन नट्स के बागानों का आधुनिकीकरण। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों की खेती को प्रोत्साहन शामिल है।

किसानों का कल्याण केंद्र की सर्वोच्च प्राथमिकता

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान कल्याण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय बजट 2026-27 में किसान को केंद्र में रखकर ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जो किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। कोकोनट प्रोत्साहन योजना से उत्पादन बढ़ेगा और 1 करोड़ किसानों सहित लगभग 3 करोड़ लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्य सरकारों के साथ मिलकर इंडियन सैंडलवुड इकोसिस्टम के गौरव को पुनर्स्थापित किया जाएगा। कृषि संसाधनों तक किसानों की आसान पहुँच के लिए 'भारत विस्तार' नाम से एक बहुभाषी एआई आधारित प्रणाली विकसित की जाएगी।

उद्योग जगत

इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के निर्माण को 40 हजार करोड़ तो कंटेनर के वैश्विक इकोसिस्टम के लिए 10 हजार करोड़ रुपये

मैन्यूफैक्चरिंग और एमएसएमई बनेंगे विकसित भारत की राह में गेम चेंजर

नई दिल्ली, बजट डेस्क

केंद्रीय बजट 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत में मैन्यूफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ाकर 'विकसित भारत' के लक्ष्य को मजबूत करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। सरकार ने 7 रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में मैन्यूफैक्चरिंग को गति देने का प्रस्ताव किया है। इसमें बायोफार्मा में अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 'बायोफार्मा शक्ति' योजना शुरू की गई है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों के निर्माण की योजना का बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत उपकरणों और आईपी डिजाइन पर विशेष जोर दिया गया है। 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे और तकनीक के जरिए पुनर्जीवित किया जाएगा।ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर (रेयर अर्थ कॉरिडोर) और 3 समर्पित केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) से घरेलू बाजार में बिक्री के लिए रियायती शुल्क की सुविधा। कंटेनर विनिर्माण का अगले 5 वर्षों में वैश्विक इकोसिस्टम बनाने के लिए 10,000 करोड़ का आवंटन हुआ है। टेक्सटाइल क्षेत्र में प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर के लिए नेशनल फाइबर मिशन और में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी सीमा को 10 से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दिया गया है।

'कॉरपोरेट मित्रों' का दस्ता एमएसएमई की करेगा मदद: सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की सहायता के लिए मझोले (श्रेणी-दो) और छोटे (श्रेणी-तीन) शहरों में 'कॉरपोरेट मित्रों' का एक दस्ता तैयार करेगी। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपायों की सिफारिश करने के लिए 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' स्थायी समिति का गठन करेगी। 'कॉरपोरेट मित्रों' का यह दस्ता एमएसएमई को किफायती लागत पर अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। सरकार इस दस्ते को तैयार करने के लिए आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई जैसे संस्थानों को मॉड्यूल पाठ्यक्रम और व्यावहारिक टूल डिजाइन करने में सहयोग देगा।

एमएसएमई को 'चैंपियन' बनाने के लिए 10,000 करोड़ का कोष

200
पुराने औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे आधुनिक

10
हजार करोड़ की 'बायोफार्मा शक्ति' योजना

नयी दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को 'चैंपियन' बनाने के लिए तीन-आयामी रणनीति अपना रही है जिसमें 10,000 करोड़ रुपये का एक समर्पित कोष भी शामिल है। एमएसएमई को सशक्त बनाने के लिए वित्त मंत्री ने इक्विटी समर्थन, नगदी समर्थन और पेशेवर समर्थन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इक्विटी समर्थन के तहत 10,000 करोड़ रुपये के एसएमई विकास कोष के माध्यम से चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

- उन्होंने कहा कि एमएसएमई को तरलता समर्थन के लिए ट्रेड्स मंच की पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा सभी एमएसएमई खरीदारी का लेनदेन ट्रेड्स मंच पर करना, सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी प्रदान करना और जीईएम को कारोबार के साथ जोड़कर वित्तपोषण को तेज और सस्ता बनाना शामिल है। इसके साथ ही सीतारमण ने 2021 में गठित 'आत्मनिर्भर भारत कोष' में 2,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि डालने की घोषणा की ताकि सूक्ष्म उद्यमों को जोखिम पूंजी उपलब्ध रहे।

"भविष्य के लिए तैयार भारत" का बजट

- **नयी दिल्ली।** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय बजट को "भविष्य के लिए तैयार भारत" का बजट बताया है। उनके मुताबिक इस बजट का मकसद निर्यात और घरेलू विनिर्माण को मजबूती देना है। बजट में मैन्युफैक्चरिंग, सेवाएं, महिलाएं, शिक्षा, कौशल विकास, मछुआरे, पशुपालन और नई तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों को शामिल किया गया है। गोयल ने कहा कि अब तक करीब 350 सुधार किए जा चुके हैं और लगातार नई पहलों के जरिए सुधार की रफ्तार तेज हो रही है। बजट में डेटा सेंटर्स को अभूतपूर्व लाभ देने और 2047 तक टैक्स छूट का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिससे भारत को एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का वैश्विक हब बनाने की दिशा में सरकार की मंशा साफ झलकती है।

उद्योग जगत ने बताया दूरदर्शी और भरोसा बढ़ाने वाला बजट

- **नयी दिल्ली।** केंद्रीय बजट को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने दूरदर्शी और भरोसा बढ़ाने वाला बताया है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी के अनुसार, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह बजट भारत की विकास यात्रा को स्थिर और मजबूत दिशा देता है। बजट में सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, रसायन, पूंजीगत वस्तुएं, वस्त्र, खेल सामग्री, महत्वपूर्ण खनिज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

बजट कर अवकाश

नयी दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को उन विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक 'कर अवकाश' का प्रस्ताव रखा, जो देश में स्थित डेटा सेंटर का उपयोग करके दुनिया भर के ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं। यह कर अवकाश संबंधित संस्थाओं को कुछ शर्तों के अधीन दिया जाएगा। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और डेटा सेंटर में निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मंत्री ने कहा, ''मैं किसी भी ऐसी विदेशी कंपनी को 2047 तक कर अवकाश देने का प्रस्ताव करती हूं, जो भारत से डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके विश्वस्तर पर ग्राहकों को क्लाउड सेवाएं प्रदान करती है।'' इस कर अवकाश का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को एक भारतीय पुनर्विक्रेता इकाई के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवाएं देनी होंगी।

भारत के डेटा सेंटर का उपयोग करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर अवकाश का प्रस्ताव

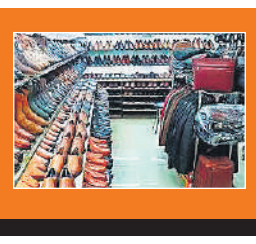

यूपी के विकास को मिलेगी रफ्तार, मिलेंगे 4 लाख करोड़ रुपये

● इन्फ्रास्ट्रक्चर, हाई-स्पीड रेल, पर्यटन व सिटी इकोनॉमिक रीजन से टियर-2 व टियर-3 शहरों को मिलेगी मजबूती ● टेक्सटाइल व एआई आधारित कृषि पर फोकस

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

बजट -2026

● भाजपा जहां बजट को ऐतिहासिक बता रही, वहीं विपक्ष और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है

अमृत विचार: आम बजट से प्रदेश को 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सौगात मिलने की उम्मीद है, जिससे विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और रोजगारोन्मुखी योजनाओं पर फोकस से सरकार उत्साहित है। हाई-स्पीड रेल, जल परिवहन और सिटी इकोनॉमिक रीजन से तस्वीर बदलने की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को जमकर सराहा है। भाजपा जहां इसे ऐतिहासिक बता रही है, वहीं विपक्ष और विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। आम आदमी और नौकरीपेशा वर्ग को प्रत्यक्ष राहत कम नजर आई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय करों से उत्तर प्रदेश के हिस्से में 2.69 लाख करोड़ रुपये आएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में राज्य को कुल 2.55 लाख करोड़ रुपये मिलने हैं। पूंजीगत निवेश (विकास कार्यों) के लिए राज्यों को ब्याजमुक्त ऋण योजना से 22 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद में करीब 18 हजार करोड़ रुपये का प्रविधान है। इसी प्रकार केंद्र सहायतित योजनाओं के मद में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक, केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर करीब 10 से 12 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग ने केंद्रीय योजनाओं से भी 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मिलने का अनुमान लगाया है। इन मदों से वर्ष 2026-27 में राज्य को करीब 4.18 करोड़ रुपये मिलेंगे। चालू वित्तीय वर्ष में इन मदों से राज्य को 3.92 करोड़ रुपये मिलने हैं। अब केंद्र से मिलने वाले इस धनराशि के आधार पर राज्य सरकार अपना बजट तैयार करेगी।

बजट में किसान, महिला, युवा, कारीगर व छोटे उद्यमियों को केंद्र में रखते हुए समावेशी विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। विशेष रूप से पूर्वांचल, काशी क्षेत्र, बुंदेलखंड और टियर-2 व टियर-3 शहरों के लिए ये योजनाएं क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार, निवेश व आर्थिक गतिविधियों को गति देने में अहम भूमिका निभाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाराणसी-सिलीगुड़ी और दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया, जिससे यूपी को कुल 1500 किमी हाई-स्पीड रेल मिली। इसके अतिरिक्त, सभी 75 जिलों में गर्ल्स हॉस्टल, कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ का विशेष बजट, नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क और तीर्थ स्थलों के विकास की घोषणा की गई। ये परियोजनाएं राज्य में कनेक्टिविटी, शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देंगी। केंद्र सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और शैक्षिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा की है। इससे दूर-दराज़ इलाकों से उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक रहने की व्यवस्था मिलेगी।

बजट में यूपी को मिले प्रमुख तोहफे

- वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम
- बुंदेलखंड में होगा आईआईटी का निर्माण, पश्चिमी यूपी में खुलेगा एम्स
- सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना से टियर-2 व टियर-3 शहरों का कायाकल्प
- 12.2 लाख करोड़ के कैपेक्स से सड़क, रेल व लॉजिस्टिक्स को मजबूती
- खेल, एमएसएमई, खादी, हथकरघा व टेक्सटाइल सेक्टर को विशेष प्रोत्साहन की घोषणा
- एआई आधारित 'भारत-विस्तार' से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक
- 'शी-मार्ट' से ग्रामीण महिलाओं को नया बाजार और उद्यमिता का अवसर
- सोलर, बैटरी व ई-मोबिलिटी को बढ़ावा, पीएम सूर्य घर योजना को गति
- हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल और जिला अस्पतालों की सुविधाओं का विस्तार
- 10,000 करोड़ का कंटेनर निर्माण विशेष बजट
- नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क, तीर्थ स्थलों का समग्र विकास

इस धनराशि से तय होगा यूपी के आम बजट का आकार

- केंद्रीय करों से हिस्सा (2026-27) : 2.69 लाख करोड़ (2025-26 में 2.55 लाख करोड़)
- पूंजीगत निवेश के लिए ब्याजमुक्त ऋण : 22,000 करोड़ (चालू वर्ष में 18,000 करोड़)
- केंद्र सहायतित योजनाएं : 1 लाख करोड़ से अधिक
- वित्त आयोग की सिफारिशों से : 10,000-12,000 करोड़
- केंद्रीय योजनाओं से अनुमानित राशि : 15,000 करोड़ से अधिक
- कुल अनुमानित केंद्रीय सहायता (2026-27) : लगभग 4.18 लाख करोड़
- (2025-26 में लगभग 3.92 लाख करोड़)

आपात-स्थिति में सस्ता और प्रभावी इलाज

गरीबों व निम्न आयवर्ग के लोगों को आपात-स्थिति में सस्ता व प्रभावी इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट में सभी जिला अस्पतालों की इमरजेंसी सुविधाएं बढ़ाने तथा ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे समय पर उपचार मिलने से जान बचाने की संभावनाएं बढ़ेंगी और जिला अस्पतालों की क्षमता में भी वृद्धि होगी। इन दोनों पहलों से यूपी में न केवल स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सहायक कर्मियों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

कनेक्टिविटी से लेकर रोजगार तक बदलेगा यूपी का परिदृश्य

अमृत विचार, लखनऊ : केंद्रीय बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश के लिए विकास का व्यापक खाका लेकर आया है। हाई-स्पीड रेल, जल परिवहन, सिटी इकोनॉमिक रीजन और 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर से प्रदेश की कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती मिलेगी। साथ ही किसान, महिला, युवा, एमएसएमई, पर्यटन और टेक्सटाइल सेक्टर पर विशेष ध्यान देकर रोजगार और निवेश के नए अवसर सृजित करने की दिशा तय की गई है।

हाई-स्पीड रेल से बदलेगी कनेक्टिविटी की तस्वीर

केंद्रीय बजट में घोषित 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर में से 2 महत्वपूर्ण कॉरिडोर सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, जिनमें दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राजधानी दिल्ली से काशी, पूर्वांचल और आगे पूर्वी भारत तक की रेलयात्रा तेज, सुरक्षित, सुविधाजनक तरीके से संपन्न होगी। आधुनिक तकनीक से लैस रेल नेटवर्क प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। हाई-स्पीड रेल से लंबी दूरी की यात्रा का समय काफी कम होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश व पर्यटन को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। काशी, पूर्वांचल व सीमावर्ती जिलों में उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

वाराणसी को मिलेगा जल परिवहन में नया आयाम

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जल परिवहन को सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय बजट में वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज शिप रिपेयर इकोसिस्टम स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। यह पहल गंगा नदी पर विकसित हो रहे जलमार्ग आधारित परिवहन तंत्र को तकनीकी व व्यावसायिक रूप से मजबूत बनाएगी। शिप रिपेयर इकोसिस्टम के स्थापित होने से मालवाहक जहाजों और जलपोतों के रखरखाव व मरम्मत की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी, जिससे समय और लागत दोनों में कमी आएगी। इससे लॉजिस्टिक्स सेक्टर को बढ़ावा मिलने के साथ जल परिवहन, एक किफायती और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में प्रभावी होगा।

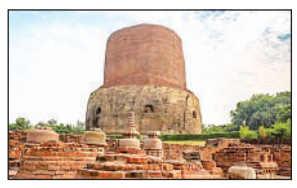

पर्यटन व धार्मिक स्थलों को नई पहचान, संरक्षण को विशेष महत्व

केंद्रीय बजट में पर्यटन व सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। इसी क्रम में भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ तथा हस्तिनापुर को देश के 15 प्रमुख पुरातात्विक पर्यटन स्थलों के विकास कार्यक्रम में शामिल किया जाना उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे न केवल यूपी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर नई मजबूती मिलेगी, बल्कि पर्यटकों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना है। इससे धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से होटल, होम-स्टे, ट्रांसपोर्ट, हस्तशिल्प, स्थानीय बाजार और अन्य सहयोगी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

सिटी इकोनॉमिक रीजन से शहरों का होगा समग्र विकास

केंद्रीय बजट 2026-27 में टियर-2 और टियर-3 शहरों को विकास की मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से सिटी इकोनॉमिक रीजन (सीईआर) योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत बड़े महानगरों पर निर्भरता कम करते हुए पांच लाख से ज्यादा आबादी वाले अन्य शहरों में बुनियादी ढांचे व आर्थिक गतिविधियों को सुदृढ़ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी जैसे प्रमुख शहरों को इस योजना का सीधा लाभ मिल सकता है। आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए लगभग 5000 करोड़ तक का चरणबद्ध निवेश प्रस्तावित है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश की घोषणा मिलेगा सीधा लाभ

केंद्रीय बजट में देशभर में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के लिए 12.2 लाख करोड़ के रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर (कैपेक्स) की घोषणा की गई है, जिसका सीधा व अप्रत्यक्ष लाभ उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। केंद्र सरकार के इस कैपेक्स का उद्देश्य आर्थिक विकास को रफ्तार देना, रोजगार सृजन करना और भारत को वैश्विक निवेश का आकर्षक केंद्र बनाना है। उत्तर प्रदेश में इस निवेश से सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क और लॉजिस्टिक हब के विस्तार को नई गति मिलेगी। राज्य का पहले से मजबूत होता एक्सप्रेसवे नेटवर्क (पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा और लिंक एक्सप्रेसवे) औद्योगिक कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करेगा।

सोलर, बैटरी और ई-मोबिलिटी क्षेत्र में रियायत बनेगी गेम चेंजर

अमृत विचार, लखनऊ : केंद्रीय बजट 2026 में सोलर ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और ई-मोबिलिटी से जुड़े कस्टम ड्यूटी व आयात शुल्क में दी गई रियायतों को उत्तर प्रदेश के लिए गेम-चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। इन फैसलों को प्रधानमंत्री सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना और राज्य में तेजी से उभरते ई-मोबिलिटी इकोसिस्टम से जोड़कर आंका जा रहा है। नीति विशेषज्ञों का मानना है कि बजट के ये प्रावधान रूफटॉप सोलर विस्तार, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा संतुलन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी- इन चारों क्षेत्रों को एक साझा दिशा में आगे बढ़ाएंगे। बजट 2026 में लिथियम-आयन बैटरी निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल- कोबाल्ट पाउडर, बैटरी स्क्रैप और अन्य क्रिटिकल मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। सोलर सेक्टर के लिए बजट में एक अहम प्रावधान करते हुए सोलर ग्लास निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल सोडियम एंटीमोनेट को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। उद्योग जगत का मानना है कि इन रियायतों से डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट (डीसीआर) आधारित सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। इनपुट्स सस्ते होने से घरेलू उत्पादन की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और आयात पर निर्भरता घटेगी। इसका असर उत्तर प्रदेश में सोलर वैल्यू चेन के विस्तार के रूप में सामने आ सकता है। बजट प्रावधानों के बाद नोएडा, लखनऊ, कानपुर और पूर्वांचल के औद्योगिक क्षेत्रों में नई सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के साथ-साथ ईवी कंपोनेंट्स, बैटरी पैक असेंबली और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े निवेश बढ़ने की संभावना है।

एमएसएमई, खादी और वस्त्र क्षेत्र को मिलेगी गति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

- लाखों उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों के लिए नए अवसर
- एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम, ग्रोथ फंड और ग्रामीण उद्योगों पर फोकस

अमृत विचार: केंद्रीय बजट 2026-27 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्रोद्योग को सशक्त बनाने के लिए कई अहम और दूरगामी प्रावधान किए गए हैं। वस्त्र क्षेत्र के लिए एक व्यापक, एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय फाइबर योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना, राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम, टेक्स-इको पहल और समर्थ 2.0 जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजन और निर्यात को गति देना है। मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना से उत्तर प्रदेश में निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।

इन प्रावधानों से प्रदेश के एमएसएमई, खादी, हथकरघा, रेशम और वस्त्रोद्योग से जुड़े लाखों उद्यमियों, कारीगरों और श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। रोजगार बढ़ेगा और 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी। एमएसएमई क्षेत्र को मजबूती देने के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत फंड में 2,000 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी डाली जाएगी। छोटे उद्यमों की कार्यशील पूंजी की समस्या कम करने के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम के दायरे का विस्तार किया जाएगा।

कॉरपोरेट मित्र और विरासत औद्योगिक क्लस्टर का प्रस्ताव

'कॉरपोरेट मित्र' व्यवस्था के जरिए एमएसएमई को व्यावसायिक मार्गदर्शन, तकनीकी सहयोग और बाजार से जोड़ने की पहल की गई है। इसके साथ ही देशभर में 200 विरासत इंडस्ट्रियल क्लस्टरों के कायाकल्प का प्रस्ताव है, जिनमें हथकरघा और हस्तशिल्प क्लस्टर भी शामिल होंगे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूते के ऊपरी हिस्सों के शुल्क-मुक्त आयात का विस्तार और चमड़ा व वस्त्र परिधान निर्यात की समय-सीमा बढ़ाने जैसे कदम उठाए गए हैं। इनसे वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उद्योगों को नई पहचान मिलेगी।

किसानों, महिलाओं व युवाओं पर विशेष ध्यान

केंद्रीय बजट में समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भारत-विस्तार योजना के माध्यम से किसानों को आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इससे राज्य के अन्नदाता किसानों को मौसम, मिट्टी, फसल चक्र और बाजार की मांग के अनुरूप सटीक कृषि सलाह उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे फसल जोखिम कम होगा और राज्य के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि संभव होगी। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा, जो परंपरागत खेती पर निर्भर हैं। बजट में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शी-मार्ट्स की शुरुआत की गई है। कृषि-तकनीक, डिजिटल मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स और उद्यमिता से जुड़े नए अवसर सृजित होंगे।

स्वास्थ्य व शिक्षा में सशक्त कदम

केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ठोस और व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की स्थापना का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण व दूर-दराज के इलाकों से आने वाली छात्राओं को दिक्कत का सामना न करना पड़े। इससे उच्च शिक्षा, मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुलभ आवास सुविधा मिल सकेगी। बजट में प्रस्तावित स्टेम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथ्स) संस्थानों से प्रदेश में पहले से जारी स्किल डेवलपमेंट अभियान को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है बजट

अमृत विचार, लखनऊ : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए कहा कि यह बजट भारतीय आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, जिन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प इसमें स्पष्ट रूप से झलकता है। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वसमावेशी दृष्टि, दूरदर्शी सोच और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सशक्त घोषणापत्र है। राज्यपाल ने कहा कि करीब 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, राजकोषीय अनुशासन, नियंत्रित घाटा और संतुलित कर्ज-जीडीपी अनुपात इस बात का प्रमाण है कि भारत की विकास यात्रा सुदृढ़ नींव पर आगे बढ़ रही है।

बजट पर विभिन्न दलों के नेताओं का कहना...

ऐतिहासिक बजट : केशव प्रसाद मौर्य

अमृत विचार : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है। देश की नारी शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। अपार अवसरों का राजमार्ग है। 2047 के विकसित भारत की ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है।

बजट में यूपी का रखा ध्यान : पाठक

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि आम बजट में उत्तर प्रदेश का पूरा ध्यान रखा गया है। स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर सहित हर क्षेत्र को बजट में समाहित किया गया है

विकसित भारत को लेकर जनोन्मुखी बजट: पंकज

अमृत विचार : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला जनोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट आर्थिक मजबूती, सामाजिक संतुलन और दीर्घकालिक विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है। हाई-स्पीड रेल, आयुष, सेमीकंडक्टर, बायोफार्मा, कृषि और एमएसएमई पर जोर से रोजगार, निवेश और कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।

समझ से बाहर है बजट : अखिलेश

अमृत विचार : सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बजट-2026 में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है और यह पूरी तरह समझ से बाहर है। अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो पीतल को लोहे पर चढ़ाकर गहने बनाने पड़ेंगे, यह बजट उसी सोच को दिखाता है। आरोप लगाया कि बजट कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है।

विश्लेषण बजट तात्कालिक वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरा उतरने के लिए रचा गया वक्तव्य : प्रो. अजय द्विवेदी

बजट संख्या नहीं संकेत : देश की आर्थिक चेतना का निर्णायक क्षण

प्रो. अजय द्विवेदी
पूर्व डीन, प्रबंधन संकाय
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

अमृत विचार: भारत का आम बजट तब तक अधूरा रहता है, जब तक उसे केवल आय-व्यय के गणित की तरह पढ़ा जाता है। उसका वास्तविक अर्थ तब खुलता है, जब उसे समाज की मनःस्थिति, राष्ट्र की दिशा और सत्ता की मानसिकता के साथ जोड़कर देखा जाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट एक ऐसे दस्तावेज़ के रूप में सामने आता है, जो शोर नहीं करता, संकेत देता है। यह बजट उत्सव का नहीं, निर्णय का बजट है। तात्कालिक वाहवाही के लिए नहीं, बल्कि समय की कसौटी पर खरे उतरने के लिए रचा गया वक्तव्य।

हर बजट अपने साथ अपेक्षाओं की एक लंबी कतार लेकर आता है। मध्यम वर्ग कर राहत की प्रतीक्षा करता है। किसान स्थिर आय और सुरक्षा की उम्मीद करता है। युवा रोजगार के ठोस संकेत खोजते हैं। उद्योग नीति स्थिरता और निवेश अनुकूल वातावरण चाहता है। सामाजिक क्षेत्र अधिक संसाधनों की आकांक्षा रखता है। ऐसे में प्रश्न यह नहीं कि क्या यह बजट सबको खुश करता है, बल्कि यह है कि यह बजट किस दिशा में देश को ले जाना चाहता है। मध्यम वर्ग के लिए यह बजट भावनात्मक संतोष का साधन नहीं बनता। प्रत्यक्ष करों में बड़े और आकर्षक बदलावों का अभाव पहली दृष्टि में निराशा पैदा कर सकता है। पर इसके भीतर छिपा संदेश अधिक गहरा है। सरकार यह संकेत देती है कि अस्थिर अर्थव्यवस्था में दी गई त्वरित राहत अंततः उसी वर्ग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। महंगाई नियंत्रण, निवेश निरंतरता और वित्तीय अनुशासन को प्राथमिकता देना यह दर्शाता है कि मध्यम वर्ग को उपभोक्ता नहीं, बल्कि आर्थिक भागीदार के रूप में देखा जा रहा है। यह दृष्टि लोकप्रिय नहीं, पर जिम्मेदार है। कृषि और ग्रामीण भारत के संदर्भ में यह बजट करुणा से अधिक रणनीति की भाषा बोलता है। किसान को सहायता का पात्र नहीं, बल्कि आर्थिक संरचना का आधार मानने की सोच इस बजट को लोकलुभावन परंपरा से अलग करती है। ग्रामीण रोजगार, कृषि अवसंरचना और मूल्य संवर्धन पर निरंतर जोर यह स्पष्ट करता है कि सरकार जानती है कि गांव कमजोर हुआ तो शहर की प्रगति टिकाऊ नहीं रह सकती। यहां राहत बांटने से अधिक जड़ों को मजबूत करने का प्रयास दिखाई देता है। युवा वर्ग के लिए यह बजट सबसे अधिक बहस को जन्म देता है। सीधे रोजगार के बड़े वादे नहीं हैं, कोई ऐसा आंकड़ा नहीं जिसे पोस्टर पर उकेरा जा सके। पर कौशल, तकनीक, स्टार्टअप और अवसंरचना के माध्यम से अवसर निर्माण की जो संरचना प्रस्तुत की गई है, वह यह संकेत देती है कि सरकार नौकरी देने की नहीं, रोजगार अर्थव्यवस्था बनाने की सोच पर आगे बढ़ रही है। यह दृष्टि धैर्य मांगती है, पर दीर्घकाल में आत्मनिर्भरता की ठोस जमीन तैयार करती है।

उद्योग और व्यापार जगत के लिए यह बजट राहत की सांस जैसा है। करों में अप्रत्याशित झटकों का अभाव, नीति की निरंतरता और अवसंरचना निवेश का स्पष्ट संकेत यह दर्शाता है कि सरकार उद्योग को संदेह की दृष्टि से नहीं, साझेदार के रूप में देखती है। यह बजट उद्योग से यह नहीं कहता कि सरकार सब कुछ करेगी, बल्कि यह भरोसा देता है कि रास्ता स्थिर और स्पष्ट रहेगा, चलना उद्योग को स्वयं होगा। सामाजिक क्षेत्र में यह बजट भावनात्मक घोषणाओं से सावधानीपूर्वक दूरी बनाए रखता है। शिक्षा और स्वास्थ्य को नारों के रूप में नहीं, बल्कि मानव पूंजी में निवेश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यही वह सूक्ष्म अंतर है जो इस बजट को गंभीर बनाता है। यह स्वीकार किया गया है कि मानव संसाधन पर किया गया निवेश तत्काल राजनीतिक लाभ नहीं देता, पर दीर्घकालिक राष्ट्र निर्माण का यही आधार होता है। इस पूरे बजट की रीढ़ उसका वित्तीय अनुशासन है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने का संकल्प यह स्पष्ट करता है कि सरकार विकास की कीमत पर लापरवाही नहीं करना चाहती। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में यह संयम भारत को एक जिम्मेदार और परिपक्व अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। अवसंरचना पर निरंतर निवेश के साथ यह अनुशासन यह दर्शाता है कि सरकार विकास को गति देना चाहती है, पर संतुलन खोकर नहीं।

मायावती ने बजट पर उठाए सवाल

अमृत विचार : केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि बजट में कई योजनाओं, परियोजनाओं और आश्वासनों का जिक्र है, लेकिन इनके वास्तविक असर का आकलन जमीन पर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं, इन पर सही नीयत से अमल होना जरूरी है। सलाह देते हुए कहा कि बजट गरीब और बहुजन हितैषी होना चाहिए, न कि केवल पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों का पक्ष लेने वाला।

बजट जवाब देने से भागने वाला : संजय

अमृत विचार : केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह बजट सवालों से भागने वाला बजट है और सरकार को अब देश की जनता को जवाब देना ही होगा। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने पहली बार शपथ ली थी, तब उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि बजट में बेरोज़गारी पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया।

आत्मनिर्भरता के संकल्प को ऊर्जा देगा बजट: अनिल

अमृत विचार : बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे ने कहा कि यह विकसित भारत का बजट है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। यह बजट विशेष कर अन्नदाताओं, नौजवानों, महिलाओं और शोषित वंचित उत्थान के लिए समर्पित है और किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण बुनियाद को मजबूत करने का काम करेगा।

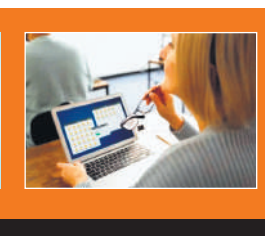

बजट प्रतिक्रिया

वृद्धि, समावेशन का संयोजन वाला साहसिक बजट: सुनील मित्तल

नई दिल्ली, एजेंसी। भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक और चेयरमैन सुनील मित्तल ने रविवार को कहा कि केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने, ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने और डेटा सेंटर परिवेश को प्रोत्साहन देने से भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास मजबूत होगा। मित्तल ने इसे विकास और समावेश को संयोजित करने वाला एक साहसिक बजट बताया और कहा कि कौशल विकास पर जोर के साथ विज्ञान, नवाचार और अनुसंधान में लगातार निवेश समय पर किया गया कदम है, जो घरेलू क्षमताओं को मजबूत करेगा और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात की जगह घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगा। मित्तल ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के उपाय, ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित करना और डेटा सेंटर परिवेश को प्रोत्साहन देना, भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास को और मजबूत करेगा।

यह बजट झुनझुना है दिखता है पर बजता नहीं : प्रमोद तिवारी

लखनऊ, एजेंसी। राज्यसभा में उप नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद प्रमोद तिवारी तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ''मोना'' ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह "झुनझुने" की तरह है, जो दिखता तो है लेकिन बजता नहीं। उन्होंने इसे किसान, बेरोजगार युवाओं और लघु एवं मध्यम उद्योगों के खिलाफ बताते हुए कहा कि बजट से देश की जनता निराश हुई है। उनका दावा है कि बजट के बाद बाजार में गिरावट इसका संकेत है। नेता ने कहा कि पिछले एक वर्ष से पूंजी निवेश ठहरा हुआ है और न तो विदेशी निवेश आ रहा है और न ही स्वदेशी निवेश में वृद्धि हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चालू वर्ष में राजस्व प्राप्तियों में 78,086 करोड़ रुपये और शुद्ध कर संग्रह में 1,62,748 करोड़ रुपये की कमी आर्थिक सुस्ती का संकेत है। उनके अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, कृषि, ग्रामीण विकास, नगर विकास, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित कई योजनाओं में बजटीय कटौती की गई है, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए कोई ठोस नई योजना या अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है और यह बजट केवल नारों तक सीमित है।

खेल विकास से सधेगी युवा शक्ति

युवा और खेल मंत्रालय के लिए बजट में 1,133 करोड़ की वृद्धि, खेलो इंडिया मिशन की शुरूआत

नई दिल्ली, एंजेंसी

यूनियन बजट 2026-27 भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है, जिसमें टैलेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार पैदा करने पर फोकस किया गया है।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने खेलो इंडिया मिशन शुरू करने की घोषणा की, जिसका मकसद अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलना है। युवा मामले और खेल मंत्रालय के लिए कुल बजट आवंटन में 1,133 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। डेवलपमेंट सेक्टर के तौर पर स्पोर्ट्स की बढ़ती अहमियत पर जोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, स्पोर्ट्स सेक्टर रोज़गार, स्किलिंग और नौकरी के कई मौके देता है।

खेलो इंडिया प्रोग्राम के जरिए स्पोर्ट्स टैलेंट को सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ाने की शुरुआत करते हुए, मैं अगले दशक में स्पोर्ट्स सेक्टर को बदलने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। यूनियन बजट में, स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं। खेलो इंडिया मिशन पूरे देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बड़ा तरीका अपनाएगा। इस मिशन का मकसद एथलीट के लिए सही रास्ते बनाना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को मजबूत करना और सभी लेवल पर परफॉर्मेंस के नतीजों को बेहतर बनाना है। बजट में युवाओं पर केंद्रित नेचर पर जोर देते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रस्ताव युवाओं को जोड़ने की कोशिशों से निकले आइडिया और उम्मीदों को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में, हमारे प्रधानमंत्री के साथ कई नए आइडिया शेयर किए गए, जिनसे कई प्रस्तावों को प्रेरणा मिली, जिससे यह एक अनोखा युवा शक्ति पर आधारित बजट बन गया। ग्लोबल स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में भारत की क्षमता को पहचानते हुए, बजट में स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक खास पहल का भी प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहाः केंद्रीय बजट 2026-27, युवा मामले और खेल मंत्रालय को कुल बजट आवंटन में 1,133 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देता है, ताकि 2036 तक भारत को टॉप 10 खेल देशों में और 2047 तक टॉप 5 में जगह दिलाने का विज़न पूरा हो सके। मंत्रालय के लिए आवंटन 2025-26 में 3,346 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 4,479.88 करोड़ रुपये हो गया है।

वर्ष 2025-26 3,346 करोड़

वर्ष 2026-27 4,479.88 करोड़

- 2036 तक भारत को टॉप 10 खेल देशों में और 2047 तक टॉप 5 में जगह दिलाने का विज़न
- स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये

बढ़ा हुआ आवंटन केंद्र द्वारा चलाए जा रहे खेल और युवा विकास योजनाओं को लागू करने को मजबूत करेगा, जिसमें एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम, युवा जुड़ाव की पहल, कोचिंग और सपोर्ट सिस्टम, स्पोर्ट्स साइंस इंटीग्रेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शामिल हैं।

बैंकों के लिए उच्चस्तरीय समिति की हुई घोषणा

नई दिल्ली, एजेंसी

- बजट में इस प्रस्ताव से होगा बही खाता सुधार, बैंकों की गांवों की ओर पहुंच और तेजी से बढ़ेगी
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियमों की हो सकेगी व्यापक समीक्षा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ''विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की। यह समिति बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करेगी और इसे भारत की वृद्धि के अगले चरण के लिए तैयार करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र आज मजबूत बही-खाते, लाभप्रदता के ऐतिहासिक उच्चस्तर, बेहतर संपत्ति गुणवत्ता और देश के 98 प्रतिशत से अधिक गांवों को शामिल करने वाली पहुंच से लैस है।

उन्होंने आगे कहा, हम इस मोड़ पर इस क्षेत्र की सुधार आधारित वृद्धि जारी रखने के लिए आवश्यक उपायों का मूल्यांकन करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण देते हुए कहा, मैं वित्तीय स्थिरता, समावेश और उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षित रखते हुए इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने और इसे भारत की वृद्धि के अगले चरण के साथ जोड़ने के लिए ''विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्चस्तरीय समिति'' स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के नजरिये को ऋण वितरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के स्पष्ट लक्ष्यों के साथ जोड़ा गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी में पैमाना हासिल करने और दक्षता में सुधार करने के लिए उन्होंने कहा कि पहले कदम के रूप में पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के पुनर्गठन का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, मैं भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन और उपयोगकर्ता के अनुकूल ढांचा तैयार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) नियमों की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव करती हूं। इस प्रस्ताव से देश के बैंकिंग क्षेत्र को लाभ मिल सकेगा।

भारत बनेगा एआई में सबसे बड़ा हब

नई दिल्ली, एजेंसी

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बजट पेश होने के बाद रेल भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि भारत कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) के क्षेत्र में दुनिया के सबसे बड़े हब के रूप में उभरने की दिशा में तेजी से अग्रसर है।

उन्होंने डिजिटल और तकनीकी विकास को बजट की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल बताया और कहा कि भारत का एआई-पारिस्थितिकी तंत्र आज पहले से कहीं अधिक व्यवस्थित, निवेश-अनुकूल बन चुका है। श्री वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सेमीकॉन 2.0 और सेमीकॉन 1.0 की सफलता के आधार पर आगे बढ़ रहा है, जो सेमीकंडक्टर के उपकरणों, सामग्री का घरेलू विनिर्माण और डिज़ाइन और प्रतिभा पारिस्थितकी तंत्र को मज़बूत करने पर फोकस करता है। उन्होंने मंत्रालय के तहत आईटी सेवाओं में बड़े सुधारों की भी घोषणा की। जिसमें टैक्स और लागू करने को आसान बनाना, और एआई डेटा सेंटर्स के लिए मज़बूत समर्थन शामिल है-जिसे 8.25 लाख करोड़ रुपये (90 बिलियन डॉलर) तक के निवेश और 2047 तक टैक्स हॉलिडे का सपोर्ट मिला है-जो भारत को वैश्विक एआई हब के तौर पर स्थापित करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि एआई और तकनीक को लेकर बजट में मिले प्रोत्साहन से देश में एआई -संबंधित बुनियादी ढांचे, डेटा-सेंटर, जीपीयू (ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट) क्षमता और शोध को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत किसी अन्य देश की नकल नहीं कर रहा, बल्कि अपनी रणनीति के साथ एक वास्तविक और व्यावहारिक एआई विकास मॉडल तैयार कर रहा है। श्री वैष्णव ने कहा कि एआई सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का अगला बड़ा इंजन है, और भारत की रणनीति इसे विश्व स्तर पर एक प्रमुख एआई हब के रूप में स्थापित करने की है। उन्होंने कहा कि सरकार एआई का उपयोग, स्किलिंग, रिसर्च और निवेश को समान रूप से बढ़ावा दे रही है ताकि देश के युवा, स्टार्टअप्स तथा उद्योग सभी इस तकनीक का लाभ उठा सकें।

पीएफ ट्रस्ट में नियोक्ता योगदान को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को भविष्य निधि या पीएफ ट्रस्ट के प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव दिया। इसके तहत नियोक्ता के योगदान पर समानता और प्रतिशत आधारित सीमाओं की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। इस पहल का मकसद कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) खातों में नियोक्ताओं के योगदान को सरल बनाकर कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देना है। इस समय कुछ ऐसे पीएफ ट्रस्ट हैं, जिन्हें सेवानिवृत्ति निधि संभालने वाली संस्था ईपीएफओ और आयकर विभाग से मान्यता प्राप्त है। इन ट्रस्ट के नियोक्ता कुछ सीमाओं के तहत पीएफ खातों में अपने कर्मचारियों के योगदान की तुलना में कम या अधिक राशि का योगदान करते थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट किया कि परिवर्तनों का उद्देश्य कामकाज को आसान बनाना है।

रियल एस्टेट और शहरी विकास को प्रोत्साहन

नई दिल्ली, एजेंसी

- राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा

केंद्रीय बजट पर राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने रविवार को कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच यह बजट उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना है।

श्री जैन ने बजट में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सभी क्षेत्रों व सेक्टरों तक अवसरों की समान पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है, जो "सबका साथ, सबका विकास" की भावना को मजबूती देता है। श्री जैन ने शहरी संतुलित विकास के लिए पूंजीगत व्यय को वित्त वर्ष 2026-27 में 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किए जाने के निर्णय को दूरदर्शी बताया। उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों पर विशेष फोकस से टियर-2 और टियर-3 शहरों में रियल एस्टेट गतिविधियों को नई गति मिलेगी और मेट्रो शहरों से परे संतुलित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर लोहिया वर्ल्डस्पेस के निदेशक पीयूष लोहिया ने कहा कि यह बजट आधारभूत ढांचे पर केंद्रित है और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्थिरता व दीर्घकालिक विकास का मजबूत आधार तैयार करता है। उन्होंने कहा कि सात हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर-मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करेंगे और इनके आसपास नए रियल एस्टेट, औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित होंगे। दोनों विशेषज्ञों ने कहा कि यह बजट रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भरोसेमंद, निवेश-अनुकूल और विकासोन्मुख वातावरण तैयार करता है, जो भारत के शहरी और आर्थिक भविष्य को नई दिशा देगा।

म्यूचुअल फंड आय से जुड़े ब्याज खर्चों पर कटौती खत्म करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली, एजेंसी

सरकार ने रविवार को लाभांश और म्यूचुअल फंड आय से संबंधित ब्याज खर्चों पर मिलने वाली कटौती को खत्म करने का प्रस्ताव रखा। बाजार विशेषज्ञों ने कहा कि इस प्रस्ताव से वह मौजूदा प्रावधान खत्म हो जाएगा, जिसके तहत लाभांश या म्यूचुअल फंड आय के 20 प्रतिशत तक के ब्याज खर्चों पर कटौती की अनुमति मिलती थी। आम बजट 2026-27 के अनुसार, यह प्रस्ताव है कि लाभांश आय या म्यूचुअल फंड की इकाइयों से होने वाली आय के संबंध में किए गए किसी भी ब्याज व्यय पर कोई कटौती नहीं दी जाएगी। साथ ही, एक तय सीमा तक ऐसी कटौती की अनुमति देने वाले मौजूदा प्रावधान को हटाने का भी प्रस्ताव है।

यह बदलाव आयकर अधिनियम, 2025 का हिस्सा है, जो एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा। अब अगर निवेशक कर्ज लेकर निवेश करते हैं, तो उनके ऋण के ब्याज जैसे खर्चों को लाभांश या म्यूचुअल फंड आय से घटाया नहीं जाएगा। इससे ऐसी आय पर कर योग्य राशि प्रभावी रूप से बढ़ जाएगी।

आवास ऋण के ब्याज पर छूट में अब ब्याज भी शामिल

नई दिल्ली, एजेंसी

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में प्रस्ताव दिया गया है कि स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति के मामले में आवास ऋण के ब्याज पर मिलने वाली दो लाख रुपये तक की आयकर कटौती में अब संपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण से पहले दिया गया ब्याज भी शामिल किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22(2) में संशोधन करेगी। इससे एक अप्रैल 2026 से लागू नए कर कानून के तहत गृह ऋण लेने वाले करदाताओं को राहत जारी रहेगी। बजट दस्तावेज के अनुसार आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22 गृह संपत्ति से होने वाली आय के मामले में मिलने वाली कटौतियों से संबंधित है।

विदेश में रहने वालों को निवेश की होगी अनुमति

नई दिल्ली, एजेंसी

पीआरओआई निवेश

- भारतीय कंपनियों में अब इक्विटी निवेश कर सकेंगे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत व्यक्ति (पीआरओआई) अब पोर्टफोलियो निवेश योजना के जरिये सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में इक्विटी निवेश कर सकेंगे। सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि पीआरओआई के लिए निवेश सीमा को भी अब पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है।

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कॉरपोरेट बॉन्ड सूचकांक पर कोष एवं डेरिवेटिव्स तक उपयुक्त पहुंच के लिए एक ढांचा विकसित करने का प्रस्ताव कर रही है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार पांच लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान देना जारी रखेगी।

उन्होंने कहा कि गुजरात के जामनगर में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन का वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र अद्यतन किया जाएगा। साथ ही देश की दूरबीन और खगोल विज्ञान अवसंरचना को भी उन्नत करने का प्रस्ताव है।

बजट के मुताबिक, पर्यटन एवं कौशल विकास क्षेत्र में सरकार 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड के कौशल उन्नयन के लिए पायलट योजना शुरू करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में पर्वतारोहण में विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करने की क्षमता मौजूद है। इसके अलावा केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण-संवेदनशील पर्यटन मार्ग भी विकसित करेगी।

सुधार

बजट में प्रशासनिक सुधारों को 65 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा

कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर 299 करोड़ खर्च करेगी सरकार

नई दिल्ली, एजेंसी

देश और विदेश में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने तथा बुनियादी ढांचे से संबंधित आवश्यक प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 299 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है।

रविवार को पेश बजट के अनुसार, इसके अलावा प्रशासनिक सुधारों के लिए 65 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस प्रावधान में सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण की योजना, प्रशासनिक सुधारों पर पायलट परियोजनाएं शामिल हैं जिनमें ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, सुशासन को प्रोत्साहित करना और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण के लिए एक व्यापक प्रणाली शामिल है।

आगामी वित्त वर्ष के लिए कुल 299 करोड़ रुपये के परिव्यय में से, 120.8 करोड़ रुपये प्रशिक्षण प्रभाग, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के लिए स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए, 52.2 करोड़ रुपये प्रशिक्षण योजनाओं के लिए और 126 करोड़ रुपये केंद्र के महत्वाकांक्षी ''मिशन कर्मयोगी'' या सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को निर्धारित की गई है। मिशन कर्मयोगी को सबसे बड़ी नौकरशाही सुधार पहल कहा जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को अधिक रचनात्मक, सक्रिय, पेशेवर और प्रौद्योगिकी-सक्षम बनाना है। बजट दस्तावेज में कार्मिक मंत्रालय के लिए बजटीय प्रावधानों का विवरण देते हुए कहा गया कि 120.8 करोड़ रुपये के प्रावधान में दिल्ली स्थित आईएसटीएम, मसूरी स्थित एलबीएसएनएए और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग से संबंधित स्थापना व्यय शामिल हैं। ये संगठन सचिवालय के सभी स्तरों तथा श्रेणियों के कर्मचारियों को नवीनतम नियमों एवं विनियमों और योग्यताओं से पर्याप्त रूप से अवगत कराने के लिए आधारभूत पाठ्यक्रम, पुनरावलोकन पाठ्यक्रम तथा मिड-करियर (कामकाज के दौरान) प्रशिक्षण सहित कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस आवंटन में घरेलू या विदेशी यात्रा पर होने वाला व्यय, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) और केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा (सीएसएस) के अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम शुल्क भी शामिल होगा।

बजट दस्तावेज में कहा गया कि 52.2 करोड़ रुपये के आवंटन में सभी के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान शामिल है। अगले वित्त वर्ष में सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के प्रचार-प्रसार के लिए 3.5 करोड़ रुपये का कोष अलग रखा गया है।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) को लोक सेवकों के सेवा संबंधी मामलों के निवारण का दायित्व सौंपा गया है। इसको आगामी वित्त वर्ष के लिए स्थापना संबंधी व्यय को 166.42 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। बजट दस्तावेज में कहा गया कि इसमें सीएटी की विभिन्न पीठों के लिए भूमि की खरीद एवं भवनों के निर्माण का प्रावधान भी शामिल है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 52.07 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव है।

बजट समावेशी, वृद्धि और रोजगार बढ़ाने वालाः महेंद्र देव

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के चेयरमैन एस महेंद्र देव ने रविवार को कहा कि बजट 2026-27 समावेशी है और वृद्धि तथा रोजगार को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बजट कारोबारी सुगमता के साथ ही रहन-सहन को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। देव ने लिंक्डइन पर पोस्ट किया, बजट 2026-27 विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अगला कदम है। यह वृद्धि, समावेश और रोजगार की दिशा में बढ़ने वाला बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों, वैश्विक डेटा केंद्रों के लिए कर छूट, और कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की।

दुर्घटना दावे से मिला हर्जाना अब आयकर से मुक्त होगा

नई दिल्ली, एजेंसी

- कानूनी उत्तराधिकारी को मि लेगी इसका लाभ
- एक अप्रैल से प्रभावी होगा यह संशोधन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आम बजट 2026-27 में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए जाने वाले हर्जाने को आयकर से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा।

बजट दस्तावेज के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत न्यायाधिकरण किसी व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को मृत्यु, स्थायी विकलांगता या किसी शारीरिक चोट के कारण मुआवजा और उस पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है।

दस्तावेज में कहा गया कि ऐसे हादसों के शिकार लोगों और उनके परिवारों की पीड़ा को कम करने के लिए उक्त अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके तहत मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली किसी भी आय पर व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को छूट दी जाएगी।

यह संशोधन एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और तदनुसार कर वर्ष 2026-27 तथा उसके बाद के कर वर्षों के संबंध में लागू होगा। इसमें यह भी कहा गया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई मुआवजे की राशि पर मिलने वाले ब्याज के संबंध में स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की जाएगी।

www.amritvichar.com

अमृत विचार

कानपुर महानगर

कानपुर, सोमवार, 2 फरवरी 2026

सुविचार

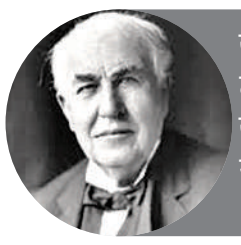

जीवन में अनेक विफलताएं केवल इसलिए होती हैं क्योंकि लोगों को यह आभास नहीं होता है कि जब उन्होंने प्रयास बन्द कर दिए तो उस समय वह सफलता के कितने क़रीब थे।

-थोमस एडिसन

कानपुर के प्रमुख समाचार

- -पूर्व से पश्चिम का सफर आसान होगा II
- ग्रेटर कानपुर योजना भरेगी उड़ान-III
- संत रविदास के आदर्शों पर चलने का संकल्प -IV

अनुराग हेल्थ केयर प्रा.लि.
•ICU •NICU DIALYSIS
• MODULAR OT
दूरबीन विधि से आपरेशन अब कम खर्च में
सीजीएचएस, मेडीक्लेम व आयुष्मान कार्ड मान्य
117/क्यू/702, शारदा नगर, कानपुर
9889538233, 7880306999

बंदी जैसे हालात की तरफ बढ़ रही लेदर इंडस्ट्री को संजीवनी मिली है। इसके साथ ही हाईस्पीड ट्रेन की सौगात के साथ मेट्रो कॉरिडोर-2 का काम समय से पूरा होने पर सफर को रफ्तार मिलना तय है।

बुनियादी ढांचा सुधरेगा

लेदर इंडस्ट्री को बूस्ट और सफर को रफ्तार

कार्यालय संवाददाता कानपुर

अमृत विचार। केंद्रीय बजट-2026-27 से अगर टियर-2 शहर होने के नाते तथा 'अर्बन चैलेंज फंड' के तहत जल निकासी और सीवरेज सिस्टम के नवीनीकरण के लिए विशेष बजट आवंटित किए जाने से कानपुर के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प होने की उम्मीद बंधी है, तो बंदी जैसे हालात की तरफ बढ़ रही लेदर इंडस्ट्री को संजीवनी मिली है। हाईस्पीड ट्रेन की सौगात के साथ मेट्रो कॉरिडोर-2 का काम समय से पूरा होने पर सफर को रफ्तार मिलना तय है। एलिम्को को 143 करोड़ के बजट आवंटन से जहां दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण होगा, वहीं महिला छात्रावास, जिला अस्पताल की क्षमता में वृद्धि, एमएसएमई सेक्टर को मिले बूस्ट और रक्षा उत्पादन में बजट वृद्धि से डिफेंस कॉरिडोर की पाइप लाइन में चल रही योजनाएं तेजी से धरातल पर आने का रास्ता भी खुला है। डिफेंस कॉरिडोर को रक्षा बजट में बढ़ोतरी और विमान के कलपुर्जों के निर्माण के लिए सीमा शुल्क में दी गई छूट का सीधा फायदा मिलेगा। लोहिया एयरोस्पेस में जल्द उत्पादन शुरू हो सकता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में औद्योगिक विकास के साथ तकनीकी संस्थान आईआईटी को रिसर्च और ट्रेनिंग में लाभ मिल सकता है।

143
करोड़ एलिम्को को बजट आवंटन से दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण होगा

3.30
मिनट में दिल्ली का सफर हो सकेगा ट्रेन से

लेदर इंडस्ट्री को संजीवनी

- शहर के सबसे बड़े उद्योग, लेदर सेक्टर के लिए बजट में राहत दी गई है। शू अपर्स के निर्यात के लिए इस्तेमाल होने वाले इनपुट पर बेसिक सीमा शुल्क से छूट दी गई है। पहले यह सुविधा लेदर गारमेंट्स, फुटवियर और लेदर प्रोडक्ट्स तक सीमित थी। इसके साथ ही लेदर गारमेंट्स और फुटवियर के निर्यात के लिए समय सीमा बढ़ाकर 1 साल कर दी गई है। इससे लेदर फैक्ट्रियों को उत्पादन लागत कम करने में मदद मिलेगी, जिससे लेदर शू तथा अन्य उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। कानपुर और उसके आसपास एक हजार छोटी-बड़ी लेदर इकाइयां संचालित हैं। इन्हें यूरोपीय यूनियम के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों के बाद बजट में घोषित राहत से संजीवनी मिली है।

शहर को मिलेगी पांच हजार करोड़ की सौगात

- केंद्र सरकार ने टियर-2 शहरों को 'ग्रोथ इंजन' के रूप में विकसित करने के लिए 5,000 करोड़ प्रति शहर का बजट आवंटित किया है। इसका फायदा प्रदेश के अन्य शहरों के साथ कानपुर को मिलना तय है। इसके तहत ग्रेटर कानपुर की योजना तेजी से धरातल पर उतर सकती है। इसके साथ ही शहर की इकोनॉमिक रीजन के रूप में मैपिंग भी की जा सकती है। इसी तरह औद्योगिक गलियारों के पास यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव है, जिससे कानपुर के युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

मेट्रो कॉरिडोर-2 का काम समय से पूरा होगा

- केंद्रीय बजट में कानपुर, लखनऊ और आगरा जैसे शहरों में मेट्रो रेल सेवाओं के विस्तार के लिए 32,075 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें कानपुर को भी हिस्सा मिलने से मेट्रो के अगले चरण कॉरिडोर-2 के काम में न सिर्फ तेजी आएगी, बल्कि समय से काम पूरा भी हो जाएगा।

दिल्ली का सफर साढ़े तीन घंटे में

दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का काम आगे बढ़ने से कानपुर को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा क्योंकि दिल्ली-वाराणसी मार्ग पर दौड़ने वाली हाईस्पीड ट्रेनें कानपुर से ही होकर गुजरेंगी। इससे कानपुर से दिल्ली का सफर साढ़े तीन घंटे और वाराणसी का सफर ढाई घंटे में तय किया जा सकेगा।

एमएसएमई सेक्टर को मिला बूस्टर

- एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई है। कानपुर के लघु और मध्यम उद्योगों को इससे अपनी कार्यशील पूंजी बढ़ाने में आसानी होगी। बजट में औद्योगिक क्षेत्रों के पास कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने की योजना है। शहर में महिला श्रमशक्ति की अधिकता को देखते हुए यहां ऐसे हॉस्टल जल्दी ही बनने की प्रबल संभावना है।

अपनी-अपनी बात

बजट से हम लोगों को सब्सिडी व राहत पैकेज की उम्मीद थी। वह उम्मीद पूरी नहीं हुई है। यह बजट भविष्य का बजट है। उद्योग पर अप्रत्याशित रूप से अपना असर दिखाएगा।

-सुशील टकरू, उद्यमी

यह बजट शहर के उद्योग के लिए मिलाजुला बजट है। किसी सेक्टर को कुछ हासिल हुआ है तो किसी सेक्टर को निराशा हाथ लगी है। बजट दूरदर्शी है। छोटे कारोबारियों को थोड़ी राहत देगा।

-उमंग अग्रवाल
महासचिव, फीटा

यह बजट भविष्य का बजट है। इस बजट से थोडी निराशा भी हाथ लगी है। सीधेतौर पर शहर के उद्योग को कुछ हासिल नहीं हुआ है। इस बजट का लाभ काफी समय बाद हासिल होगा।

मनोज बंका, प्रांतीय अध्यक्ष, पीआईए

कानपुर एलिम्को में एआई से बनाए जाएंगे कृत्रिम अंग

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। केंद्रीय बजट 2026-27 ने कानपुर के दिव्यांगों और बुजुर्गों बड़ी सौगात दी है। वित्त मंत्री द्वारा घोषित 'दिव्यांगजन कौशल योजना'' और 'दिव्यांग सहारा योजना' से शहर की पहचान बन चुका संस्था एलिम्को (भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम) को नई उड़ान मिलने वाली है। अब यहां के दिव्यांगों को न सिर्फ हाई-टेक उपकरण मिलेंगे, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

शहर में खुलेंगे मॉडर्न 'टेक्नोलॉजी मार्ट': अब दिव्यांगों और बुजुर्गों को अपनी जरूरत के सामान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कानपुर और दिल्ली से असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट की शुरुआत होने जा रही है। ये किसी बड़े शॉपिंग मॉल की तरह मॉडर्न रिटेल स्टोर होंगे, जहां आधुनिक व्हीलचेयर, हियरिंग एड्स और प्रोस्थेटिक्स आसानी से उपलब्ध होंगे।

बजट की 3 बड़ी सौगातें

- **एआई पर जोर :** एलिम्को को मिलने वाली फंडिंग बढ़ने से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृत्रिम अंग तैयार होंगे।
- **हुनर से मिलेगा रोजगार :** दिव्यांगजन कौशल योजना के तहत विजुअल इम्पेयर्ड के लिए सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग और फिजिकल डिसेबल्ड के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स जैसे कस्टमाइज्ड कोर्स सिखाए जाएंगे।
- **घर बैठे सुविधाएं :** सरकार का लक्ष्य बुजुर्गों और दिव्यांगों को उनके घर के पास ही सारी सुविधाएं और सर्विस मुहैया कराना है।

कानपुर को ही क्यों होगा ज्यादा फायदा?

- एलिम्को का मुख्य प्लांट कानपुर में है, इसलिए बजट का सबसे बड़ा हिस्सा और नई योजनाओं का ट्रायल सबसे पहले यहीं से शुरू होगा। इससे स्थानीय स्तर पर हजारों नौकरियां पैदा होंगी और शहर 'असिस्टिव टेक्नोलॉजी' का हब बनकर उभरेगा।

सरकार ने एलिम्को की वित्तीय दिक्कतों को दूर करने का जो फैसला लिया है, वह क्रांतिकारी है। टेक्नोलॉजी मार्ट खुलने से दिव्यांगों और बुजुर्गों का जीवन काफी आसान हो जाएगा।"

— प्रवीण कुमार, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एलिम्को

एलआरएस स्कीम में बदलाव से राहत

चर्चा

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

बैठक कर सीए ने बजट पर चर्चा की। अमृत विचार

अमृत विचार। विदेश में पढ़ाई करना और विदेश की यात्रा करना अब पहले के मुकाबले सस्ता होने जा रहा है। विदेश यात्रा और विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए पैसा भेजने पर लगने वाले टीसीएस पर सरकार बड़ी छूट देने का बजट में ऐलान किया है। नये नियम के तहत दो प्रतिशत ही टीसीएस देना होगा। यह नियम ढाई लाख डॉलर के खर्च करने पर लागू होगा।

यह जानकारी सिविल लाइन स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टिट्यूट में सीए राजीव मल्होत्रा ने दी। सिविल लाइंस स्थित कार्यालय में सभी आर्थिक विशेषज्ञों ने बजट की समीक्षा की। इस दौरान सीए डीपी शुक्ला, सीए नवीन भार्गव, सीए प्रशांत रस्तोगी, सीए यूएस गुप्ता, सीए अतुल मेहरोत्रा शामिल रहे। बताया गया कि पहले विदेश यात्रा करने पर 20 प्रतिशत टीसीएस और विदेश में पढ़ाई के लिये पैसा भेजने पर पांच प्रतिशत टीसीएस लगता था। जिससे अब बड़ी राहत मिलेगी। पूर्व सभापति सीआईआरसी अतुल मल्होत्रा ने बताया कि आयकर में अब अपील करना सस्ता हो जायेंगा। पहले अपील करने पर टैक्स का 20 प्रतिशत राशि जमा करने पर ही अपील कर सकते थे लेकिन अब नये बजट के अनुसार यह राशि को घटकर 10 प्रतिशत कर दी गयी है। जिससे अपीलकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। कानपुर सीए सीपीई के डिप्टी कंवीनर प्रशांत रस्तोगी ने बताया कि विदेश में बनायी गयी सम्पत्ति की अगर उस आयकर रिटर्न में घोषित नहीं किया गया तो 6 माह के अंदर विदेश की में खरीदी गयी सम्पत्ति की घोषणा कर 30 प्रतिशत अतिरिक्त कर देकर विदेश की सम्पति को घोषित किया जा सकता है। यह नियम पांच करोड़ से तक की सम्पत्ति पर होगा। नये बजट में किय गये प्रस्ताव में बायबैंक शेयर अगर कम्पनी प्रमोटर्स से खरीदती है तो 22 प्रतिशत डिविडेंट टैक्स लगेगा और यदि शेयरहोल्डर्स से कम्पनी खरीदती है तो शेयर होल्डर के दिन ऊपर 12.5 प्रतिशत कैपिटल गेन टैक्स लगेगा।

- विदेश में पढ़ाई करना और विदेश की यात्रा करना अब पहले के मुकाबले सस्ता होने जा रहा

अमृत योजना से 7 वार्डों में दूर होगी सीवर की समस्या

विकास पथ

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। अमृत योजना-2 के तहत शहर के सात वार्डों में 342 करोड़ रुपये से सीवर लाइन डाली जाएगी। अगले तीन साल में काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद पश्चिम क्षेत्र के इन वार्डों की तीन लाख आबादी को सीवर और जलभराव की समस्या से निजात मिल जाएगी। इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है।

अमृत योजना-2 के अंतर्गत 200 किलोमीटर सीवर लाइन डाली जाएगी। इसके साथ ही तीन पंपिंग स्टेशनों का निर्माण कराया जाएगा। सीवर के पानी का शोधन करने के लिए पनकी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जाएगा। शोधन के बाद पांडु नदी में डाला जाएगा। यह काम पूरा होने के बाद इन सभी सात वार्डों के लोगों को सीवर और जलभराव की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा।

अमृत योजना-2 के तहत जल निगम शहर में छूटे इलाकों में सीवर लाइन डालने का कार्य कराएगा। पश्चिम क्षेत्र से शुरुआत होगी। तीन सीवरेज पंपिंग स्टेशन के लिए जमीन चिह्नित की जा रही है। वार्ड में ही पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। दूषित पानी को शोधित करने के लिए पनकी में बने 30 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ दिया जाएगा। इसके बनने के बाद क्षेत्र में जलभराव नहीं होगा।

इन वार्डों को मिलेगा फायदा

- मसवानपुर (वार्ड 8), कल्याणपुर (19), आवास विकास कल्याणपुर (23), नवीन नगर काकादेव (25), नानकारी (27), विनायकपुर (54) और रावतपुर (60)।

समर्थ हॉस्पिटल
Ph.No.7081011022, 8115824810, 9935307505
3COM,1/14,आवास विकास, अम्बेडकरपुरम,कल्याणपुर,कानपुर
साफ नियत, सही विकास
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
के अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पताल
प्रदेश के लगभग 6 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख रुपये तक का इलाज पूरी तरह से निःशुल्क
डॉ. मिलन सचान
जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन
मुख्य विशेषताएं
हेल्प लाइन नम्बर-14555
प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का इलाज पूर्णतया निःशुल्क
सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में मिलेगा इलाज
चिकित्सालयों में मरीजों की सहायता के लिए आरोग्य मित्र की तैनाती
सेकेण्डरी, टर्शियरी जैसे कि कैन्सर, हृदयरोग जैसी 1350 बीमारियाँ सम्मिलित
परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु सीमा एवं लिंग की बाध्यता नही
पूर्व से चली आ रही बीमारियों का भी इलाज सम्मिलित
इलाज के दौरान दवा, जांच जैसे कि एक्स-रे इत्यादि पूर्णतया निःशुल्क
देश के अन्य राज्यों के सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा अनुमन्य
समर्थ हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड एवं पं. दीनदयाल योजना के अंतर्गत ऑपरेशन एवं इलाज की सुविधा उपलब्ध है।

टूटी उम्मीद फ्यूचर एंड ऑप्शन कारोबार पर 150 फीसदी तक सिक्योरिटी ट्रांसक्शन टैक्स बढ़ने का असर

शहर के निवेशकों को लगा 2,500 करोड़ रु. का झटका

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

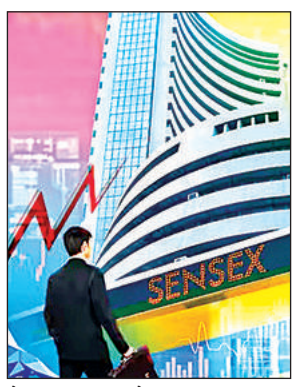

अमृत विचार। केंद्रीय बजट में टैक्स कटौती की उम्मीद लगाए शेयर बाजार को जोर का झटका लगा। टैक्स घटाने के बजाय सरकार ने वायदा कारोबार पर सिक्योरिटी ट्रांसक्शन टैक्स (एसटीटी) बढ़ा दिया। यह एलान रिटेल निवेशकों को ध्यान में रख कर लिया गया। सेबी के रिपोर्ट के अनुसार शेयर बाजार के वायदा कारोबार में 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स को घाटा होता है।

रिटेल निवेशकों को लम्बी अवधि में धन सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए फ्यूचर कारोबार के एसटीटी में 150 फीसदी के साथ ऑप्शन पर एसटीटी में 50 फीसदी बढ़ोतरी का एलान हुआ है। एसटीटी में बढ़ोतरी शेयर ब्रोकर्स और मार्किट इंफ्रा वाली कम्पनियों के लिए नेगेटिव है। फ्यूचर पर एसटीटी 0.02 प्रतिशत से बढाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है, वहीं ऑप्शन पर एसटीटी 0.10 %से बढाकर 0.15 फीसदी कर दिया गया है।

यह बढ़ोतरी शेयर बाजार को पसंद नहीं आई। और सेंसेक्स 2000 अंको से ज्यादा लुढ़क गया। हालांकि कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 1547 अंकों तथा निफ़्टी में 495 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। इस कारण शहर के निवेशकों के पोर्टफोलियो में करीब 2,500 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान लगाया गया है।

अच्छे फंडामेंटल्स और ग्रोथ वाली कंपनियों में करें निवेश

- बजट के प्रभावों को लेकर वित्तीय सलाहकार राजीव सिंह ने बताया कि सेकंडरी मार्किट से ख़रीदे सोवरन गोल्ड बांड को 1 अप्रैल 2026 के बाद बेचने पर टैक्स लगेगा, जबकि पहले यह टैक्स फ्री था। नगर निगम द्वारा 'म्युनिसिपल बांड' जारी करने तथा उसे स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कराने पर केंद्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये तक का इंसेंटिव दिया जायेगा। इसका फायदा कानपुर नगर निगम को मिलेगा, जिसका 'म्युनिसिपल बांड' प्रस्तावित है। एसएमई ग्रोथ फण्ड शहर को आईपीओ लाने को प्रोत्साहित करेगा। कुछ ही दिन पहले शहर में एसएमई आईपीओ को बढ़ाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन हुआ था। बजट के बाद आरबीआई का क्रेडिट पालिसी बाजार के लिए अहम होगा। अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो शेयर बाजार को सहारा मिल सकता है। लम्बी अवधि के लिए भारतीय शेयर बाजार का फंडामेंटल मजबूत है। गिरावट पर अच्छे फंडामेंटल्स और ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनियों के शेयरों में निवेश करना चाहिए, वो भी एक साथ की बजाय किस्तों में।

SILK WEAVES EXPO
सिल्क वीव्स एक्सपो
कानपुर में पहली बार
भारत की सबसे बड़ी सिल्क एक्सपो
EXHIBITION-CUM-SALE
Silks - Linens - Shawls - Wedding Ethnics
Showcasing the Art of Hands
सिल्क महोत्सव
आज अंतिम दिन!
Upto 60% OFF
23 जनवरी से 2 फरवरी
प्रातः 11 से रात्रि 9 बजे तक
लाजपत भवन
मोती झील एवेन्यू, हर्ष नगर, कानपुर
टेक्सटाइल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत
CONTACT - 6006747682 पार्किंग एवं एंट्री फ्री

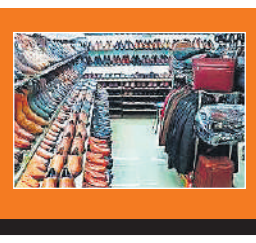

पूरब से पश्चिम तक का सफर आसान करेगी एलिवेटेड रोड

गोल चौराहे से लेकर रामादेवी तक बनाई जाएगी एलिवेटेड रोड

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। आम बजट ने शहरियों का सफर आसान करने की राह खोल दी है। यातायात व्यवस्था को बड़ी राहत देने वाली गोल चौराहे से रामादेवी तक प्रस्तावित एलीवेटेड रोड परियोजना को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी (एनएच) के इंजीनियर औपचारिकताएं पूर्ण करने में जुट गए हैं। जल्द ही अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

लोक निर्माण विभाग (एनएच) ने एलीवेटेड रोड के निर्माण के लिए वन एवं पर्यावरण के साथ ही रेल मंत्रालय की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है। रेल मंत्रालय की एनओसी प्राप्त करने के लिए पांच लाख रुपये की फीस जमा की गई है, जबकि वन विभाग का एस्टीमेट मिलने का इंतजार है। आम बजट में एलीवेटेड रोड का प्रावधान होने के बाद इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम स्वीकृति दिलाने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है।

एलिवेटेड रोड बनने के बाद रामादेवी के इस जाम से छुटकारा मिलेगा। अमृत विचार

10.2 किमी लंबी होगी एलिवेटेड रोड

- गोल चौराहे से रामादेवी तक बनने वाली एलिवेटेड रोड की लंबाई 10 .2 किलोमीटर होगी। इस एलिवेटेड रोड के बनने से टाट मिल चौराहा, झकरकटी बस अड्डा, जरीब चौकी जैसे इलाकों में यातायात का दबाव कम होगा और शहर के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक पहुंचने में सफर आसान हो जाएगा। तीनों स्थानों पर एलिवेटेड रोड पर चढ़ने और उतरने के लिए रैंप बनाए जाएंगे।

पीडब्ल्यूडी (एनएच) के लखनऊ मुख्यालय से करीब 15 दिन पहले फाइल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय कार्यालय को भेजी गई थी। मंत्रालय की ओर से एलिवेटेड रोड की डिजाइन और तकनीकी बिंदुओं की प्राथमिक जांच के बाद सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर आगे की कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि जल्द ही हरी झंडी मिल जाएगी। इसके निर्माण में लगभग 1500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

1500

करोड़ रुपये खर्च होंगे, तैयारी में जुटा पीडब्ल्यूडी

कई बार बदली गई रोड की डिजाइन

- एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाने का काम जनवरी 2024 में शुरू हुआ था। हेक्सा कंपनी को नवंबर 2024 तक डीपीआर सौंपनी थी, लेकिन विभागीय इंजीनियरों और कंपनी के बीच सहमति नहीं बनने और बार-बार संशोधनों के कारण डीपीआर का काम करीब 15 माह पिछड़ गया। करीब 20 बार बदलाव होने के बाद स्वीकृति के लिए भेजा गया। सबसे ज्यादा संशोधन अलाइमेंट, रैंप डिजाइन में हुए। झकरकटी बस अड्डे, जरीब चौकी और सीओडी क्रासिंग पर प्रस्तावित रैंप की ऊंचाई, मोड़ और सुरक्षा मानकों को लेकर आपत्तियां उठीं। जरीब चौकी पर एलिवेटेड रोड को सेतु निगम के ओवरब्रिज से छह मीटर ऊपर बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन इसे जोखिम भरा और महंगा मानते हुए डिजाइन बदली गई। अब एलिवेटेड रोड को सीधे ओवरब्रिज से जोड़ने का विकल्प तलाशा गया है।

ईवी पार्क परियोजना को मिल सकता है धरातल

कानपुर। महानगर विकास विजन 2030 के तहत भीमसेन के पास 500 एकड़ क्षेत्र में अत्याधुनिक ईवी पार्क की स्थापना होनी है। बजट में ईवी पार्क की स्थापना पर बल दिया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि पीपीपी मॉडल पर प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट को धरातल मिलेगा।

700 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस पार्क का निर्माण डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन पीपीपी मॉडल के तहत विकसित करेगा। यहां इलेक्ट्रिक मोटर, चेसिस, स्टील पार्ट्स, और लिथियम-आयन सेल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है। पार्क में चार्जर, कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन की इकाइयां भी स्थापित होनी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट में ईवी पार्क निर्माण पर जोर दिया है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिल सके। केडीए से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस परियोजना के लिए बजट मिलेगा।

पार्क में ईवी सहायक क्लस्टर भी विकसित किया जाना है। इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के समीप प्रस्तावित इस पार्क में लगने वाले उद्योगों को लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी की सुविधा आसानी से मिल जाएगी।

www.amritvichar.com
पर भी खबरें पढ़ें

छोटे उद्योगों को लोन नहीं निवेश से होगा लाभ

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। बजट में शहर में लगभग सवा लाख एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी इकाइयों को सीधा लाभ मिला है। यह लाभ 10 हजार करोड़ रुपये के एसएमई ग्रोथ फंड के जरिये मिलना माना जा रहा है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस ग्रोथ फंड से अब लोन के बजाय निवेश के जरिये इस सेक्टर को लाभ दिया जाना तय किया गया है। विशेषज्ञ इस फंड के नियम व शर्तों का इंतजार कर रहे हैं।

शहर में लगभग सवा लाख एमएसएमई सेक्टर की इकाइयां मौजूद हैं। इनमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी लगभग 20 फीसदी इकाइयां हैं। पूरे देश के लिए स्थापित एसएमई ग्रोथ फंड का लाभ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शहर के साथ ही गाजियाबाद, लखनऊ व गौतमबुद्ध नगर को मिलने की बात की जा रही है। यह फंड छोटे कारोबारियों को लोन के झंझट से छुटकारा दिलाएगा। खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग युनिट्स को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकार ग्रोथ फंड के जरिए एक ऐसा सिस्टम विकसित करने का मन बना रही है जो युनिट्स में निवेश करेगी। ऐसे में वे उद्यमी जिनके पास पूंजी की क्षमता कम है और इसके बावजूद उनके पास बड़ा ऑर्डर है तो वे इस निवेश को हासिल कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे युनिट के निदेशक को लोन के ब्याज और उसकी अदायगी से छुटकारा मिल सकेगा। ऑर्डर पूरा होने के बाद निवेश की गई रकम में लाभ में हिस्सेदारी के रूप में रकम चुकाई जाएगी। इससे उद्यमियों का काफी लाभ हासिल हो सकेगा।

फलेगा-फूलेगा उद्योग

- बजट में हुई इस व्यवस्था को शहर के लिए मुफीद माना जा रहा है। इसकी वजह कम पूंजी वाले उद्यमियों को अब बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए मिलने वाली आसानी से निवेश के रूप में रकम है। अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ के बाद घाटे में आए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उबारने के लिए सरकार की ओर से उठाया गया यह ठोस कदम है।

एफटीए के लिए तैयारी

- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्यात कारोबार में बड़ा योगदान माना जाता है। इस स्थिति में सरकार की ओर से हाल ही में किए गए एफटीए के लिए निर्यात इकाइयों को सुविधा दिए जाने की यह तैयारी मानी जा रही है। निर्यात विशेषज्ञों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ऑर्डर के अनुसार मजबूत करने और निवेश संबंधी सहायता दिए जाने को भविष्य का निर्णय माना जा रहा है।

बजट पर बोले

यह बजट रिफॉर्मिंग और गेमचेंजर साबित होगा। अर्थव्यवस्था को 2047 तक के लक्ष्य प्राप्ति के दृष्टिकोण से बहुत सुगम नजर आता है। इस बजट में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया।

-केशव बाजपेई, प्रांत सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच

यह बजट बहुत ही संतुलित है। इसमें युवा, किसान, उद्योग, कारोबार हर किसी का ध्यान रखा गया है। निश्चित रूप से यह बजट विकसित भारत के सपने को साकार करेगा।

- डॉ. विकास शुक्ला, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन

बजट घोर निराशाजनक है। कस्टम ड्यूटी, जीएसटी और खरीद पर नगद धनराशि की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया। महंगे होते सोने-चांदी से आम लोगों के लिए गहने खरीदना मुश्किल हो जाएगा।

- राम किशोर मिश्रा, मंत्री, उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन

बजट बहुत अच्छा है। इस बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जुड़ी दवाओं को सस्ता करने का निर्णय तो बहुत ही अच्छा है।

-राजेश चंदेल, व्यापारी नेता

बजट में एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड बनाया गया है, जो छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर प्रावधान सकारात्मक हैं।

-महेश सोनी, चेयरमैन व्यापार विकास समिति

केंद्र सरकार द्वारा बजट में जो स्थान खादी ग्रामोद्योग को मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। खादी ग्रामोद्योग गांव में रोजगार सृजन करती हैं। जिससे कि शहरो और पलायन रुकता है।

-सुरेश गुप्ता, अध्यक्ष, खादी ग्रामोद्योग महासंघ

इस बजट को भविष्य का बजट कहा जाएगा। बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए की गई घोषणाएं बेहतर व सकारात्मक परिणाम देंगे। इससे एमएसएमई सेक्टर के छोटे उद्यमियों को राहत मिलेगी।

-सुशील शर्मा, चेयरमैन, इडस्ट्री कमेटी, मर्चेंट चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश

यह बजट पूरी तरह से निराश कर देने वाला है। सोने व चांदी के दामों पर बजट में कोई प्रावधान नहीं है। यह बजट व्यापारियों को मारने वाला बजट है। किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं है।

-आशू शर्मा, अध्यक्ष, कानपुर महानगर बुलियन एंड सराफा एसोसएशन

टेक्सटाइल उद्योग को लेकर घोषणाएं हुई है। टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए हम लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अब घोषणा होने के बाद हम लोग उसे शहर लाने का प्रयास करेंगे।

-बलराम नरूला, उद्यमी

बजट में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह तात्कालिक रूप से प्रत्यक्ष राहत के प्रावधान दिखाई नहीं देते, किंतु दीर्घकालिक दृष्टि से यह बजट सकारात्मक और दूरदर्शी परिणाम देने वाला है।

-अतुल सेठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पीआईए

बजट देखते लोग। अमृत विचार

आत्मनिर्भरता और देश के विकास का बजट

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

- लघु उद्योग भारती, कानपुर की ओर से केंद्रीय बजट पर दी गई प्रतिक्रिया

अमृत विचार। लघु उद्योग भारती, कानपुर ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है। जिसमें सरकार ने देश के विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। संगठन ने बजट में किए गए प्रावधानों को उद्योग के लिए बेहतर बताया।

उद्यमियों ने कहा कि बजट में सरकार ने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ के लिए कॉरिडोर बनाने, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, एमएसएमई के लिए समर्थन, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, और डेटा सेंटर को टैक्स छूट देने की घोषणा की है। इस दौरान लघु उद्योग भारती, कानपुर के अध्यक्ष संदीप अवस्थी ने कहा कि यह बजट देश के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें उम्मीद है कि ये घोषणाएं हमारे उद्योगों को मजबूत करेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। उद्यमियों ने बजट की प्रमुख बिंदुओं पर कहा कि इस बजट में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ के लिए कॉरिडोर बनाने की घोषणा, 7 सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है।। इसके अलावा एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान, इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया गया है। उधर डेटा सेंटर को 2047 तक टैक्स छूट देने की घोषणा व 7 हाई-स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने की योजना इसमें शामिल हैं।

इसी तरह 20 हजार करोड़ का कार्बन ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए आवंटन व 20 नेशनल वॉटरवे का विकास राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेसवे की तरह किया जाएगा। इस दौरान लाडली प्रसाद गुप्ता, हरेंद्र मूरजानी, अमन घई, संदीप अरोरा, संदीप अवस्थी, अंकुर अंशवानी (महामंत्री), प्रेरणा वर्मा, सुशील मोहन टकरू, अजय गुप्ता, हिमांशु सिंह मौजूद रहे।

बजट से अर्थव्यवस्था होगी मजबूत और रोजगार बढ़ेंगे

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

- मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा बजट व्यूइंग सेशन का आयोजन

अमृत विचार। मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की फिस्कल कमेटी की ओर से रविवार को केंद्रीय बजट पर एक विशेष बजट व्यूइंग सेशन का आयोजन हुआ। डॉ. गौर हरि सिंघानिया कॉन्फ्रेंस हॉल में हुए आयोजन में उद्यमियो ने बजट को देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और रोजगार बढ़ाने वाला बजट बताया।

बजट व्यूइंग सेशन में केंद्रीय बजट 2026-27 का लाइव टेलीकास्ट बड़े स्क्रीन पर प्रसारित किया गया। जिसमें चेम्बर के पदाधिकारियों, सदस्यों, उद्यमियों तथा व्यापार एवं उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने देखा। उद्यमियों ने प्रस्तुत केंद्रीय बजट को देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, रोजगार सृजन, किसानों की आय में वृद्धि, मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने तथा भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से तैयार करने वाला बताया। वार्ता के दौरान चेंबर के इंडस्ट्री कमेटी के चेयरमैन सुशील शर्मा ने बताया कि यह बजट भविष्य का बजट हैं। इस बजट में खासतौर पर उद्योग के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने एमएसएमई सेक्टर और डिफेंस सेक्टर के लिए किए गए प्रावधानों को उद्योग के लिए बेहतर बताया। इस दौरान चेम्बर के पूर्व अध्यक्ष मुकुल टंडन, काउंसिल सदस्य अनिल अग्रवाल, फिस्कल समिति के एडवाइजर सुधींद्र जैन, चेयरमैन अनिल के. सक्सेना, कॉर्पोरेट अफेयर्स समिति के एडवाइजर अक्षय गुप्ता ने भी विचार रखे। उद्यमियों ने बजट के विभिन्न प्रावधानों, व्यापार एवं उद्योग पर इसके प्रभाव, विकासोन्मुखी नीतियों तथा भविष्य की आर्थिक संभावनाओं वाला बजट बताया। मर्चेंट्स चेम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के मुख्य परिचालन अधिकारी प्रभात मिश्रा ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य केंद्रीय बजट को सरल भाषा में समझना, उसके प्रभावों का विश्लेषण करना तथा व्यापारिक समुदाय को समयोचित एवं प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में मर्चेंट्स चेम्बर के काउंसिल सदस्य विजय पांडे, श्याम मेहरोत्रा, विश्वनाथ गुप्ता, तरुण गर्ग चैम्बर के सदस्य धर्मेंद्र श्रीवास्तव, डॉ. जय प्रकाश, उमेश पांडे, शेष नारायण त्रिवेदी सहित अन्य मौजूद रहे।

विशेष बजट सेशन में भाग लेते उद्यमी। अमृत विचार

मिलेगा सहयोग, बढ़ेगा टेक्सटाइल व होजरी उद्योग

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

- शहर में इस सेक्टर से नए उद्यमी उभरने की उम्मीद
- राजस्व बढ़ेगा और रोजगार के मौके मिलेंगे

05 हजार करोड़ का सालाना कारोबार

12 सौ करोड़ रुपये का होजरी कारोबार

13 सौ यूनिट होजरी की होती हैं संचालित

150 यूनिट्स टेक्सटाइल की होती हैं संचालित

अमृत विचार। बजट से शहर के टेक्सटाइल व होजरी उद्योग के लिए संभावनाएं खुल गई हैं। माना जा रहा है कि नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर, नेशनल हैंडलूम पॉलसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और टेक्सटाइल पाक जैसी घोषणाओं का शहर को भी लाभ मिल सकेगा। इससे न केवल राजस्व में बढ़ावा होगा अपितु रोजगार के मौके भी बढ़ सकेंगे।

वित्तमंत्री की इस सेक्टर की घोषणा के बाद अब यहां के उद्यमी शहर के टेक्सटाइल और होजरी सेक्टर के बढ़ने की उम्मीद जता रहे हैं। उनका कहना है कि इन योजनाओं के जमीन पर उतरने पर खासतौर पर नए उद्यमी को उभरने के लिए सहायता मिल सेकगी।

शहर में टेक्सटाइल व होजरी का लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का सालाना कारोबार है। इनमें सिर्फ होजरी की बात की जाए तो लगभग 13 सौ छोटी बड़ी युनिट्स यहां पर सीधे कारोबार से जुड़ी हैं। बजट से शहर के इस सेक्टर को लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

खासतौर पर कौशल और तकनीकी के लिए सहूलियत का असर भविष्य में इस सेक्टर में दिख सकता है। उद्यमी बलराम नरूला ने कहा कि यह बजट भविष्य का बजट है।

इस बजट में दूरदर्शिता साफतौर पर दिखाई दे रही है। ऐसे में होजरी व टेक्सटाइल उद्योग को इस बार के बजट में सीधे फोकस किया गया है। जिसका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ शहर के इस सेक्टर को मिलेगा। इस बजट में हुए इस सेक्टर के लिए घोषणा से होजरी व टेक्सटाइल् के निर्यात के बढ़ने की भी संभावना अधिक हो गई है।

मिल सकता टेक्सटाइल पार्क

- इस बार के बजट में टेक्सटाइल पार्क पर की गई घोषणा से शहर से उठ रही लंबे समय से मांग पूरी होने की संभावना भी बढ़ गई है। उद्यमियों का कहना है कि वे लोग लगभग 10 साल से टेक्सटाइल पार्क की मांग हर स्तर पर कर चुके हैं। अब बजट में घोषणा होने के बाद इस मांग के जोर पकड़ने की संभावना बढ़ गई है। घोषणा के बाद अब और जोर लगाकर इस योजना को शहर लाने का प्रयास किया जाएगा। पार्क मिलने से शहर के टेक्सटाइल इंटस्ट्री को पंख लग जाएंगे।

मंथन

कोऑपरेटिव इस्टेट सभागार में हुई बजट पर चर्चा

उद्यमियों ने औद्योगिक विकास का बजट करार दिया

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। केंद्रीय बजट को कोऑपरेटिव इस्टेट सभागार में उद्यमियों ने समीक्षा की। बड़ी स्क्रीन पर सभी उद्यमियों ने बजट को देखा। इस दौरान बजट को उद्यमियों ने औद्योगिक विकास का बजट करार दिया। उद्यमियों ने बजट को भविष्य का बजट बताया।

बजट की समीक्षा के बाद उद्यमियों ने कहा कि बजट में औद्योगिक विकास एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने की दिशा में किए गए प्रयास सराहनीय हैं। उनका मत है कि यदि निर्यातकों को और अधिक छूट व सुविधाएं प्रदान की जाएं, तो इससे निर्यात में वृद्धि होगी। उद्योगों को गति मिलेगी और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एमएसएमई सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। जो वर्तमान आवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त प्रतीत होता है। इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कम से कम एक लाख करोड़ का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन पुराने लघु उद्योगों पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जो पिछले लगभग 70 वर्षों से देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

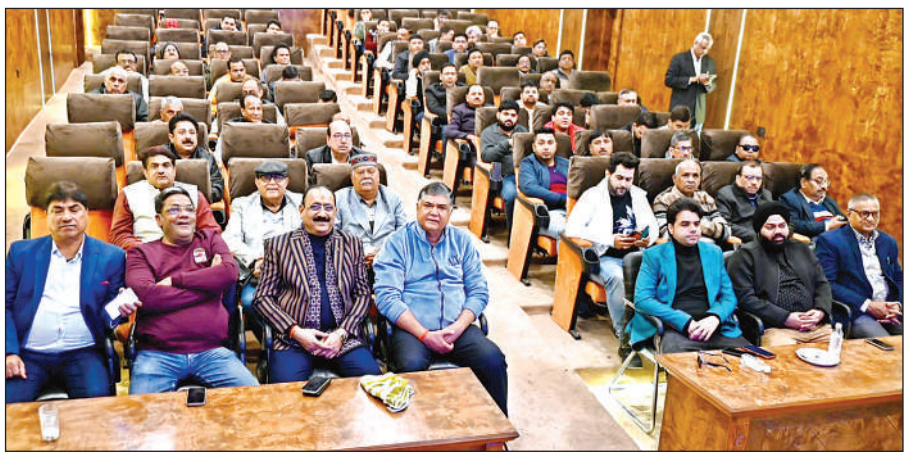

बड़ी स्क्रीन पर उद्यमियों ने बजट को देखा-सुना। अमृत विचार

- विकास और निर्यात को प्रोत्साहन पर खुशी जताई

इस दौरान हरीश इसरानी, विशाल खंडेलवाल, श्याम लाल मूलचंदानी, नरेश पंजाबी, बसंत लाल विश्वकर्मा, कार्तिक कपूर, समनदीप, अनिल श्रीवास्तव, निखिल गुप्ता, सतीश प्रकाश, संतोष पिपरिया, राजेश कत्याल, शिवेश दुबे, प्रेम राज, बॉबी कपूर, राजेंद्र गुप्ता, यशपाल सचान, देशराज मिश्रा, भीम सेन व अरुण जैन सहित अन्य उद्यमी मौजूद रहे।

अब हैलट में ट्रामा सेंटर की परियोजना को लगेंगे पंख

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

- केंद्रीय बजट में प्रोजेक्ट को किया गया बजट का प्रावधान
- 500 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाना है एपेक्स ट्रामा सेंटर

अमृत विचार। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध हैलट अस्पताल में लेवल-1 एपेक्स ट्रॉमा सेंटर को शासन स्तर से वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृति चार माह पहले मिल गई थी अब इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार से भी बजट मिल जाएगा। केंद्रीय बजट में ट्रामा सेंटरों की स्थापना के लिए भारी भरकम बजट आवंटित किया गया है। ऐसे में हैलट में प्रस्तावित प्रोजेक्ट को अब पंख लग जाएंगे। यह परियोजना पांच सौ करोड़ रुपये की है। शासन ने 168 करोड़ 50 लाख रुपये पहले ही आवंटित कर दिया था।

मेडिकल कॉलेज प्राचार्य हैलट में 300 बेड का एपेक्स ट्रामा सेंटर बनाने का प्रस्ताव भेजा था।

यह सेंटर ट्रामा इंस्टीट्यूट की तरह काम करेगा। यहां डाक्टर, पैरा मेडिकल और टेक्नीशियन उच्च मानक की पढ़ाई कर सकेंगे। एपेक्स ट्रामा सेंटर में गंभीर मरीज के इलाज के साथ पठन-पाठन के लिए अकादमिक ब्लाक की सुविधा होगी। छह मंजिला ट्रामा इंस्टीट्यूट में 200 बेड के साथ 100 बेड का आइसीयू भी होगा। इसकी छत पर एयर एंबुलेंस के लिए दो हेलीपैड बनेंगे ताकि मरीजों और घायलों को एयर लिफ्ट किया जा सके।

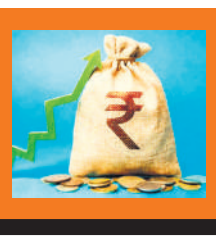

शहर को सौगात

अमृत विचार

बजट पर बोले

यह भविष्य का सकारात्मक बजट है। इस बजट से बाजार की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। इसका असर रोजगार पर भी पड़ेगा। युवाओं को रोजगार के अवसरों के खुलने का लाभ हासिल होगा।

–मुकुंद मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल

चमड़े के वस्त्र, चमड़ा या सिंथेटिक जूते और शुल्क-मुक्त आयातित इनपुट का उपयोग करके निर्मित चमड़े के उत्पादों के निर्यात दायित्व को 6 महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है।

–आलोक श्रीवास्तव, सहायक निदेशक, फियो

टेक्सटाइल पार्क की घोषणा होने के बावजूद भी कानपुर का कपड़ा उद्योग खाली हाथ है। व्यापारी कल्याण के लिए बहुत उम्मीदें थी। निराशा ही हाथ लगी है। मूलभूत उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की गई।

– रूमित सिंह सागरी, निदेशक, कानपुर कपड़ा कमेटी

बहुत निराशा जनक बजट है। आम आदमी मजदूर, किसान के लिए कुछ नहीं है। बेरोजगारी दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। फैक्ट्रीया लगाने की कोई योजना पर काम नहीं किया।

–आलोक मिश्र, कांग्रेस नेता

बजट स्वागत योग्य है, रोजगार सृजनोन्मुख है, देश के विकास को गति मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली नहीं होने से कर्मचारियों में मायूसी है। इस बजट को भविष्य का बजट कहा जाएगा।

–प्रभात मिश्रा, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद

ग्रेटर कानपुर योजना भरेगी उड़ान

आम बजट में टियर-2 श्रेणी के शहरों को मिला बजट, कानपुर को भी मिलेगा फायदा

बृजेश श्रीवास्तव, कानपुर

- हजारों परिवारों के आशियाना का सपना हो सकेगा पूरा
- मेडिसिटी, एमएसएमई और ई-वाहन पार्क भी बनेंगे

अमृत विचार। आम बजट में टियर-2 श्रेणी के शहरों में 12.2 लाख करोड़ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के प्रावधान से ग्रेटर कानपुर योजना के बसने और ऐरो सिटी के धरातल पर उतरने का सपना पूरा हो सकेगा। कानपुर विकास प्राधिकरण ने महानगर में ग्रेटर कानपुर योजना विकसित करने के लिए करीब 5000 वर्गमीटर की परियोजना का खाका तैयार किया है।

केडीए ने ग्रेटर कानपुर योजना विकसित करने के लिए कंसल्टेंट कंपनी से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) मांगे थे। करीब 5000 वर्गमीटर की इस परियोजना का खाका तैयार किया गया है। ग्रेटर कानपुर योजना में सड़कें, प्लाट, बहुमंजिला इमारतें, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स सहित अन्य सार्वजनिक सुविधाएं होंगी और तीन व्यावसायिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। ग्रेटर कानपुर योजना धरातल पर उतरने के बाद शहर के विकास को एक नई उड़ान मिलेगी और विकसित कानपुर की तस्वीर बदल जाएगी।

कानपुर विकास प्राधिकरण ने भीमसेन रेलवे स्टेशन और आउटर रिंग रोड के बीच भैरमपुर, कैंधा, रामपुर सहित सात गांवों की करीब 5000 एकड़ जमीन पर ग्रेटर कानपुर योजना विकसित करने का खाका तैयार किया है, जिससे जहां एक तरफ हजारों परिवारों का आशियाना का सपना पूरा होगा, वहीं मेडिसिटी पार्क, एमएसएमई पार्क और ई-वाहन पार्क भी बनेंगे।

आम बजट पेश होने के बाद केडीए ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर ग्रेटर कानपुर की तैयारी में जुट गया है। पांच हजार एकड़ में यह अब तक की शहर की सबसे बड़ी योजना है। इस योजना को तीन फेज में धरातल पर लाया जाएगा।

जल्द ही जमीन को चिह्नित कर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। भीमसेन और आउटर रिंग के बीच स्थित जमीन और सात गांवों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए खरीद और विक्रय पर रोक लगेगी। किसानों से सर्किल रेट का चार गुणा दाम देकर जमीन खरीदी जाएगी। हर वर्ग के लिए आवासीय, व्यावसायिक व औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। पहला फेज दो हजार एकड़ में विकसित होगा।

मंधना-भौंती बाईपास के किनारे होगा डेवलपमेंट

- ग्रेटर कानपुर योजना भीमसेन और निर्माणाधीन आउटर रिंग रोड के बीच विकसित की जाएगी। यह क्षेत्र भौंती से पांच किलोमीटर और भीमसेन रेलवे स्टेशन से दो किलोमीटर दूर है। मंधना से भौंती बाईपास करीब साढ़े आठ किलोमीटर का है। इसकी मरम्मत में 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके दोनों तरफ डेवलपमेंट होगा। इससे सेन पश्चिम पारा, सेन पूरब पारा, पतेहुरी गोपालपुर, गंभीरपुर कैथा सरनेतपुर, डांडे का पुरवा, दुर्जनपुर इटारा आदि गांवों को फायदा होगा।

हर वर्ग के लिए बनेंगे फ्लैट

- योजना में कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के भूखंड व फ्लैट तैयार किए जाएंगे। मध्यम और उच्च आय वर्ग के लिए एमआईजी, एचआईजी प्लाट, ग्रुप हाउसिंग, मल्टीस्टोरी फ्लैट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही ग्रीनबेल्ट, पार्क, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, शॉपिंग काम्प्लेक्स, सामुदायिक केंद्र, आधुनिक कूड़ाघर, दूषित पानी के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण कराया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर, सोलर लाइटिंग, वेस्ट मैनेजमेंट जैसी सुविधाएं भी होंगी।

एयरो सिटी भी धरातल पर उतरेगी

- **कानपुर।** चकेरी एयरपोर्ट का विस्तार करने की तैयारी है, ताकि यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकें। कानपुर एयरपोर्ट से अभी चार शहरों तक ही हवाई उड़ान की सुविधा है। एयरपोर्ट के विस्तार के बाद हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अभी सिर्फ 50 एकड़ में एयरपोर्ट है। विस्तार के लिए जमीन चिह्नित करने और उसका अधिग्रहण करने की जिम्मेदारी केडीए को दी गई है। केडीए ने जमीन चिह्नित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। यहां एयरो सिटी भी बसाने की तैयारी है।

हमीरपुर समानांतर हाईवे के निर्माण की बाधा दूर

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। रमईपुर के पास मगरासा गांव से रिंग रोड से शुरू होकर घाटमपुर से हमीरपुर के रास्ते महोबा के कबरई तक प्रस्तावित फोरलेन एलिवेटेड हाईवे के निर्माण के लिए केंद्रीय बजट में धनराशि का प्रावधान कर दिया गया है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप देने में अब किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। इस मार्ग के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण को बजट की आवश्यकता थी जो अब मिल जाएगी। निर्माण के लिए टेंडर मांगा जा चुका है। जिसे इसी माह खोला जाएगा।

भूमि अधिग्रहण के लिए धारा श्री ए का प्रकाशन हो चुका है। किसानों की भूमि का अंश निर्धारण किया जा रहा है। जल्द ही आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद धारा श्री डी का प्रकाशन होगा। इसके बाद मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। फिलहाल इस प्रक्रिया में अभी तीन से चार माह का समय लगेगा। हालांकि जो किसान धारा श्री डी के प्रकाशन से पहले सुलह समझौता के आधार पर रजिस्ट्री करना चाहेंगे उनसे भूमि की रजिस्ट्री कराई जाएगी। ऐसे में बजट की आवश्यकता पड़ेगी। पूरे प्रोजेक्ट पर 57 सौ करोड़ रुपये खर्च होने हैं। यह राशि बजट में आवंटित है ऐसे में परियोजना आसानी से मूर्त रूप ले लेगी। भोपाल से छतरपुर होते हुए फोर लेन हाईवे का निर्माण हो रहा है। कानपुर से कबरई तक प्रस्तावित 112 किलोमीटर लंबा हाईवे इसी हाईवे से कबरई में मिल जाएगा।

औद्योगिक विकास को लगेंगे पंख

- रमईपुर में प्रस्तावित मेगा लेदर क्लस्टर और मेगा फुटवेयर पार्क जैसी परियोजनाओं को इस हाईवे से गति मिलेगी। इसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर के विस्तार की योजना को भी पंख लगेगा क्योंकि इस हाईवे से आसानी से मुंबई, भोपाल आना- जाना आसान हो जाएगा। उद्यमी आसानी से अपने उत्पाद की ढुलाई कर सकेंगे और कच्चा माल यहां ला सकेंगे।

सिंगल पिलर पर बनने वाले इस हाईवे पर कानपुर के घाटमपुर में रैंप बनेगी। इसके बाद हमीरपुर, महोबा, कबरई आदि में रैंप का निर्माण होगा। प्रशासन को 1139 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना है। इसमें हमीरपुर के 35 गांवों की 500 हेक्टेयर, कानपुर नगर व देहात के 49 गांवों की 387 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। महोबा के नौ गांवों की 252 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी। किसानों से सुलह समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि समय से भूमि का अधिग्रहण हो जाए और प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सके। हमीपुर, कबरई से बड़े पैमाने पर गिट्टी, मौरंग कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, अयोध्या, लखीमपुर आदि जिलों को भेजी जाती है। इस वजह से वर्तमान हाईवे पर जाम लगता है। लेकिन नया हाईवे बनने के बाद जाम की समस्या खत्म हो जाएगी।

बजट पर बोले

आम बजट से कर्मचारियों एवं सेवा निवृत्त कर्मियों को घोर निराशा हुई है। उनकी आशा के विपरीत यह बजट है वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में कोई छूट नहीं दी गई। ओपीएस के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई।

–राजेश कुमार शुक्ला, अध्यक्ष पेंशनर एसोसिएशन

टैक्स प्रक्रिया को सरल और आधुनिक बनाने वाला बजट है। 'इनकम टैक्स एक्ट 2025 'पेश करना और 'असेसमेंट ईयर 'की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर 'टैक्स ईयर' लागू करना बेहतर कदम है।

–सिमरन जीत सिंह, टैक्स प्रैक्टिशनर

बजट में कैंसर जैसी महत्वपूर्ण औषधियों को सस्ता किया जाना राहत भरा कदम है। इस्पात, सीमेंट आदि पर कर में कमी से इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में मदद मिलेगी। यह बजट राहत देने वाला है।

–उदय राज सिंह, मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद

यह बजट महंगाई से त्रस्त आम जनता, बेरोज़गार युवाओं, मजदूर, छोटे व मध्यम व्यापारियों, महिलाओं, संघर्ष कर रहे किसानों और मध्यम वर्ग की उम्मीदों को तोड़ने वाला है। यह बजट आम आदमी के साथ विश्वासघात है। सरकार ने युवाओ को रोजगार सृजन, किसानों की आय दोगुनी करने और महिलाओं-गरीबों को राहत देने के बजाय कॉरपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने वाला बजट पेश किया है। महंगाई कम करने की कोई ठोस योजना नहीं है।

–पवन गुप्ता, अध्यक्ष कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी

बजट में लेदर कारोबारियों को अधिक राहत नहीं दी मगर, पिछले साल बजट में जिस 20 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा हुई थी, उसे लेकर कोई वक्तव्य सामने नहीं आया। हम उसी पैकेज का इंतजार कर रहे हैं।

– मुख्तारुल अमीन, अध्यक्ष, सुपरहाउस ग्रुप

यह बजट हाल ही में हुए एफटीए को सहायता पहुंचना वाला है। यह बजट भविष्य का बजट है। इसमें कई ऐसे प्रावधान हुए हैं जो उद्योग जगत को राहत प्रदान करने वाले हैं।

–सुनील वैश्य, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आईआईए

एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़ के प्रावधान से छोटे, लघु उद्योगों व व्यापारियों को लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल, 2026 से रिटर्न दाखिल करने में सरलीकरण के लिए नए प्रावधान से टैक्स प्रक्रिया आसान होगी।

–ज्ञानेश मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल

यह बजट युवा शक्ति को केंद्र में रखकर तैयार किया गया दूरदर्शी बजट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल नवाचार, स्टार्टअप और कौशल विकास को प्राथमिकता दी गई। इससे युवाओ को लाभ होगा।

–प्रो विनय कुमार पाठक, कुलपति, सीएसजेएमयू

बजट में व्यापारियो के लिए कुछ भी नहीं, यह पूर्ण रूप से निराशा जनक है। उम्मीद थी बजट में कई ट्रेड में राहत मिलेगी और एमएसएमई के उद्योगों में भी कोई राहत नहीं मिली।

–आयुष द्विवेदी, अध्यक्ष, कानपुर युवा उद्योग व्यापार मंडल

अधिवक्ता ने 2.50 लाख हड़पे, पीड़िता को धमकाया

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। कोतवाली में दुष्कर्म पीड़िता ने अधिवक्ता पर 2.50 लाख रुपये हड़पने व आरोपी से साठगांठ का आरोप लगाया है। विरोध पर अधिवक्ता ने जान से मारने व फर्जी मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी। कोतवाली पुलिस ने अधिवक्ता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

जूही की रहने वाली पीड़िता के अनुसार 2025 में उन्होंने दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद वह विधिक राय के लिए अधिवक्ता वीएन मिश्रा से मिली। आरोप है कि अधिवक्ता ने दुष्कर्म के मामले में सरकार से मुआवजा दिलाने का झांसा देकर केनरा बैंक में खाता खुलवाया। उनसे सादे कागज व चेकबुक पर हस्ताक्षर करवाकर अपने पास रख लिया। करीब 2.50 लाख रुपये लिए। इसके अलावा अधिवक्ता ने आरोपी से मिलकर उसकी जमानत में मदद की। जिसकी जानकारी होने पर उन्होंने अधिवक्ता से चेकबुक वापस मांगी तो हस्ताक्षर किए चेक गायब थे। अपनी रकम मांगी। इस पर अधिवक्ता ने गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी व फर्जी मुकदमे में फंसाने को धमकाया।

ग्रामीण बैंक में लगी आग, फर्नीचर-दस्तावेज जले

कानपुर । कल्याणपुर में ग्रामीण बैंक में रविवार सुबह अचानक धुंआ उठने लगा। यह देख राहगीरों ने तत्काल पुलिस को खबर दी। पुलिस की सूचना पर पहुंची दमकल ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग से बैंक का फर्नीचर व कुछ दस्तावेज जल गए। पुलिस के अनुसार कैश रूम सुरक्षित रहा।

उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की कल्याणपुर शाखा में रविवार सुबह अचानक आग लग गई। बैंक परिसर से धुआं उठता देख राहगीरों ने शोर मचा दिया। आवाज सुनकर मकान मालिक सतीश मिश्रा की नातिन कृतिका ने पुलिस व फायर ब्रिगेड को हादसे की खबर दी।

सगे भाइयों समेत चार बच्चे झुलसे

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

- सचेंडी में कंजड़न मोहल्ला के पास अलाव तापते समय हुआ धमाका राख समझकर बारूद डाल दिया

अमृत विचार। सचेंडी में रविवार सुबह अलाव तापते समय तेज धमाका हुआ। जिसमें सगे भाइयों समेत चार बच्चे झुलस गए। धमाके की आवाज व बच्चों की चीख सुनकर परिजन पहुंचे और तत्काल घायलों को लेकर अस्पताल भागे। दो भाइयों को उर्सला व दो को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह शौच के लिए गए बच्चे राख के धोखे में बारुद उठा लाए थे। जिसे अलाव तापते समय आग में डालने से धमाका हुआ। बारुद घर से कुछ दूरी पर पड़ी थी। पुलिस ने आशंका जताई कि पटाखों के अवैध भंडारण के खिलाफ किसी ने बारुद फेंकी होगी कंजड़न मोहल्ला निवासी बीनू पावदान चटाई की फेरी लगाते हैं। उनके परिवार में आठ वर्षीय बेटा निहाल, सात वर्षीय का करिया और तीन वर्षीय बेटी अमायरा व पत्नी रजनी हैं। उर्सला में घायल बच्चों की देखरेख कर रहीं रजनी ने बताया कि सुबह निहाल व करिया शौच के लिए घर से बाहर गए थे। उनके साथ पड़ोसी किशन का आठ वर्षीय बेटा कृष्णा और जयल का आठ वर्षीय बेटा ऋषि भी था। शौच से लौटते समय बच्चों को बारुद पड़ी दिखी। जिसे वह राख समझकर उठा लाए।

सुबह कोहरा और गलन होने के कारण बच्चों ने अलाव जलाया और तापने लगे। तभी खेल-खेल में बच्चों ने राख भी अलाव में डाल दी। उसे डालने ही धमाका हुआ। अलाव की चिंगारी फैलने से चारों बच्चे गंभीर झुलस गए। उनकी चींख और धमाका सुनकर मोहल्ले के लोग व परिजन भागकर मौके पर पहुंचे। बच्चों को अस्पताल लेकर भागे। निजी अस्पताल के बाद निहाल व करिया को उर्सला ले जाया गया। जबकि दो अन्य बच्चों का वहीं इलाज चल रहा है। सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि दिवाली पर आतिशबाजी के अवैध भंडारण पर पुलिस ने सख्त अभियान चलाया था। कुछ लोगों ने चोरीछिपे काफी पटाखा नष्ट कर दिया था। आशंका जताई कि पुलिस से बचने के लिए ही किसी ने पटाखों की बारुद फेंकी होगी।

वकील समेत 6 पर धोखा देने और ठगी की रिपोर्ट

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। कोतवाली में अधिवक्ता समेत छह लोगों पर धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। झांसी के बराटा नई बस्ती निवासी पूजा देवी के अनुसार उनके पति रमाकांत त्रिवेदी रोडवेज में कर्मचारी थे। 23 सितंबर 2014 को दुर्घटना में पति की मौत हो गई। उन्होंने कर्मचारी क्षतिपूर्ति के तहत न्यायालय आयुक्त सर्वोदयनगर में वाद दाखिल किया। पैरवी के लिए अधिवक्ता अजय कुमार सिंह चंदेल, उनके जूनियर संजय बाजपेई को नियुक्त किया। 30 मार्च 2017 को 7,88,240 रुपये क्षतिपूर्ति राशि उन्हें, चार बच्चों व सास को देने का आदेश हुआ। अधिवक्ता ने उनका व सास का खाता यूको बैंक में खुलवाया। बैंक पासबुक अपने पास रख ली। सास के खाते से एक लाख रुपये फीस ली।

खाते में 2.94 लाख रुपये बचे थे। 2025 में अधिवक्ता से बैंक पासबुक व बच्चों की एफडी मांगी। इस पर मना कर दिया। जब बैंक से डुप्लीकेट पासबुक और स्टेटमेंट निकलवाया तो जानकारी हुई कि 2017 से 2019 के बीच फर्जी हस्ताक्षर और कूटरचित दस्तावेजों से चेकबुक जारी कराकर खाते से 2,99,700 रुपये निकाले गए हैं।

राहत | सीवर, सड़क और अन्य कार्यों के लिए तकनीकी बिड खुली

इस्पातनगर के विकास के लिए 54 .62 करोड़

विशेष संवाददाता,कानपुर

अमृत विचार। कोई 40 साल से विकास कार्यों की बाट जोह रहे इस्पातनगर के दिन बहुर गए। अब वहां 54.62 करोड़ रुपये की लागत से सीवर लाइन, सड़कों के साथ ही अन्य विकास कार्य होंगे।

यह जानकारी कानपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता आरपी सिंह ने सांसद रमेश अवस्थी को पत्र के जरिये दी। दरअसल 1984 में बसाए गए इस्पातनगर में विकास कार्य नहीं होने के कारण कारोबार बड़े पैमाने पर प्रभावित था। कई उद्योग और व्यापार दूसरे स्थानों में शिफ्ट हो गए थे। यह क्षेत्र 2014 में केडीए को हस्तांतरित कर दी गई थी। जुलाई 2025 को इस्पातनगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद पॉल ने कारोबारियों के साथ सांसद रमेश अवस्थी को ज्ञापन देकर समाधान का निवेदन किया था। सांसद रमेश अवस्थी ने इस बाबत मंडलायुक्त से बात की, चिट्ठी लिखी और संबंधित विभागों को भी निर्देश दिए। इस इलाके का सर्वे हुआ और इस्टीमेट बनाया गया। अब फाइल ओके हो गई है। 54.62 करोड़ की तकनीकी बिड खुल गई है। इसका परीक्षण किया जा रहा है। सीवर लाइन, सड़कों की मरम्मत, निर्माण, फुटपाथ और अन्य विकास कराए जाएंगे। सीवर लाइन डालने का काम जल निगम और सड़कों का काम केडीए करेगा। यह जानकारी इस्पातनगर उद्योग व्यापार मंडल को दे दी गई है।

इस्पात नगर में सड़कें गायब हैं। अमृत विचार

अब कोई समस्या नहीं रहेगी

इस्पातनगर में वाकई समस्या विकराल है। जलनिकासी के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं। सड़कें तो बेहद जर्जर हैं। अब बिड खुल गई है और शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। हमने जो वादा व्यापारियों से किया, उसे पूरा किया।

–रमेश अवस्थी, सांसद

व्यापारी से 1.04 करोड़ की धोखाधड़ी, रिपोर्ट

कानपुर। काकादेव में व्यापारी ने 1.04 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। बिरहाना रोड निवासी अनुपम अग्रवाल ने बताया कि वह मेसर्स पैरागन कॉटन टेक्सटाइल प्रा. लि. व उमा पॉलिस्टर्स प्रा.लि. के निदेशक हैं। उनकी कंपनियों से वीवी टेक्सटाइल व मेसर्स जीएलकेके इंडस्ट्रीज प्रा.लि. को पॉलिमर व मास्टर बैच दाने की आपूर्ति की जा रही थी। आरोप है कि वीवी टेक्सटाइल पर 98.50 लाख और जीएलकेके इंडस्ट्रीज पर 5.67 लाख रुपये का बकाया है। इसके बावजूद संचालकों ने फर्म बंद कर दी। मशीन व अन्य स्टॉक बेच दिया। अक्टूबर 2025 को काकादेव पहुंचकर बकाया मांगने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी।

श्रीहरि और मां लक्ष्मी का गुलाब और कमल पुष्प से सहस्त्रार्चन

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। धूनी ध्यान केंद्र एवं शकुंतला शक्ति पीठ विकास नगर में राजलक्ष्मी ललिता महायज्ञ का आयोजन किया गया। सवा लाख गुलाब एवं कमल के पुष्पों से पूर्ण आहुति संपन्न की गई। इस अवसर पर भगवती महालक्ष्मी और भगवान श्रीहरि विष्णु का सहस्त्रार्चन किया गया। श्रद्धालुओं ने गुलाब पुष्प, किसमिस, मखाना आदि द्रव्यों से भगवती महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन किया।

पीठ के संस्थापक डा. आचार्य अमरेश मिश्रा एवं कोषाध्यक्ष सुनीता मिश्रा के संरक्षण आयोजित महायज्ञ में आचार्यों ने राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी का भी पूजन किया। इस अवसर पर केए दुबे पद्मेश, बाल विकास राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला, विधायक नीलिमा कटियार, विधायक अमिताभ बाजपेयी, पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी, विधायक सलिल विश्नोई, रोचना विश्नोई, महामंडलेश्वर श्रीकृष्ण दास जी महाराज, सिद्धेश्वर पीठाधीश्वर अरुण पुरी जी महाराज, गंगा प्रहरी राम जी त्रिपाठी ने महायज्ञ में हिस्सा ले कर लक्ष्मी नारायण का सहस्त्रार्चन किया।

पूजन करतीं राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला व पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी।

- धूनी ध्यान केंद्र एवं शकुंतला शक्तिपीठ में पूर्णिमा पर महायज्ञ का आयोजन

सिटी ब्रीफ़

संत शिरोमणि ने दिया आपसी सौहार्द, समानता भाईचारे का पैगाम

कानपुर। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपने जीवन और वाणी से समाज को समानता, प्रेम, भाईचारा और सामाजिक न्याय का संदेश दिया। रविवार को कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती श्रद्धा एवं सम्मान के साथ तिलक हाल में मनाई गई। कार्यक्रम में संत शिरोमणि के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके विचारों को स्मरण किया गया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष पवन गुप्ता शंकर दत मिश्रा, मदन मोहन शुक्ला, विकास सोनकर, रितेश यादव, सैमुअल लकी सिंह, इकलाक अहमद, अजय श्रीवास्तव, राकेश साहू, संजय दीक्षित, सुरेन्द्र भदौरिया, राज किशोर वर्मा, रामजी दुबे, शांतनु दीक्षित, मुकेश कन्नौजिया, शाकिर अली उस्मानी, मनोज दुबे, नसीम अंसारी, विनोद अवस्थी उपस्थित थे।

दुकान में शराब पीने का विरोध किया तो दुकानदार को पीटा

कानपुर। चकेरी में रामादेवी फ्रेंड्स कालोनी में परचून दुकानदार ने इलाके का एक युवक व उसके दो साथियों पर उसकी दुकान में शराब पीने का आरोप लगाया है। दुकानदार के अनुसार मना करने पर आरोपियों ने उससे गाली-गलौज कर मारापीटा। पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। फ्रेंड्स कालोनी निवासी भूपेंद्र चौरसिया उर्फ मंटू के अनुसार उनकी घर के बाहर ही परचून की दुकान है। पीड़ित ने बताया कि 30 जनवरी की रात को वह अपनी दुकान पर बैठे थे। तभी इलाके का यजुवेंद्र सिंह अपने दोस्त रामजी व एक अन्य के साथ दुकान आया और शराब पीने लगा। उन्होंने मना किया तो आरोपी गाली-गलौज करने लगे। विरोध पर पीटना शुरूकर दिया।

सर्विस सेंटर से 37 हजार रुपये चोरी

कानपुर। चकेरी के शिवकटरा में बाइक सर्विस सेंटर का शटर तोड़कर चोर गल्ले में रखा 37 हजार रुपये पार कर ले गए। चोरी का पता चलने पर पीड़ित दुकानदार ने चकेरी थाने में शिकायत की। पुलिस ने चोर की तलाश शुरू की है।

डॉ. हेमंत मोहन को सम्मानित करते पदाधिकारी। अमृत विचार

खिचड़ी का वितरण करते समाजसेवी।

जयंती पर संत रविदास के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया

शहर में कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, झांकियां भी निकाली गईं

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। संत रविदास जयंती पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। झांकियां निकाली गईं और संत रविदास के आदर्शों को अपनाने पर बल दिया गया।

रामादेवी में सामाजिक समरसता सहभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डा. हेमंत मोहन समेत कई लोगों को सम्मानित किया गया। मुख्य वक्ता संजय शुक्ला जी ने कहा कि हम समस्त हिंदुओं को संगठित होना चाहिए अब इसका समय आ गया कार्यक्रम में सनातन धर्म के प्रचारक सिद्धार्थ काशी बार ने कहा कि भारतीय संस्कृति एवं सनातन धर्म का प्रचार यदि हम लोग अपने बच्चों में नहीं करेंगे तो बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे पैदा होगा। कानपुर नगर जिला अध्यक्ष अरुण कुमार शर्मा, काजल किरण, जय शुक्ला, प्रवीण सिंह चंदेल, राघव शुक्ला, विद्याभूषण तिवारी आदि रहे। ईदगाह स्थित संत रविदास मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। मुख्यअतिथि के रूप में राजेंद्र गुप्ता ने रविदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भंडारे का आरंभ किया भंडारे का आयोजन धर्मेंद्र गौतम द्वारा किया गया भंडारे में खीर, हलुआ, वेज बिरियानी का वितरण किया गया। गंगा समग्र के प्रांत प्रमुख प्रांत मीडिया आयाम राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि भगवान रविदास जी ने समाज के उत्थान के लिए उपदेश दिए उनका कहना था सभी मनुष्य ईश्वर की संतान हैं, कोई छोटा-बड़ा नहीं। शरद महेश्वरी, विनय मिश्रा, अमित गौतम, धर्मेंद्र गौतम, राजकुमार राजपूत, संतोष दिक्षित, चांद इमरान हाशमी आदि रहे।

एक्सपो में उत्पाद देखते ग्राहक। अमृत विचार

2 फरवरी तक चलेगी एक्सपो

कानपुर। सिल्क वीव्स एक्सपो का आयोजन शहर में 2 फरवरी तक मोतीझील में होगा। इस एक्सपो में बनारस के घाटों से लेकर बिहार के गांवों तक, बंगाल से तमिलनाडु तक, असम के पहाड़ों और राजस्थान के रेगिस्तानों से 20 से ज़्यादा तरह के सिल्क के परिधान एक ही छत के नीचे हैं। बनारसी, कोसा, जामदानी, भागलपुरी, जयपुरी, असम सिल्क इस एग्जीबिशन की खास पहचान हैं। यहाँ 15 अलग-अलग राज्यों के लगभग 75 स्टॉल हैं। यह इवेंट लाजपत भवन लॉन मोती झील में 2 फरवरी तक सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक हो रहा है।

सिख बच्चों की दस्तारबंदी, सिखी के नियम समझाये

कानपुर। गुरु नानक जी के सातवें स्वरूप साहिब श्री गुरु हरिराय जी महाराज के मनाए जा रहे दो दिवसीय प्रकाश पर्व के कार्यक्रम के दूसरे व अंतिम दिन रविवार को सुबह व शाम गुरमत समागम हुआ। सिख बच्चों की सिखी सिखाने के साथ ही उनकी दस्तारबंदी की गई।

रविवार को गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा ब्लाक-4 गोविन्द नगर की ओर से खालसा कालेज हाल गोविन्द नगर में कार्यक्रम की शुरुआत सुबह सुखमनी साहिब तथा नितनेम के पाठ से हुई। उसके उपरांत रागी जत्थों ने कीर्तन करके संगत को निहाल किया।

मॉब लिंचिंग भारत में हो या बांग्लादेश में, निंदनीय है

कानपुर। कोई भी आतंकवादी इस्लाम का वफादार नहीं हो सकता। हर तरह की आतंकवादी सोच निंदनीय है, चाहे वह कलमा पढ़ने वाला हो या न पढ़ने वाला। मॉब लिंचिंग चाहे भारत में हो या बांग्लादेश में, हर हाल में इंसानियत के खिलाफ है।

रविवार को मदरसा अल-जामिया अल-इस्लामिया अशरफुल मदारिस, गद्दियाना में 36वां सालाना जलसा अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस व जश्न-ए-दस्तारबंदी आयोजित हुआ। इस मौके पर 40 छात्र-छात्राओं को फजीलत, हिफ्ज और किराअत की सनदें (प्रमाणपत्र) दी गईं, साथ ही साफा और जुब्बा पहनाकर दस्तार से नवाजा गया। जलसे की अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफी ने की। मुख्य अतिथि कछौछा शरीफ के शैख-ए-तरीकत मौलाना शाह सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन अशरफी जिलानी ने कहा कि बच्चों में तालीम का शौक पैदा करें और इल्म पर दिल खोलकर खर्च करें। जायस से आए मौलाना शाह सैयद मोहम्मद सलमान अशरफी जिलानी ने कहा कि दहेज की मांग शरीअत में मना है।

लांचिंग के अवसर पर उपस्थित निदेशक आत्माराम खत्री, हीरालाल खत्री, संजय खत्री व प्रहलाद खत्री। अमृत विचार

श्री कृष्ना रतन का ग्रैंड लॉन्च

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। रतन हाउसिंग डेवलपमेंट लिमिटेड की प्रीमियम आवासीय परियोजना श्री कृष्ना रतन की शुरुआत रविवार को हुई। मैनावती मार्ग में हुए आयोजन में शहर के नागरिक, रियल एस्टेट से जुड़े विशेषज्ञ और संभावित खरीदार मौजूद रहे। कार्यक्रम को लोगों से शानदार प्रतिक्रिया मिली।

लॉन्च के दौरान प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में खास उत्साह दिखाया। कंपनी की ओर से बताया गया कि कार्यक्रम के दौरान कई यूनिट्स की बुकिंग हुई। यह भी बताया गया कि कंपनी ने अब तक कानपुर, लखनऊ, एनसीआर, पुणे और गोवा जैसे प्रमुख शहरों में कई सफल आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं को पूरा किया है। परियोजना के बारे में कंपनी के निदेशक संजय खत्री ने कहा कि श्री कृष्ना रतन को आधुनिक परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी का उद्देश्य केवल घर बनाना नहीं, बल्कि लोगों को बेहतर जीवनशैली देना है। श्री कृष्ना रतन परियोजना में 3 बीएचके प्रीमियम फ्लैट्स के साथ-साथ 4 और 5 बीएचके पेंटहाउस की सुविधा उपलब्ध है। प्रोजेक्ट का डिजाइन आधुनिक वास्तुकला पर आधारित है, जिसमें खुली जगह, बेहतर वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी पर विशेष ध्यान दिया गया है। परियोजना में रहने वालों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें क्लबहाउस, स्विमिंग पूल, जिम, योगा डेक, मल्टीपर्पज हॉल, वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के लिए इनडोर और आउटडोर खेल क्षेत्र, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, कम्युनिटी हॉल, हाई-स्पीड लिफ्ट और आधुनिक कार पार्किंग व्यवस्था शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत बनाया गया है।

संत कंवर राम मंदिर में श्रद्धालुओं ने किये दर्शन

कार्यालय संवाददाता, कानपुर

अमृत विचार। सिंधी कालोनी परिसर में नवनिर्मित संत कंवर राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया।

वर्ष 1997 में लच्छी बाई ने पति की स्मृति में भूखंड मंदिर के निर्माण के लिए सिंधी समाज को दान किया था। उक्त भूखंड पर ही मंदिर की स्थापना समाज द्वारा की गई थी। उसी स्थान पर दी ओल्ड सख्खर पंचायत सिंधी समाज ने मंदिर को नए व भव्य रूप में निर्मित कराया है। इसमें साईं झूलेलाल भगवान, सिंधी समाज के पूज्य संत कंवर राम साहिब जी की मूर्ति की स्थापना की गई। यह मंदिर जीर्ण-शीर्ण हो गया था। मंदिर का उद्घाटन शिव शांति आश्रम लखनऊ के संत साईं मोहन जी व संत बीरबल दास आश्रम डबरा के साईं शिवलाल जी महाराज व कानपुर के साईं रमेश लाल ने किया। कार्यक्रम में अध्यक्ष घनश्याम दास छाबड़ा, महामंत्री रवि बदलानी, उपाध्यक्ष अमित खत्री, पार्षद अरविंद यादव, विजय खत्री, अशोक वासवानी, सोनू छाबड़ा, अशोक पमनानी, इंद्रजीत आहूजा, नरेंद्र कालरा, राजेश आहूजा, गौरव बजाज आदि रहे।

संत ने किया संबोधित। अमृत विचार

मंदिर में मौजूद भक्त। अमृत विचार

ट्रेन से कटकर युवक ने दी जान

घाटमपुर। फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के औरंगाबाद कोड़ा निवासी 42 वर्षीय मोहम्मद इमरान ने शनिवार देर रात कानपुर बांदा रेलवे ट्रैक पर स्थित घाटमपुर में ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। युवक ने ट्रेन के आगे कूदने से पहले अपने हाथ में मोबाइल नंबर लिखा, ताकि उसकी पहचान हो सके। यहां से निकल रहे ट्रेन के चालक ने घटना की सूचना स्टेशन मास्टर को दी। स्टेशन मास्टर की सूचना पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने स्टेशन के बाहर का मामला होने के चलते घाटमपुर पुलिस को घटना की सूचना दी। जानकारी मिलते घाटमपुर पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने युवक के हाथ में लिखे मोबाइल नंबर पर कॉल करके युवक की पहचान की, इसके साथ ही परिजनो को घटना की सूचना दी। परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान रह रहा था, वह लोग उसका उपचार करा रहे थे।

चौपाल लगाकर कांग्रेसियों ने लिया मनरेगा बचाने का संकल्प

संवाददाता, घाटमपुर

अमृत विचार। घाटमपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के देशव्यापी अभियान मनरेगा बचाओ संग्राम को जिला कांग्रेस कमेटी कानपुर नगर ग्रामीण ने भी धरातल पर उतारना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला के नेतृत्व में गांव गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर रहे हैं।

घाटमपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पतारा विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरगांव में रविवार को कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित कांग्रेसियों ने चौपाल लगाकर मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को जागरूक किया। इस दौरान कांग्रेस कानपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष संदीप शुक्ला ने कहा की कांग्रेस की यूपीए सरकार ने ग्रामीण अंचलों के लिए रोजगार की गारंटी योजना 2006 में लागू की थी। जिसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने मनरेगा का नाम बदल कर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीरामजी कर दिया है। जिसका बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के अन्तर्गत कांग्रेसियों ने घाटमपुर विधानसभा के पतारा ब्लॉक के दतारी व सरगंवा में किसान मज़दूरों के साथ चौपालें लगाकर संवाद किया। चौपाल की संयोजिका पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष उषा रानी कोरी ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि इस जनांदोलन मे ग्रामीणों की सहभागिता आवश्यक है। आनंद वर्मा, शक्ति पांडेय, अवधेश कमल, मोहम्मद शकील, रामचंद्र सचान मौजूद रहे।

मनरेगा बचाओ चौपाल में बोलते कांग्रेसी नेता। अमृत विचार

छात्रों ने पेश किये रंगारंग कार्यक्रम

घाटमपुर। घाटमपुर के विपाता गुलाब देवी इंटर कॉलेज नौरंगा में विद्यालय का वार्षिक उत्सव एवं स्मृति दिवस का आयोजन किया गया। वहीं विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करके सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। साथ ही विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्र एवं छात्राओं को भी पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची घाटमपुर विधायक सरोज कुरील का विद्यालय परिवार के द्वारा फूलमालाओं के साथ प्रतीक चिह्न देकर कर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप जलाकर किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से स्वर्गीय विपाता गुलाब देवी रानी जी के शिक्षा एवं समाजसेवा के प्रति योगदान को स्मरण किया गया। विद्यालय परिवार द्वारा आयोजित यह आयोजन अनुशासन, संस्कार एवं शिक्षा के महत्व को दर्शाने वाला रहा।

लोडर की टक्कर से बाइक सवार युवक हुआ घायल

संवाददाता, घाटमपुर

- **लोडर में बैठा पल्लेदार डरकर पुल से नीचे कूद गया, उसके दोनों पैर टूटे, अस्पताल में भर्ती**

अमृत विचार। घाटमपुर में ओवरब्रिज पर शनिवार देर रात एक सड़क हादसा हो गया। विपरीत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवार मुनीम को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मचे हंगामे और भीड़ के डर से लोडर में बैठा पल्लेदार पुल से नीचे कूद गया, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए।

घाटमपुर थाना क्षेत्र के कुष्मांडा नगर मोहल्ला निवासी रामकरण (46) जो सजेती स्थित पाण्डेय रोडलाइंस में मुनीम के पद पर काम करता हैं। वह शनिवार देर रात ड्यूटी करके बाइक से घर लौट रहा था, जैसे ही वह घाटमपुर थाना क्षेत्र के कानपुर सागर हाईवे पर नगर स्थित ओवरब्रिज पर पहुंचा तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में रामकरण गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुल पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ का आक्रोश और पुलिस के पकड़े जाने के डर से लोडर में बैठा कुष्मांडा नगर मोहल्ला निवासी 22 वर्षीय पल्लेदार अजीत ने सीधे पुल के ऊपर से छलांग लगा दी। काफी ऊंचाई से गिरने के कारण अजीत को गंभीर चोट आई है।

पुलिस ने दोनों घायलों को एंबुलेंस से घाटमपुर सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर पल्लेदार को गंभीर हालत में कानपुर जिलास्पताल रेफर कर दिया गया।

गाली-गलौज का विरोध करने पर युवक को पीटा

चौबेपुर। क्षेत्र के गौरी लक्खा गांव में बेवजह गाली गलौज का विरोध करने पर पड़ोसी ने युवक को मारपीट कर घायल कर दिया।

गौरी लक्खा गांव निवासी सुनील कुमार ने पुलिस को दिए पत्र में बताया है कि दरवाजे पर उसकी कुछ ईंटें रखी थीं। मवेशियों द्वारा ईंटों का चट्टा ढहा दिए जाने पर कुछ ईंटें पड़ोसी मनोज के दरवाजे पर बिखर गईं। शुक्रवार वह अपनी ईंटें उठा कर रख रहा था। तभी पड़ोस के सूरज पुत्र मनोज ने गाली गलौज की। विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। शोर मचाने पर दौड़े घर के लोगों को देख सूरज जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग निकला। मारपीट से उसके शरीर में गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सीएचसी भेजा। थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

आयोजन | संघ की स्थापना के शताब्दी वर्ष पर हुआ आयोजन, हिंदू जनशक्ति का उमड़ा सैलाब

बिल्हौर के 'हिंदू सम्मेलन' में गूंजा राष्ट्रवाद का स्वर

संवाददाता बिल्हौर

अमृत विचार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर के उपलक्ष्य में बिल्हौर स्थित बापू गेस्ट हाउस में विराट 'हिंदू सम्मेलन' का आयोजन किया गया। इस समागम में हजारों की संख्या में उमड़े हिंदू समाज के जनसैलाब ने राष्ट्र रक्षा और सामाजिक उत्थान का सामूहिक संकल्प लिया।

हिंदू सम्मलेन का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ स्वयंसेवक रामकुमार गुप्ता एवं फर्रुखाबाद विभाग के विभाग प्रचारक राहुल द्वारा भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान वातावरण 'भारत माता की जय' के उद्घोष से गुंजायमान रहा।

मुख्य वक्ता विभाग प्रचारक राहुल ने संघ की 100 वर्षों की विकास यात्रा का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भारत का इतिहास केवल पराजयों का नहीं, बल्कि अनगिनत बलिदानों और संघर्षों की विजय गाथा है।

जब उन्होंने भारत के वीर सपूतों और महापुरुषों के बलिदानों का वर्णन किया, तो कार्यक्रम में उपस्थित माताओं और बहनों की आँखें नम हो गईं। उन्होंने समस्त हिंदू समाज से संघ के 'पंच प्रणों' को अपने जीवन का आधार बनाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि जाति-पाति के भेद को मिटाकर अखंड समाज का निर्माण करना होगा। परिवारों में संस्कारों का बीजारोपण करना होगा। प्रकृति की रक्षा को ईश्वरीय कार्य मानना होगा। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिये स्वदेशी अपनाना होगा। इस अवसर पर पंडित कृष्ण मोहन शास्त्री, रमाकांत कटियार ने भी वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित कराया।

इस विशाल सम्मेलन में जिला प्रचारक धीरेंद्र, सह जिला संघ चालक अवधेश, सेवा प्रमुख संदीप, अर्जुन, हितांशु, उत्कर्ष, बस्ती प्रमुख आशुतोष सहित संघ के तमाम पदाधिकारी, स्वयंसेवक और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सम्मेलन में बोलते वक्ता। अमृत विचार

विराट हिंदू सम्मेलन में मौजूद लोग। अमृत विचार

घाटमपुर में 8 को होगा हिंदू सम्मेलन

- घाटमपुर में आगामी विराट हिन्दू सम्मेलन के आयोजन को लेकर मां कुष्मांडा देवी मंदिर मैदान, घाटमपुर में भूमि पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच सम्पन्न हुए इस भूमि पूजन कार्यक्रम में संत-महात्माओं, पदाधिकारियों एवं धर्मप्रेमी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इस अवसर पर बताया गया कि हिन्दू सम्मेलन समिति, घाटमपुर के तत्वावधान में 8 फरवरी को दोपहर 12 बजे से विराट हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति मुख्य अतिथि के रूप में सहभाग करेंगी। सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में प्रकाश शर्मा पूर्व राष्ट्रीय संयोजक बजरंगदल उपस्थित रहेंगे।

कल्याणपुर को हरा इटर्रा बना विजेता

घाटमपुर। घाटमपुर के ग्राम पंचायत इटर्रा में आयोजित बाबा भटेश्वर क्रिकेट टूर्नामेंट में इटर्रा व कल्याणपुर के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। इटर्रा ने कल्याणपुर को 13 रनों से हरा कर ट्राफी पर कब्जा जमाया। इटर्रा टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 151 रन का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करते हुए कल्याणपुर की टीम 138 रनों पर आउट हो गईं। मैन ऑफ द मैच विशाल को दिया गया। फाइनल मुकाबला टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्य अतिथि पतारा ब्लाक प्रमुख पति अजय सिंह ने फीता काट कर किया। वही समापन घाटमपुर सभासद रोहित सिंह एडी, राम शंकर पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष ललित पांडे, सचिन सचान, नूतन तिवारी अजय, अध्यक्ष टिंकू बाजपेई, अरुण प्रजापति, अनु श्रीवास्तव, चिंकू वर्मा, प्रांशु अवस्थी विनय शर्मा आदि लोग मौजूद रहे।

सामाजिक समरसता की पहचान थे संत रविदास

शिवराजपुर। सपा के विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने कार्यालय में संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर संत रविदास के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके विचारों, कृतित्व और समाज के प्रति किये गए योगदान को साझा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विनय यादव ने कहा कि संत रविदास का जीवन सामाजिक समानता, मानव गरिमा और भेदभाव के विरोध का प्रतीक है। विनय यादव ने कहा कि संत रविदास जी ने जिस समतामूलक समाज की कल्पना की थी, उसे साकार करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान कार्तिकय शुक्ला, वीरेंद्र वर्मा, सुरेश यादव, सुनील यादव, पुरन वर्मा, रोहित राजपूत, रोहित यादव आदि मौजूद रहे।

अमृत विचार

क्लासीफाइड

विज्ञापन हेतु अमृत विचार कार्यालय में सम्पर्क करें

सूचना

मेरे पुत्र दीपक यादव का चाल चलन समाज विरोधी व संदेहजनक हो गया है। समझाने के बाद भी उसमें सुधार नही है। इस कारण से मैने उससे सम्बंध विच्छेद कर अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया। यदि वह किसी से लेनदेन या कोई कृत्य करता है तो वह स्वंय ही जिम्मेदार होगा। उसका परिवार के लोगों से कोई सरोकार नहीं। **सतीश कुमार पुत्र मोहर सिंह निवासी मोहनपुर पोस्ट लरखौर सैंफई इटावा।**

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में मेरा और मेरे पिता का नाम आनंद त्रिपाठी पुत्र रामकृपाल त्रिपाठी दर्ज है जबकि पैन कार्ड में मेरा और मेरे पिता का नाम आनंद तिवारी पुत्र राम कृपाल तिवारी दर्ज है, भविष्य में मेरे और मेरे पिता के नाम को आनंद त्रिपाठी पुत्र राम कृपाल त्रिपाठी समझा व पढ़ा जाए। **आनंद त्रिपाठी पुत्र रामकृपाल त्रिपाठी ग्राम व पो. हाजीपुर जिला अयोध्या**

न्यूज ब्रीफ

मारपीट में कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट

रसूलाबाद। माल का पुरवा में आपसी पारिवारिक मकान के बंटवारे को लेकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को मारा पीटा और फावड़े से हमला करके जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही 24 जनवरी को उसकी दीवार गिरा दी। इस पर घायल ने इसकी रिपोर्ट थाने में सात लोगों के विरुद्ध दर्ज कराई है। प्रमोद कुमार दुबे ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया की पारिवारिक मकान के बंटवारे को लेकर गत 23 जनवरी को परिवार के ही शिवम उर्फ कन्हैया, सत्यनारायण ,पिंकी पत्नी सत्यनारायण ,अवधेश, गोपाल, लवकेश व वीरेंद्र में एक राय होकर उसे मारा पीटा और फावड़े से हमला कर जान से करने की धमकी दी। उसके साथ ही 24 जनवरी को उसके द्वारा बनाई गई दीवाल गिरा दी तब उसकी रिपोर्ट करने थाने आया। थाना प्रभारी सतीश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की रिपोर्ट संबंधित धाराओं में दर्ज कर ली गई है।

कलश यात्रा के साथ यज्ञ शुरू

रसूलाबाद। रविवार को 12 मऊ स्थित श्रीसती जी मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक यज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। इस अवसर पर श्रद्धालु भक्त कलश में जल भरकर कथा पंडाल तक आए जहां आचार्य ने कलश स्थापित करवाएं। इस भागवत कथा के कलश यात्रा में रामनगर ,भारामऊ ,माखन पुरवा, तारानगर भीमसेननगर, हाफिजपुर, गुखुरुआ, रामपुर की महिलाएं व पुरुष शामिल हुए। कलशों में जल भरने का कार्यक्रम आचार्य हरिओम जी दीक्षित एवं संदीप कुमार दीक्षित की देख रेख में संपन्न हुआ। इस मौके पर कथा आयोजक एवं परीक्षित पूर्व प्रधान अरविंद सिंह यादव व उनकी पत्नी सुनीता यादव, श्रीपाल ,रामविलास, सुरेश गुप्ता, महेश गुप्ता ,जितेंद्र सिंह, जगपाल, अवधेश यादव, श्री कृष्ण प्रजापति सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।

पुलिस के हत्थे चढ़ा इनामी बदमाश

कानपुर देहात। जिले की थाना भोगनीपुर पुलिस ने दस हजार रूपए के पुरस्कार घोषित गैंगस्टर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बीती रात मुखबिर की सूचना पर पुरस्कार घोषित आरोपी गौरव कुमार पुत्र स्व कृष्ण कुमार उर्फ स्व कृष्णा कुमार निवासी ग्राम लवरसी कछ्गांव थाना मूसानगर को गिरफ्त में लिया गया। कानपुर झाँसी हाइवे कानपुर की तरफ सर्विस रोड देवीपुर चौराहे के पास थाना भोगनीपुर से उसकी गिरफ्तार हुई। पुलिस ने बताया कि गौरव कुमार केस नंबर 188/2025 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट में पुरस्कार घोषित वांछित अपराधी है।

भागवत में किया गोवर्धन पूजा का वर्णन

सिकंदरा। सिकंदरा तहसील क्षेत्र के ऊमरपुर गांव मे चल रही श्रीमदभागवत कथा के पांचवे दिन आचार्य सौरभ महाराज ने गोवर्धन पूजा की कथा सुनाई। बताया कि जब ब्रजवासी गोवर्धन की पूजा करने लगे, तब इंद्र क्रोधित हो गया और भारी वर्षा करने लगा। तब भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर सात दिनों तक गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को वर्षा से बचाया। इसीलिए उन्हें गोवर्धनधारी कहा जाता है। गोवर्धन पर्वत को स्वयं श्रीकृष्ण का रूप माना जाता है। इस मौके पर कृष्णा शुक्ल, प्रियतम शुक्ला,विमल, कपिल पाल,पुनीत सक्सेना,राजे शुक्ल, विल्सन शुक्ल, विजय ,सुधाकर तिवारी,अंशू तिवारी,टिल्लू राठौर,ओमप्रकाश नारायन, धीरज आदि रहे।

युवती को ले जाने का आरोपी पकड़ा गया

कानपुर देहात। थाना मंगलपुर पुलिस टीम ने महिला संबन्धी अपराध में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। छह जनवरी को वादी ने थाना मंगलपुर पर तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसला कर ले गया है। इसके संबंध में थाना मंगलपुर पर धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आए आरोपी शिवम पुत्र अरविंद कुमार उर्फ गंभीर निवासी ग्राम शहबाजपुर थाना अकबरपुर को रविवार को झींझक के शुलभ शौचालय केंद्र के 100 कदम पहले रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया।

www.amritvichar.com
पर भी खबरें पढ़ें

फैक्ट्री में टिनशेड लगा रहा युवक गिरा, मौत

संवाददाता, रनियां

अमृत विचार: रनियां औद्योगिक क्षेत्र में एक रेलवे पार्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री में रविवार की सुबह रस्सा टूटने से ऊंचाई पर चढ़कर टिनशेड लगा रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन कानपुर के हैलट अस्पताल ले जा रहा थे, रास्ते में मौत हो गई। इसके बाद परिजन रनियां लौट आए और शव फैक्ट्री में रखकर मुआवजे को लेकर हंगामा किया। दोपहर बाद हुए समझौते के बाद पुलिस ने शव को पोस्ट मार्टम के लिए भिजवाया।

फत्तेपुर रोशनाई गांव के मजरा महादेव कुटी निवासी सूरज (22) पुत्र शिव बालक रनियां में संचालित फ्रंटियर फैक्ट्री में काम करता था। रविवार की सुबह काम पर पहुंचा और फैक्ट्री में लगाई जा रही टिनशेड में ऊंचाई पर चढ़कर टीनशेड लगा रहा था। अचानक रस्सा टूट गया और वो नीचे जमीन पर गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी पर पहुंचे परिजन उसे कानपुर के हैलट अस्पताल लेकर जा रहे थे कि तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद वे लोग रनियां लौट आए।

फैक्ट्री में मजदूर की मौत पर हंगामे की सूचना पर नायब तहसीलदार विक्रम पासवान, सीओ सदर संजय कुमार सिंह, इंस्पेक्टर रनियां शिवनारायण सिंह सहित अकबरपुर, गजनेर तथा महिला थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। घटना के बाद पिता, मां मंजू देवी, बहनों अंजलि, शालू, रेनू का रो रोकर बुरा हाल था। लगभग चार घंटे तक शव फैक्ट्री में रखा रहा। इस संबंध में इंस्पेक्टर रनियां ने बताया कि फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से मृतक के पिता को मुआवजे के रूप में बीस लाख रुपये की चेक व अंतिम संस्कार के लिए पचास हजार रुपये की नकद सहायता प्रदान की है। समझौते के बाद शव को पोस्ट मार्टम के लिए भिजवाया गया।

रेलवे के पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री में युवक की मौत के बाद गेट पर बैठीं महिलाएं।

रोजगार के लिए लाठियां खा रहे बेरोजगार

संवाददाता, रसूलाबाद

अमृत विचार: भाजपा सरकार में जैसे हालात हैं ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए। नौजवान व छात्र बेरोजगार हैं। रोजगार के लिए वे लाठियां खा रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है।

यह बात भीतरगांव कुर्सी खेड़ा में विधानसभा क्षेत्र प्रभारी सांसद प्रतिनिधि एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवकुमार बेरिया ने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहीं। उन्होंने सपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कहा कि भाजपा सरकार में सभी समाज के लोगों को अपमानित होना पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे कि हमने युद्ध रुकवा दिया लेकिन भारत के नेता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। विदेश में फर्जी का डंका पीटने की बात हो रही है। लगातार बढ़ रहे टैरिफ से

कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवकुमार बेरिया, मौजूद भीड़। अमृत विचार

● भाजपा सरकार पर बरसे पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवकुमार बेरिया

भारत में महंगाई हो रही है जबकि भारत सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध नहीं कर पा रही। गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है क्योंकि भाजपाई यह जानते हैं कि यदि गरीब का बच्चा पढ़ गया तो वह अपना अधिकार लड़कर ले लेगा। यह चीज ही भाजपा सरकार के लोगों को रास नहीं आ रही।

उन्होंने गांव-गांव जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। जहां एक ओर वे कार्यकर्ताओं की जन समस्याएं सुन रहे हैं वहीं कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भी ला रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष वीर सेन यादव ने कहा कि जोन,सेक्टर और बूथ प्रभारी मेहनत से काम करके नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य करें। याद रखें ग्राउंड पर की गई मेहनत ही आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र बनेगी। सपा जिलाध्यक्ष अरुण कुमार बबलू राजा, पूर्व जिलाध्यक्ष लाखन सिंह यादव, जिला कोषाध्यक्ष गोपाल गुप्ता,जिला उपाध्यक्ष हाजी फैजान खान, धर्मेंद्र त्रिवेदी, सौरभ यादव ,वीरू कुशवाहा आदि मौजूद रहे।

कॉरिडोर की घोषणा से होगा विकास

वकील बोले, कागजों पर विकास, आम लोगों से दूर बजट, भाजपा नेताओं ने जिला कार्यालय में बैठक कर जताई खुशी

कार्यालय संवाददाता,कानपुर देहात

अमृत विचार: रविवार को केंद्र सरकार द्वारा 2026 का बजट पेश किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। कॉन्फ्रेंस हॉल में भाजपा नेताओं ने बजट का लाइव प्रसारण देखा-सुना।

कार्यालय पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि यह बजट आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक है। इसमें नए भारत और विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि स्पष्ट दिखाई देती है.। .आयुष और स्वास्थ्य क्षेत्र पर जोर देना, महिलाओं के लिए हर जनपद में छात्रावास के निर्माण की व्यवस्था, नौजवानों के लिए हर क्षेत्र में अवसर के साथ-साथ अलग-अलग क्षेत्र में रिफॉर्म का बजट पेश किया गया है। भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए ये बजट मददगार साबित होगा। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सतीश शुक्ला ने कहा कि अमेरिका के 50 परसेंट टैरिफ के बावजूद इस बजट में कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया गया है जब कि अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव है। डिजिटल क्षेत्र में सरकार द्वारा बजट में उचित व्यवस्था की गई है। रक्षा क्षेत्र में 15 परसेंट तक बजट बढ़ाया गया है। इसके अलावा बजट में नए रेलवे कॉरिडोर की घोषणा विकास के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगी।

उन्होंने कहा कि बजट में सभी सेक्टरों का ध्यान रखा गया है। जिला अध्यक्ष रेणुका सचान ने कहा कि लेदर कपड़ा सिंथेटिक फुटवियर, विदेशी यात्रा और कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी। कुल मिलाकर यह बजट दूरदर्शी है एवं भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला है। व्यापारी नेता एवं जिला उपाध्यक्ष रामजी मिश्रा ने कहा व्यापारियों के लिए टैक्स भरने में जो गलती होने पर व्यापारियों के लिए जेल का प्रावधान था उसे प्रावधान को खत्म कर दिया गया है यह व्यापारियों के लिए राहत देने वाला होगा। पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान सहित मदन पांडेय, श्याम सिंह सिसोदिया, मलखान सिंह चौहान, सौरभ मिश्रा, केपी सिंह, शिव विलास मिश्रा, विकास मिश्रा जिला मीडिया प्रभारी आदि रहे।

जिला कार्यालय में बजट का प्रस्तुतिकरण देखतीं राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला व अन्य।

सभी के सपने पूरे करने वाला बजट: पाठक

कानपुर देहात। बजट पर विधान परिषद सदस्य अरुण पाठक ने कहा कि इसमें सबका साथ और सबका विकास नीति साफ नजर आई है। प्रतिक्रिया में स्नातक विधायक ने कहा कि बजट युवा वर्ग को समर्पित है। यह वृद्धि और विकास के स्तंभ का द्योतक है। इससे भारत के आर्थिक विकास का रास्ता खुलेगा। इसके अलावा, देश में विनिर्माण की क्षमता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि बजट में दिए गए प्रावधान से दूरगामी संरचनात्मक सुधार होंगे। साथ ही सार्वजनिक निवेश में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित होगी। श्री पाठक ने कहा कि एक लाइन में कहें तो यह सबका साथ सबका विकास और सबके सपनों को पूरा करने वाला बजट है।

अरुण पाठक।

अधिवक्ताओं ने सराहना के साथ की आलोचना

कानपुर देहात: सिविल बार एसोसिएशन अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रीय बजट 2026 पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट की वास्तविक सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब इसके प्रावधान नीति, बजट क्रियान्वयन और जनजीवन के संतुलित असर के रूप में जमीन पर दिखाई दें। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 देश की आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक विकास की दिशा को रेखांकित करता है। इसमें उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को गति देने के प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। फिर भी, आम जीवन पर बजट का ठोस असर अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। युवाओं के रोजगार सृजन, गरीब एवं मध्यम वर्ग की प्रत्यक्ष राहत, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता, कृषि एवं कृषक आय-सुरक्षा, न्यायिक ढांचा, विशेषकर जिला न्यायालय ,इन क्षेत्रों में अपेक्षित परिणाम अभी नहीं दिख रहे। शेयर बाजार और वित्तीय संकेत यह दर्शाते हैं कि निवेशकों और आम जनता का विश्वास अभी पूरी तरह सुदृढ़ नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि देश हित में अपेक्षा और आशा यह है कि आगामी नीतिगत निर्णय इन कमियों को दूर करते हुए बजट को और अधिक जनकेन्द्रित, पारदर्शी और विश्वासपूर्ण बनाएं।

जितेंद्र प्रताप सिंह।

विकासोन्मुख है बजट : प्रदीप पांडेय

दूसरी तरफ, प्रदीप पांडेय शासकीय अधिवक्ता, पूर्व महामंत्री एकीकृत बार कानपुर देहात ने कहा कि बजट विकासोन्मुख है। किसानों, युवाओ व माध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लगातार बढ़ रहे सोने व चांदी के दाम को नियंत्रित करने के लिए कस्टम ड्यूटी में कमी की गई है। हालांकि देश के अधिवक्तावर्ग के लिए कुछ न होने के कारण निराशा भी है।

प्रदीप पांडेय।

उद्यमियों ने देखा देश के आम बजट का सीधा प्रसारण। अमृत विचार

उद्यमियों ने कहा, प्रस्तावित रूपरेखा से मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा

संवाददाता, रनियां

अमृत विचार: आम बजट को लेकर हर वर्ग में तरह-तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। आईआईए भवन में उद्यमियों ने बजट टीवी के सामने बैठकर देखा और इसे रोजगार और विकसित भारत 2047 के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता हुआ बजट बताया।

चेयरमैन पीयूष जैन ने आम बजट के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और कहा कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसमें रुपरेखा तैयार की गई है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर नए सिरे से ज़ोर दिया गया है। प्रमुख घोषणाओं में भारत को एक वैश्विक फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना, पांच वर्षों में बायोफार्मा के लिए 100 बिलियन का आवंटन, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त 400 बिलियन, सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का विकास, कार्बन-उत्सर्जन में कमी कार्यक्रमों के लिए 200 बिलियन, और छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए 100 बिलियन के ग्रोथ फंड की स्थापना शामिल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश गोयल ने कहा कि बजट की घोषणाएं सभी क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था और एमएसएमई के विकास के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। सीए रीना भार्गव ने कहा सीमार्ट को बढ़ावा देना और सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना एक सकारात्मक और सशक्त बनाने वाली पहल है। यहां पर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तरुण खेत्रपाल, सुनील वैश्य, आलोक अग्रवाल राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डिविजनल चेयरमैन कानपुर दिनेश बरसिया, डिविजनल सचिव रोहित बृजपुरिया, कानपुर चैप्टर चेयरमैन आर के अग्रवाल, हर्षल अग्रवाल, विक्रांत अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

कभी अहंकार नहीं करना चाहिए

कार्यालय संवाददाता,कानपुर देहात

अमृत विचार: हम भले बलशाली, वैभवशाली या धनबली हो जाएं लेकिन कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। 100 कौरवों के होते हुए भी सत्य मार्ग पर चलने वाले पांच पांडवों ने पराजित कर दिया था।

यह विचार जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मुलायम सिंह यादव ने ग्राम दुआरी में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के सातवें दिन व्यक्त किए। रविवार को कथा स्थल पर पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने प्रसिद्ध कथा वाचक पंडित मनीष तिवारी को अंगवस्त्र एवं फूल-मालाओं से सम्मानित किया। इसके बाद पंडाल में उपस्थित भक्तों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा मात्र एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। उन्होंने आगे जोर देकर कहा समाज द्वारा बनाए गए नियम गलत हो सकते हैं लेकिन भगवान के बनाए नियम कभी गलत नहीं होते। परमात्मा के नियम लोकहित के लिए होते हैं। इस अवसर पर उनके साथ रमेशचंद्र सिंह गौर, डॉ. आनंद सिंह, सतीश कुमार अग्निहोत्री, नितिन दुबे, शंकर सिंह, अनिल दुबे, गिरजा शंकर दीक्षित, शिवपाल सिंह भदौरिया आदि मौजूद रहे।

कथा वाचक का सम्मान करते एड. मुलायम सिंह यादव।

करंट की चपेट में आने से युवक की थमीं सांसें

कार्यालय संवाददाता,कानपुर देहात

अमृत विचार: मंगलपुर थाना क्षेत्र के मनकापुर गांव निवासी एक युवक गांव में ही मकान की पुताई कर रहा था। इस बीच घर के अंदर लगी केबिल में हुए शॉर्ट-सर्किट से वह करंट की चपेट में आ गया। इस बाद वह ड्रम से नीचे गिर गया। परिजन इलाज के लिए ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मंगलपुर थाना क्षेत्र के मनकापुर गांव निवासी दीपक बाथम उम्र 23 वर्ष मेहनत मजदूरी करते थे। शनिवार की देर शाम वह गांव में ही विनोद सिंह के मकान में पुताई का काम कर रहे थे। इस बीच घर के अंदर लगी केवल कहीं शॉर्ट होने से वह करंट की चपेट में आ गया। उस समय वह ड्रम के ऊपर खड़े होकर पुताई कर रहा था। करंट लगने से वह ड्रम से नीचे गिर गया वहीं सूचना मिलने पर परिजन भी पहुंच गए। मकान मालिक व परिजन इलाज के लिए झींझक सरकारी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

युवक की मौत से मां निर्मला देवी बदहवास हो गई। वहीं पिता बलराम बाथम व भाई सत्येंद्र सहित अन्य परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल था। मृतक का एक भाई जितेंद्र आंध्र प्रदेश में प्राइवेट नौकरी करता है। मृतक की बहन प्रीति व बहनोई मुंबई में रहते है।

दीपक की मृत्यु के बाद शोक में बैठीं महिलाएं। अमृत विचार

कार्यक्रम जयंती पर अकबरपुर में श्रद्धाभाव से याद किए गए संत रविदास

संत रविदास की कल्पना के अनुरूप बनाना होगा समाज

कार्यालय संवाददाता,कानपुर देहात

अमृत विचार: रविवार को नगर पंचायत के शंकर दयाल नगर मोहल्ले में कबीर विद्यालय प्रांगण में महामना संत रविदास जी की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वक्ताओं ने कहा कि पूर्वजों और महापुरुषों की दिखाई राह पर चलना और उनके सदविचारों पर अमल करना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

कार्यक्रम में सभासद निर्लेप भारती के प्रतिनिधि जय कुमार भारती ने कहा कि संत रविदास जी मध्यकालीन भारत के एक महान संत दार्शनिक कवि और समाज सुधारक थे। संत रविदास जी का जन्म 1388 में हुआ था। पिता का नाम संतो राव दास माता का नाम कलसा देवी था। वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में जन्मे रविदास ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से छुआछूत और जातिवाद का कड़ा विरोध किया। उनके 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं।

उन्होंने भगवान बुद्ध के तरह बेगमपुरा नामक एक आदर्श शहर की परिकल्पना की थी जहां पर कोई दुःखी न हो और छुआछूत न हो। सब एक समान हों। रविदास के दोहे, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ों सब सब बसै रैदास रहें प्रसन्न, से बात खत्म की। इस मौके पर सभासद शिव सिंह नायक, सभासद सुनील राजपूत, सरदार प्रमोद सिंह केसावत, सभासद आदेश यादव, हाजी मोहम्मद अबरार, रमेश नायक, संतोष बंजारा आदि रहे।

संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते आयोजक। अमृत विचार

धूमधाम से मनाया पंथा देवी का वार्षिकोत्सव

शिवली। कस्बा शिवली के लंका मैदान स्थित मां पंथा देवी के छठवें वर्षिकोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर रविवार को सुंदरकांड पाठ एवं सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया गया। हवन पूजन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। वार्षिकोत्सव अवसर पर माता रानी समेत सभी देवी देवताओं का भव्य श्रृंगार किया गया। भंडारे में बड़ी संख्य में भक्तगणों ने प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी मनोज तिवारी का कहना है कि कभी बियावान जंगल में मौजूद माता रानी का मंदिर आज कस्बा एवं क्षेत्र वासियों के आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंदिर के पुजारी बाबा मनोज तिवारी, चंद्र कुमार मिश्रा, मुन्ना यादव, टीटू गुप्ता, विजय शंकर आदि रहे।

भंडारे में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

संवाददाता,रसूलाबाद

अमृत विचार: अखंड ब्रह्मचारी नारायण स्वरूप जी महाराज की पावन पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नार खास स्थित नारदाश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण की।

कार्यक्रम प्रतिवर्ष बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर माघी पूर्णिमा तक चलता है। जिसमें नव दिवशीय श्री राम कथा का आयोजन होता है इस वर्ष वृंदावन धाम से पधारे धनंजय दास जी ने लोगों को राम कथा सुनाई। इसके साथ ही यज्ञ हुआ एवं गौ सेवा का महत्व लोगों को बताया गया। बताते चलें कि वर्ष 1996 4 फरवरी माघी पूर्णिमा को अखंड ब्रह्मचारी नारायण स्वरूप ब्रह्मचारी जी ने गोलोक प्रयाण किया था। उनकी पुण्यतिथि पर तब से अब तक लगातार माघी पूर्णिमा को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है।

भंडारे में महाप्रसादी ग्रहण करते श्रद्धालु। अमृत विचार

उसी क्रम में इस वर्ष भी बसंत पंचमी से प्रारंभ हुई नव दिवसीय राम कथा के उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें आए श्रद्धालु शिष्यों ने महा प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर अन्य उपस्थित लोगों में श्याम शरण दास जी,पवन तिवारी, रामजी तिवारी,गोपाल दीक्षित, देव कुमारी, शिवकांत, सुनंदा जी, अविनाश तिवारी, सुदीप तिवारी, मंगलम, तेजू अवस्थी, अनंदीलाल अवस्थी, छानू तिवारी, बउवा सिंह गौर , विजय , रामचंद्र सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

अमृत विचार

सोमवार, 2 फरवरी 2026

सपने को साकार होने से रोकने वाली एकमात्र चीज है- असफलता का भय।

-पाउलो कोएल्हो, ब्राजीलियन लेखक

संप्रभुता पर सख्त

देश के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा यह स्पष्ट कहना कि तथाकथित 'चिकन नेक' भारत की भूमि है और इस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक गंभीर रणनीतिक संकेत है। बयान बताता है कि केंद्र सरकार 22 किलोमीटर चौड़ी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को लेकर अत्यंत सतर्क और इसकी रक्षा के लिS आक्रामक रुख रखती है। 'चिकन नेक' पूर्वोत्तर भारत को शेष देश से जोड़ने वाली एकमात्र स्थलीय कड़ी है। इसके पश्चिम में नेपाल, पूर्व में बांग्लादेश और उत्तर में भूटान तथा चीन का प्रभाव क्षेत्र है। यदि इस संकरी पट्टी की सुरक्षा में कोई व्यवधान आता है, तो आठ पूर्वोत्तर राज्यों की भौगोलिक और सामरिक निरंतरता पर प्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। इस दृष्टि से इसे रणनीतिक संप्रभुता का मामला माना जाना चाहिए।

गृहमंत्री ने यह भी संकेत दिया कि दिल्ली में कुछ तत्वों ने इस कॉरिडोर को 'काट देने' जैसे नारे लगाए थे। उनके बयान पर केंद्र की कड़ी प्रतिक्रिया यह संदेश देती है कि राष्ट्रीय एकता और भौगोलिक अखंडता पर कोई भी सार्वजनिक उकसावा अब सहन नहीं किया जाएगा और राजनीतिक विमर्श की आड़ में सामरिक संवेदनशीलता को हल्के में लेने वालों के साथ सख्त रवैया अपनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में सरकार बनते ही सीमा पर बाड़ लगाने की घोषणा भी इसी व्यापक सुरक्षा दृष्टिकोण का हिस्सा है। जहां भूमि संबंधी विवाद हैं, वहां केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, हलांकि केवल भूमि का मुद्दा ही बाधा नहीं है; तकनीकी सर्वेक्षण, सीमा निर्धारण के अंतर्राष्ट्रीय समझौते और स्थानीय विरोध भी प्रक्रिया को धीमा करते हैं। असल में सीमा प्रबंधन में भूमि अधिग्रहण, स्थानीय प्रशासन का सहयोग, पर्यावरणीय स्वीकृतियां तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रोटोकॉल जैसे जटिल पहलू शामिल होते हैं। कई स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा भूमि उपलब्ध कराने में देरी एक व्यावहारिक बाधा रही है, पर यह पूरी कहानी नहीं है। नदियां, आबादी का घनत्व, तस्करी की चुनौतियां और सीमा पर रहने वाले नागरिकों के आजीविका संबंधी प्रश्न भी बाड़बंदी को जटिल बनाते हैं। इसलिए दूसरी सीमाओं, विशेषकर कुछ हिस्सों में भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमा पर भी पूर्ण बाड़बंदी अभी बाकी है।

भाजपा पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं आती तो भी बाड़ तो लगेगी, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा किसी एक दल के शासन पर निर्भर नहीं हो सकती। संवैधानिक ढांचे के भीतर केंद्र सरकार के पास सीमा सुरक्षा के पर्याप्त अधिकार हैं। किंतु प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार का सहयोग अनिवार्य होता है। बेहतर समाधान यह होगा कि इसे चुनावी मुद्दा बनाने के बजाय सर्वदलीय सहमति और केंद्र–राज्य समन्वय के जरिए आगे बढ़ाया जाए। गृहमंत्री का बयान केवल चुनावी आरोप-प्रत्यारोप नहीं माना जाना चाहिए। यह उस बदलते सुरक्षा वातावरण की स्वीकृति है, जिसमें हाइब्रिड युद्ध, सूचना युद्ध और आंतरिक अस्थिरता के प्रयास समान रूप से गंभीर खतरे हैं। 'चिकन नेक' केवल एक भूगोल नहीं, भारत की पूर्वोत्तर नीति, 'एक्ट ईस्ट' रणनीति और सामरिक आत्मविश्वास का प्रतीक है, इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक शोर से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय सुरक्षा के ठोस, संस्थागत और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना समय की मांग है।

प्रसंगवश

एक संन्यासी ने हजारों आंखों में भर दी रोशनी

पंजाब के एक छोटे से गांव से निकले एक साधारण युवक ने संन्यास का मार्ग चुना और राजस्थान में पहुंच कर भक्ति के साथ जन सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उसने अपने तप, त्याग व करुणा से हजारों लोगों की जिंदगी में उजाला भर दिया। वह युवक संत स्वामी ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है। गणतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार ने उन्हें पदमश्री प्रदान देने की घोषणा की है। उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं बल्कि उस विचारधारा पर मुहर है, जिसमें सेवा को साधना और मानवता को धर्म माना जाता है।

पंजाब के मोगा जिले की निहाल सिंह वाला तहसील में एक छोटा सा गांव है- रौंता। इस गांव से एक दिन एक युवक निकला, लेकिन उसने दुनिया से कुछ पाने का नहीं बल्कि दुनिया को कुछ लौटाने का रास्ता चुना। यह युवक आगे चलकर स्वामी ब्रह्मदेव के नाम से विख्यात हुआ। स्वामी ब्रह्मदेव ने संन्यास लिया, लेकिन समाज से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने पीड़ित मानवता की पीड़ा को देखा। उन्होंने 1963 में जब अमृतसर में श्री दुर्ग्याना मंदिर में अंध विद्यालय को देखा तो ऐसा ही कोई काम करने का संकल्प किया।

अमरपाल सिंह वर्मा

वरिष्ठ पत्रकार

अपनी शिक्षा पूर्ण कर वह 1978 में राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक मंदिर में आए। यहीं से शुरू हुई श्री जगदंबा अंध विद्यालय की कहानी। शुरुआत बहुत साधारण थी। कोई बड़ी इमारत नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं। थे तो बस कुछ अच्छे लोग और स्वामी जी का अटूट भरोसा। जन सहयोग से रोपा गया एक छोटा सा पौधा। किसी ने नहीं सोचा था कि यही पौधा एक दिन वटवृक्ष बन जाएगा।

वर्ष 1980 में उन्होंने जगदंबा अंध विद्यालय की आधारशिला रखी। जगदंबा अंध विद्यालय की शुरुआत केवल एक बच्चे और एक शिक्षक के साथ हुई थी, लेकिन आज वह वटवृक्ष बन चुका है। बीते साढ़े चार दशकों में उन्होंने सात हजार से ज्यादा दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षित किया है। मूक-बधिर बच्चों के लिए चार दशक से स्कूल भी चल रहा है। स्वामी ब्रह्मदेव ने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं, बल्कि उन्हें जीना भी सिखाया। नेत्रहीन और मूक-बधिर बच्चों के हाथ में हुनर दिया, साथ में आत्म विश्वास भी दिया। आज उस विद्यालय से पढ़े अनेक बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं।

स्वामी जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं, जो जन्म से अंधे नहीं हैं, बस आर्थिक संकट के कारण इलाज नहीं करा पाए। यहीं से शुरू हुआ मोतियाबिंद ऑपरेशन का काम। वर्ष 1993 में स्थापित श्री जगदंबा आई हॉस्पीटल में अब तक साढ़े चार लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर उनकी आंखों की रोशनी बचाई जा चुकी है। साढ़े चार लाख का यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं है। यह साढ़े चार लाख घरों में लौटी उम्मीद है। स्वामी ब्रह्मदेव ने समाज को एक और गहरी बात सिखाई है, वह है मरणोपरांत नेत्रदान। उन्होंने लोगों को समझाया कि मौत के बाद भी किसी की जिंदगी रोशन की जा सकती है। धीरे-धीरे यह बात लोगों के दिलों में उतरती गई। सालों से संस्था के जरिए नेत्रदान करा कर जरूरतमंदों को नेत्र प्रत्यारोपित किए जाते हैं।

स्वामी ब्रह्मदेव का जीवन दिखावे से दूर रहा है। वह कथा-कीर्तन करते हैं, चढ़ावे में आया धन सेवा में लगा देते हैं। न कोई शोर, न कोई प्रचार। वही सादा वेश, वही सरल बोलचाल। वे खुद संस्था में मौजूद रहते हैं, काम देखते हैं, लोगों से मिलते हैं। उनके लिए सेवा कोई परियोजना नहीं है, जीवन का स्वभाव है। पदमश्री मिलने के बाद भी उन्होंने श्रेय खुद नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान प्रभु की कृपा और जनता के निःस्वार्थ सहयोग का प्रतिफल है।

आम बजट 2026 विकास व अनुशासन का संतुलन

रजत मेहरोत्रा

वित्तीय एवं आर्थिक विशेषज्ञ

केंद्रीय बजट 2026-27 केवल सरकार का हिसाब-किताब नहीं, बल्कि यह बताता है कि आने वाले समय में देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। दुनिया में व्यापार तनाव, तकनीकी बदलाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच सरकार ने इस बजट में विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को संतुलित करने की कोशिश की है। सरकार ने पूंजीगत खर्च बढ़ाकर लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपये किया है और यह लक्ष्य रखा है कि देश का कुल कर्ज (Debt/GDP) अनुपात को बजट अनुमान 2026-27 में GDP के 55.6 % के रूप में आंका गया है, जबकि संशोधित अनुमान 2025-26 में यह 56.1% था। Debt-to-GDP अनुपात में गिरावट का अर्थ है कि समय के साथ सरकार को ब्याज भुगतान पर कम खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि सरकार खर्च भी करेगी और कर्ज को भी नियंत्रण में रखेगी।

बजट में राजकोषीय घाटा लगभग 4.3% ऑफ जीडीपी के स्तर पर रखने का लक्ष्य रखा है, क्योंकि इससे देश की आर्थिक सेहत मजबूत होती है। जब सरकार का घाटा घटता है, तो उसे कम उधार लेना पड़ता है और ब्याज पर होने वाला खर्च भी कम होता है। इसका सीधा फायदा यह होता है कि सरकार के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी क्षेत्रों पर खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचता है। घाटा कम होने से महंगाई पर भी दबाव घटता है। इसके अलावा, जब फिस्कल डेफिसिट नियंत्रण में रहता है, तो विदेशी निवेशकों और रेटिंग एजेंसियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ता है, जिससे देश में निवेश आता है और रुपया भी मजबूत रहता है। कुल मिलाकर, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट घटाने का उद्देश्य केवल हिसाब संतुलित करना नहीं है, बल्कि भविष्य में विकास के लिए स्थायी और भरोसेमंद आर्थिक आधार तैयार करना है।

कृषि क्षेत्र के लिए बजट को आय स्थिरता व जोखिम प्रबंधन का बजट कहा जा सकता है। सिंचाई परियोजनाओं, कृषि अवसंरचना और वेयर हाउसिंग नेटवर्क के विस्तार से फसल नुकसान कम होगा और किसानों को बेहतर कीमत मिल सकेगी। एग्री-लॉजिस्टिक्स और कोल्ड-चेन पर निवेश बढ़ाकर कृषि उत्पादों की बर्बादी घटाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल एग्री प्लेटफॉर्म और फसल बीमा कवरेज के विस्तार से किसानों की आय में स्थिरता आएगी। कृषि-आधारित एमएसएमई और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवर्धन और रोजगार दोनों बढ़ाने की रणनीति अपनाई गई है।

छात्रों और युवा शक्ति के लिए यह बजट 'शिक्षा से रोजगार' की कड़ी को मजबूत करता है। डिजिटल शिक्षा अवसंरचना, स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक लैब तथा उद्योग से जुड़े कौशल कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है। शिक्षा और मेडिकल शिक्षा से जुड़े टीसीएस प्रावधानों को घटाकर 2% किए जाने से विदेश में अध्ययन करने वाले मध्यम वर्गीय छात्रों को सीधी राहत मिलेगी। इसका उद्देश्य केवल डिग्री उत्पादन नहीं, बल्कि रोजगार योग्य युवा तैयार करना है, ताकि जनसंख्या लाभांश वास्तविक आर्थिक शक्ति बन सके। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बजट में केंद्रीय स्थान मिला है। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को सस्ते ऋण, बीमा और डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने से महिलाओं की भागीदारी औपचारिक अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट 2026 संजीवनी जैसा है। सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का एमएसएमई ग्रोथ फंड घोषित किया है, जिससे छोटे उद्योगों को सस्ता ऋण और विस्तार का अवसर मिलेगा। यह क्षेत्र देश में 11 करोड़ से अधिक रोजगार देता है, इसलिए इसमें निवेश सीधे रोजगार सृजन से जुड़ा है। एमएसएमई के डिजिटलीकरण और निर्यात क्षमता बढ़ाने से भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकेगा। कपड़ा और टेक्सटाइल उद्योग के लिए बजट ने पूरी वैल्यू चेन- फाइबर से फैशन तक को मजबूत करने का रोडमैप दिया है। नई नेशनल फाइबर स्कीम से उत्पादन लागत घटेगी और गुणवत्ता बढ़ेगी। भारत का टेक्सटाइल निर्यात पहले ही लगभग 40 अरब डॉलर के स्तर पर है और इस नीति से इसमें और वृद्धि की संभावना बनेगी। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा। इससे पलायन कम होगा।

सरकार ने सात नए रेल कॉरिडोर और टियर-2 शहरों पर फोकस की घोषणा की है। इससे लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी। उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा। रेलवे में निवेश का गुणक प्रभाव स्टील, सीमेंट और निर्माण उद्योग पर पड़ता है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन संभव है। आईटी, एआई और डेटा सेंटर नीति बजट 2026 की सबसे रणनीतिक घोषणाओं में से एक है। सरकार ने एआई के लिए 'पिक एंड शोवेल' अप्रोच अपनाई है यानी सीधे एप्लिकेशन पर नहीं, बल्कि अवसंरचना पर निवेश। विदेशी कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करने पर 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने की घोषणा की गई है, बशर्ते वे भारतीय रीसेलर्स का उपयोग करें। इससे भारत ग्लोबल डेटा हब बनने की दिशा में बढ़ेगा और आईटी सेक्टर में उच्च-मूल्य रोजगार सृजित होंगे।

स्वास्थ्य और बायो-फार्मा सेक्टर को बजट में नई ऊर्जा मिली है। अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये की 'बायोफार्मा शक्ति' पहल से अनुसंधान, विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। मेडिकल टूरिज्म, आयुष केंद्र, डायग्नोस्टिक सेवाओं और पोस्ट-केयर सुविधाओं के विस्तार से भारत वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभर सकता है। वर्तमान में मेडिकल टूरिज्म बाजार लगभग 9-10 अरब डॉलर का है, जिसे कई गुना बढ़ाने की क्षमता इस नीति में है। रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर रणनीति बजट 2026 का सबसे भू-रणनीतिक पक्ष है। सरकार ने रेयर अर्थ खनिजों के घरेलू उत्पादन, प्रोसेसिंग और वैल्यू-चेन विकास के लिए विशेष आवंटन किया है।

दुनिया में व्यापार तनाव, तकनीकी बदलाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के बीच सरकार ने इस बजट में विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को संतुलित करने की कोशिश की है।

आमने

खुद के ऊपर 14-14 मुकदमे हैं। उनमें जमानत करा लें। उनको सेटल करा लें सरकार से हाथ-जोड़ी करके। पौने तीन साल बाद में कांग्रेस की सरकार आ रही है। मदन दिलावर जी से मिलने जेल में मैं जाऊंगा। गोविंद डोटासरा तो यहीं रहेगा। कहीं नहीं जाएगा।

-गोविंद सिंह डोटासरा
कांग्रेस नेता, राजस्थान

सामने

कांग्रेस सरकार के दौरान मिड-डे मील योजना में करीब दो हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। जांच की आंच उन 'मगरमच्छों' तक पहुंचेगी, जिन्होंने जनता की कमाई पर डाका डाला। भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का जाल बिछ चुका है।

-मदन दिलावर
शिक्षा मंत्री
राजस्थान सरकार

सुप्रीम फैसले से प्राइवेट स्कूलों में बराबरी की बात

रोहित माहेश्वरी

स्वतंत्र पत्रकार

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अब हर प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। यानी अगर आपके पास साधन नहीं हैं, फिर भी आपका बच्चा महंगे प्राइवेट स्कूल में मुफ्त पढ़ाई कर सकता है। हाल ही में शिक्षा के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम और दूरगामी फैसला सामने आया है। अदालत ने साफ कहा है कि सच्चा बंधुत्व तभी संभव है, जब समाज के हर वर्ग के बच्चे एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में साथ पढ़ें। इसी सोच को मजबूत करते हुए शीर्ष अदालत ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्राइवेट और गैर-सरकारी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत मुफ्त सीटें सुनिश्चित करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में गरीब बच्चों को प्रवेश देना 'एक राष्ट्रीय मिशन होना चाहिए।'

आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार कानून, पहली अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसके तहत छह से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत यह हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अधिकार को आसान भाषा में समझने की कोशिश करें, तो इसमें कोई भी स्कूल बच्चे को दाखिला देने से मना नही कर सकता है। हर 60 बच्चों पर कम से कम दो प्रशिक्षित अध्यापकों का होना अनिवार्य है। हर तीन किलोमीटर के अंदर स्कूल होना जरूरी हैं। राईट टू एजुकेशन पर होने वाले खर्चों का 55 प्रतिशत केंद्र और 45 प्रतिशत राज्य सरकार उठाती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, देश के स्कूल शिक्षा तंत्र में 24.8 करोड़ से अधिक छात्र नामांकित हैं और प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर 96.9 फीसदी से ऊपर पहुंच गई है।

कोर्ट ने कहा कि कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों का दाखिला केवल कागज़ी अधिकार नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को स्पष्ट नियम बनाने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से जुड़े इस मामले में याचिकाकर्ता दिनेश बीवाजी अष्टिकर ने आरोप लगाया कि उनके बच्चों को पड़ोस के निजी स्कूल में 25 फीसदी कोटे के तहत दाखिला नहीं मिला। आरटीआई से सामने आया कि सीटें खाली थीं, फिर भी स्कूल ने जवाब नहीं दिया। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए राहत नहीं दी कि ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वर्षों की देरी के कारण बच्चों को समय पर राहत मिलना संभव नहीं रहा। इसके बावजूद अदालत ने इसे 'नज़ीर तय करने वाला' मामला मानते हुए व्यापक दिशा-निर्देश देने का फैसला किया। कोर्ट ने माना कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, भाषा की बाधा, डिजिटल अशिक्षा और जानकारी की कमी के कारण गरीब परिवारों के लिए 25 फीसदी कोटे तक पहुंचना आज भी मुश्किल है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पड़ोस के स्कूलों में दाखिला केवल सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम है।

अदालत ने यह याद दिलाया कि निजी स्कूलों में वंचित वर्ग के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना कोई अलग कल्याणकारी योजना नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 (ए) और 39 (एफ) में निहित बाल विकास और बंधुत्व के सिद्धांतों को लागू करने का जरिया है। शीर्ष अदालत का कहना था कि आरटीई कानून सभी बच्चों को जाति, वर्ग, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के बिना एक ही स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा देने की बात करता है।

अदालत ने कोठारी आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसमें कॉमन स्कूल सिस्टम पर जोर दिया गया था, जहां पर समाज के हर वर्ग के बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा मिल सके। संविधान के भाईचारे का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है, जब एक रिक्शा खींचने वाले का बच्चा, एक करोड़पति या सुप्रीम कोर्ट के जज के बच्चे के साथ एक ही स्कूल में पढ़े। शीर्ष अदालत के इस फैसले को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संवैधानिक भावना को जमीन पर उतारने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य सलाहकार परिषदों से सलाह लेकर, धारा 12(1)(सी) के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक नियम और कानून तैयार करें और जारी करें। कोर्ट ने आगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियम और कानून जारी करने की जानकारी इकट्ठा करें और 31 मार्च तक कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई छह अप्रैल को होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सच्चा बंधुत्व तभी संभव है, जब समाज के हर वर्ग के बच्चे एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में साथ पढ़ें।

सोशल फोरम

जिगर और नातिया मुशायरा

अजमेर में एक नातिया मुशायरा था। आयोजकों के सामने बड़ी मुश्किल थी कि जिगर मुरादाबादी को इस मुशायरे में कैसे बुलाया जाए। वे खुले रिंद (शराब पीने वाले) थे। नातिया मुशायरे में उनकी शिरकत आसान नहीं थी। आयोजकों में कुछ उनके हक़ में थे, कुछ खिलाफ़। आख़िर बहुत सोच-विचार के बाद आयोजकों ने फैसला किया कि जिगर को दावत दी जानी चाहिए। जब जिगर को बुलाया गया तो वे सिर से पांव तक कांप उठे।

हिस्ट्री अनफोल्ड

ब्लॉगर

'मैं गुनहगार, रिंद, सियाहकार, बदनसीब—और नातिया मुशायरा! नहीं साहब, नहीं।'

अब आयोजकों के सामने यह समस्या थी कि जिगर साहब को कैसे तैयार किया जाए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों से इनकार। आख़िरकार असगर गोंडवी ने हुक्म दिया और जिगर ख़ामोश हो गए। सिरहाने बोतल रखी थी, उसे कहीं छिपा दिया। दोस्तों से कह दिया कि कोई उनके सामने शराब का नाम तक न ले। यह मौक़ा मिला है तो मुझे इसे खोना नहीं चाहिए। शायद यह मेरी बख्शीश की शुरुआत हो। एक दिन गुज़रा, दो दिन गुज़र गए। नात के मज़मून सोचते थे और ग़ज़ल कहने लगते थे। सोचते रहे, लिखते रहे, काटते रहे, लिखे हुए को काट-काट कर थकते रहे। आख़िर एक दिन नात का मतला हो गया।

फिर एक शेर हुआ, फिर तो जैसे बारिश-ए-अनवार हो गई। नात मुकम्मल हुई तो उन्होंने सज्द-ए-शुक्र अदा किया। मुशायरे के लिए इस तरह रवाना हुए जैसे हज को जा रहे हों। उन्होंने कई दिनों से शराब नहीं पी थी, लेकिन हलक़ सूखा नहीं था। इधर तो यह हाल था, दूसरी तरफ़ मुशायरा-गाह के बाहर और शहर के चौराहों पर विरोध में पोस्टर लग गए थे कि एक शराबी से नात क्यों पढ़वाई जा रही है। आख़िर मुशायरे की रात आ गई। जिगर को बड़ी सुरक्षा के साथ मुशायरे में पहुंचा दिया गया। मंच से आवाज़ उभरी- 'रईस-उल-मुतग़ज़्ज़लीन हज़रत जिगर मुरादाबादी!'

इस एलान के साथ ही एक शोर उठ खड़ा हुआ। जिगर ने बड़े धैर्य के साथ मजमे की ओर देखा और प्रेम से भरे स्वर में बोले, 'आप लोग मुझे हूट कर रहे हैं, या रसूल पाक की नात को, जिसे पढ़ने की सआदत मुझे मिलने वाली है और जिसे सुनने की सआदत से आप अपने आप को महरूम करना चाहते हैं?'

शोर को जैसे सांप सूंघ गया। बस यही वह विराम था, जब जिगर के टूटे हुए दिल से यह आवाज़ निकली-

एक रिंद है और मद्हत-ए-सुल्तान-ए-मदीना
हां, कोई नज़र-ए-रहमत-ए-सुल्तान-ए-मदीना

-फेसबुक वॉल से

सामयिकी

बेटियों का कागजी कवच और सामाजिक बेड़ियां

बेटियां घर की रौनक होती हैं। समाज की शक्ति होती हैं और राष्ट्र की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिर भी देश की बेटियां समान अवसर, सुरक्षा एवं लैंगिक समानता की उपेक्षा का बोझ ढो रही हैं। सरकार ने बेटियों के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां और कानून बनाए हैं, जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला आरक्षण विधेयक, पास्को एक्ट, घरेलू हिंसा से सुरक्षा कानून और अन्य कल्याणकारी योजनाएं, जिनके माध्यम से बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और कानूनी अधिकार प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। इन योजनाओं से कुछ सकारात्मक बदलाव भी दिखे हैं।

फिर भी, जमीनी हकीकत आज भी बहुत नहीं बदली है। सामाजिक सुरक्षा के अभाव में लड़कियों की उन्नति दिखावा मात्र है। जिस समाज में हर रोज कोई लड़की या महिला बलात्कार का शिकार होती हो, उस समाज को प्रगतिशील कहना, दोगलापन है। राष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, देश में प्रतिदिन 81 रेप के पुलिस केस दर्ज होते हैं। ये तो बस आंकड़े हैं, अधिकतर घटनाएं तो लोक-लाज के डर से परिवार और समाज द्वारा छिपा लिए जाते हैं।

अंबिका अंबी

लेखिका

जहां एक तरफ लड़कियों के लिए समान अवसरों की बातें तो बोली जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ घरेलू जिम्मेदारियां लड़कियों पर ही लाद दी जाती हैं। आज भी लड़कियों को खुद के सपने चुनने का अधिकार नहीं है और न ही स्वतंत्रता से कहीं आने-जाने की छूट ही मिलती है। साथ ही, रसोई और घरेलू कामों का बोझ शुरू से ही उनके कंधों पर डाल दिया जाता है।

वास्तविकता में, लड़कियों को स्वतंत्रता और समान अवसर की सुविधाएं केवल मौखिक एवं कागजी स्तर पर ही सीमित रही है। वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार, भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा कम है। घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ इतना भारी है कि शिक्षा में आगे होने के बावजूद कई लड़कियां नौकरी या आगे की पढ़ाई छोड़ देती हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता, लैंगिक भेदभाव, असुरक्षा की भावना और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसी चुनौतियां हर कदम पर उन्हें कमजोर करती हैं। आज भी लाखों लड़कियां शिक्षा और नौकरी के अवसरों से वंचित रह जाती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है, सामाजिक एवं पारिवारिक सहयोग का प्राप्त न होना।

डिजिटल युग में साइबर हिंसा और ऑनलाइन उत्पीड़न ने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। खुले आम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनके चरित्र पर उंगलियां उठाई जाती हैं और गालियां दी जा रही हैं। यह हिंसा न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महिलाओं की गरिमा और मानसिक स्वास्थ्य को चोट पहुंचाती हैं, बल्कि उन्हें ऑनलाइन स्पेस से दूर रहने, अपनी राय व्यक्त न करने या डिजिटल दुनिया से कट जाने पर मजबूर करने की साजिश है। यह क्रूर सच्चाई है कि जहां इंटरनेट ने महिलाओं को आवाज दी, शिक्षा दी और अवसर दिए, वहीं इस प्लेटफॉर्म का उनके खिलाफ दुरुपयोग हो रहा है।

लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए बचपन से ही शिक्षा और घर-समुदाय स्तर पर हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। सही मायने में, देश की बेटियों की वास्तविक प्रगति तब होगी, जब कानून और योजनाएं सिर्फ घोषणाएं न रहें, बल्कि समाज की सोच बदलने, जमीनी सुरक्षा सुनिश्चित करने, घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ बांटने और हर बेटी को बराबरी का हक दिलाने में सक्षम बनें। हमारे देश को 'बेटी बचाव, बेटी पढ़ाओ' नारे की अपेक्षा 'समाज और परिवार में बेटियों के प्रति भेदभाव मिटाओ' नारे की ज्यादा ही जरूरत है।

स्वामी-रुहेलखंड इंटरप्राइजेज के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक त्रिनाथ शुक्ला द्वारा प्लाट नं.-42, निकट बद्री नगर,इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज, लखनऊ-226008 (उ.प्र.) से मुद्रित एवं 117/एल/320-ए, नवीन नगर काकादेव, कानपुर नगर 208001 (उ.प्र.) से प्रकाशित। **संपादक- राजेश श्रीनेत, कार्यकारी संपादक- दिग्विजय सिंह***
0512-2548300 (कार्यालय), ईमेल- editorschoice@amritvichar.com, आर.एन.आई नं0-UPHIN/2022/85730 *इस अंक में प्रकाशित समाचार के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत उत्तरदायी।(नोट-सभी विवादों का न्यायक्षेत्र कानपुर होगा)।

कार खरीदना कुछ लोगों के लिए बुनियादी जरूरत है, तो कुछ लोगों के लिए शानो-शौकत और रुतबे का प्रतीक, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों के लिए यह हमेशा से एक सपने के सच होने जैसा है। कार आज हम सभी के घरों का एक जरूरी और अहम हिस्सा बन चुकी है। इस मांग की वजह से ही हाल के वर्षों में पुरानी कारें खरीदने का चलन तेजी से बढ़ा है और देश में पुरानी कारों का बाजार एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है। यह तब हुआ है, जब लोगों को भरोसा हुआ है कि पुरानी कारें भी नई कारों जितनी ही अच्छी हो सकती हैं। एक और वजह यह भी है कि पसंदीदा नई कारें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, ऐसे में कम बजट में बेहतर ब्रांड, शानदार फीचर्स की उपलब्धता भी पुरानी कारों की मांग को शहरों से लेकर कस्बों तक आगे बढ़ा रही है। हालांकि काफी सारे लोग पुरानी कार खरीदने में जोखिम और धोखाधड़ी के कारण बचते हैं, लेकिन पुरानी कारों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने के बाद से चीजें काफी आसान भी हो गई हैं।

-मनोज त्रिपाठी, कानपुर

नई कार स्टेटस देती पुरानी कार समझदारी

पुरानी कारों की बिक्री नई कारों से ज्यादा

भारत में पुरानी कारों की बिक्री नई कारों की तुलना में 8 से 10 फीसदी सालाना वृद्धि दर से बढ़ रही है। वर्तमान में प्रत्येक नई कार की बिक्री पर लगभग 1.4 पुरानी कारें बेची जा रही हैं। मौजूदा आंकड़ों के अनुसार साल 2026 के अंत तक भारत में इस्तेमाल की गई कारों की बिक्री 75 लाख यूनिट्स तक पहुंचने का अनुमान है। यही नहीं इस साल देश में पुरानी कारों का बाजार 3.4 लाख करोड़ से अधिक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि पुरानी कारों के बाजार में हिस्सेदारी की बात करें, तो अभी भी सिक्का स्थानीय डीलरों और ब्रोकर का चलता है, जो बाजार के लगभग 68 फीसदी हिस्से पर काबिज हैं, लेकिन ग्राहकों का भरोसा अब वारंटी और सर्टिफाइड कारों के कारण तेजी से संगठित क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो रहा है। इस बदलाव से डिजिटल माध्यमों से होने वाली पुरानी कारों की बिक्री की हिस्सेदारी इस साल के अंत तक करीब 30 फीसदी पहुंचने की उम्मीद है।

मारुति, टाटा, महिंद्रा के साथ ऑनलाइन स्टार्टअप्स ने जीता यूज्ड कार का भरोसा

पुरानी कारों के संगठित कारोबार में मारुति सुजुकी True Value, महिंद्रा First Choice और टाटा मोटर्स Assured जैसे निर्माताओं के साथ Cars24, Spinny, CarDekho और Droom जैसे बड़े खिलाड़ियों के साथ और भी अनेक ऑनलाइन स्टार्टअप्स शामिल हैं। ये सभी सर्टिफाइड गाड़ियां खोजने, टेस्ट ड्राइव बुक करने और पूरी लेनदेन प्रक्रिया में मदद के अलावा अधिकतर कार के मूल्यांकन और कागजी कार्रवाई में भी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे पुरानी कार खरीदना आसान हो जाता है। इनमें Cars24 को पुरानी कारों की खरीद-बिक्री के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आप कार का मूल्यांकन, टेस्ट ड्राइव और पूरी कागजी कार्रवाई जैसे आरसी ट्रांसफर, लोन आदि में मदद पा सकते हैं। Spinny भी एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है, जो सर्टिफाइड और अच्छी क्वॉलिटी वाली पुरानी कारों को आसान और सुरक्षित तरीके से खरीदने का बेहतर अनुभव प्रदान कर रहा है। CarDekho पुरानी और नई दोनों तरह की कारों की पूरी जानकारी जैसे मॉडल, कीमत और माइलेज जैसी डिटेल्स प्रदान करता है। इसके मुकाबले Droom ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहां आप विभिन्न कारों की तुलना कर सकते हैं और कई विकल्प देख सकते हैं। इसी कड़ी में CarWale भी एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है, जहां आपको पुरानी और नई कारों के ढेर सारे विकल्प मिलते हैं। इनके अतिरिक्त OLX भी पुरानी कारें खरीदने और बेचने के लिए लोकप्रिय ऐप है, जिसमें आप सीधे विक्रेता से संपर्क कर सकते हैं।

इसलिए बढ़ रहा है पुरानी कारों का बाजार

देश में हर साल लाखों लोग पहली बार कार खरीदते हैं और उनमें से बड़ी संख्या सेकेंड हैंड या यूज्ड कार को प्राथमिकता देती है। इसके पीछे कारण हैं-

- नई कारों की बढ़ती कीमतें
- कम डाउन पेमेंट और आसान फाइनेंस
- डेप्रिसिएशन का कम झटका
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती विश्वसनीयता
- सर्टिफाइड प्री-ओन्ड कार प्रोग्राम्स

इन कारों की मांग सबसे अधिक

बाजार के ट्रेंड पर नजर डालें, तो हैचबैक मारुति स्विफ्ट, वैगनआर, ग्रैंड आई-10 और सेडान में होंडा सिटी, मारुति सियाज, इसी तरह एसयूवी में क्रेटा, ब्रेजा, डस्टर आदि 5 से 7 साल पुरानी, कम चली और अच्छी तरह मेंटेंड कारें सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं।

खरीदने से पहले जरूरी बातें

- सबसे पहले अपना बजट बनाएं,फिर यह देखें कि पुरानी कार फर्स्ट हैंड है या फिर उसके पहले भी कई ऑनर रह चुके हैं। ऐसी कार लेना हमेशा बेहतर होता है, जो कम किलोमीटर चली हो। भारत में, एक कार औसतन सालाना 6 हजार से 12 हजार किलोमीटर चलती है। यह जरूरी है कि आप सर्विस रिकॉर्ड और गाड़ी की पूरी स्थिति के अनुसार चलाए गए किलोमीटर की जांच करें।
- आरसी, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जांच करें। ओडोमीटर रीडिंग और सर्विस हिस्ट्री मिलाएं। कार को दिन की रोशनी में ध्यान से देखें।
- टेस्ट ड्राइव जरूर लें, आवाज, ब्रेक, गियर पर ध्यान दें। किसी अच्छे मैकेनिक से पूरा इंस्पेक्शन करवा लें। इंश्योरेंस ट्रांसफर की प्रक्रिया ठीक से समझें।

ऑनलाइन या ऑफलाइन कहां से खरीदें

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म : ज्यादा विकल्प, पारदर्शी कीमत
- डीलरशिप : भरोसेमंद लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा
- डायरेक्ट ऑनर : सस्ता सौदा, पर जोखिम ज्यादा

Hero Vida Dirt.E K3 : बच्चों के रोमांच को मिली इलेक्ट्रिक उड़ान

बदलते समय के साथ बच्चों की दुनिया भी स्मार्ट और टेक-फ्रेंडली हो रही है। इसी कड़ी में Hero MotoCorp की इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने भारत में बच्चों के लिए एक अनोखी और सुरक्षित इलेक्ट्रिक डर्ट बाइक Dirt.EK3 पेश की है। यह बाइक न सिर्फ खेल-खेल में राइडिंग का मजा देती है, बल्कि सुरक्षा और सीखने, दोनों का पूरा ध्यान रखती है।

दमदार बैटरी

Dirt.EK3 में 360 Wh की रिमूवेबल बैटरी और 500W मोटर दी गई है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी टॉप स्पीड 25 किमी प्रति घंटा तक सीमित रखी गई है। बैटरी महज 2 घंटे में 20% से 80% तक चार्ज हो जाती है और एक बार चार्ज करने पर 2 से 3 घंटे तक राइड का मजा देती है। तीन राइडिंग मोड- Beginner, Amateur और Pro, बच्चों को धीरे-धीरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर देते हैं।

सुरक्षा और स्मार्ट फीचर्स

Vida ने सेफ्टी के मामले में कोई समझौता नहीं किया है। बाइक में मैग्नेटिक किल स्विच, चेस्ट पैड, ब्रेक रोटर कवर और रियर ग्रैबरेल जैसे फीचर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि एक मोबाइल ऐप के जरिए माता-पिता बच्चे की राइडिंग एक्टिविटी पर नजर रख सकते हैं, स्पीड लिमिट सेट कर सकते हैं और अन्य पैरामीटर्स नियंत्रित कर सकते हैं।

इंटरनेशनल पहचान

Dirt.E K3 का डिजाइन सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। इसे Red Dot Award 2025 दिया गया है, जो इसकी क्वालिटी और इनोवेशन का प्रमाण है। कुल मिलाकर, Hero Vida Dirt.EK3 बच्चों के लिए एक ऐसा इलेक्ट्रिक राइडिंग अनुभव लेकर आई है, जहां रोमांच, सीख और सुरक्षा तीनों का खूबसूरत संतुलन देखने को मिलता है।

कीमत और उपलब्धता

Vida Dirt.EK3 की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 69,990 रखी गई है। पहले 300 यूनिट्स इसी कीमत पर उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे यह बच्चों के लिए एक प्रीमियम, लेकिन समझदारी भरा विकल्प बनती है। इसकी बिक्री 12 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है।

बच्चे के साथ 'बढ़ने' वाली बाइक

इस बाइक की सबसे खास बात है इसका एडजस्टेबल डिजाइन। व्हीलबेस और सस्पेंशन को तीन लेवल- Small, Medium और High पर सेट किया जा सकता है। यानी जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा, बाइक भी उसके कद और उम्र के अनुसार ढलती जाएगी। इससे माता-पिता को हर कुछ साल में नई बाइक खरीदने की चिंता नहीं रहती।

मॉय फर्स्ट राइड

सासू मां के साथ मेरी आगे बढ़ने की यात्रा

जीवन में कुछ यात्राएं सड़कों पर तय होती हैं और कुछ हमारे मन और सोच के भीतर। मेरी कार सीखने की यात्रा भी ऐसी ही एक यात्रा रही, जो केवल ड्राइविंग सीखने तक सीमित नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और बदलाव को अपनाने की कहानी बन गई।

2024 में जब मेरी शादी तय हुई, तब तक मैं कार चलाना नहीं जानती थी। मायके में इसकी कभी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ी थी, इसलिए यह कौशल मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया, लेकिन शादी के बाद ससुराल का वातावरण अलग था। यहां मेरी सासू मां और ननद दोनों कार चलाती थीं। घर से जुड़ा अधिकांश काम-चाहे फैक्ट्री जाना हो, कच्चा माल लाना हो या बाजार की खरीदारी-कार से ही पूरा होता था। ऐसे में मुझे यह समझ में आने लगा कि अब मुझे भी इस जिम्मेदारी में हाथ बंटाना होगा।

कार सीखने का निर्णय लेना आसान था, लेकिन उसे सीखने की प्रक्रिया उतनी सरल नहीं थी। पहली बार स्टीयरिंग पकड़ते समय हाथ कांप रहे थे। सड़क पर निकलते ही मन में डर और असमंजस बना रहता था। ब्रेक, एक्सेलरेटर और क्लच के बीच तालमेल बैठाने में समय लगा। कई बार छोटी-छोटी गलतियां हुईं, लेकिन हर बार सासू मां ने धैर्य और अपनापन दिखाया। उनका विश्वास और सहयोग मेरे लिए सबसे बड़ा संबल बना।

धीरे-धीरे अभ्यास बढ़ा और डर कम होने लगा। सुबह की खाली सड़कों से शुरुआत हुई, फिर मोहल्ले की गलियों से होते हुए मैं मुख्य सड़क तक पहुंच पाई। समय के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। आज मैं अपनी सासू मां के साथ फैक्ट्री के कामों के लिए जाती हूं और बाजार की जिम्मेदारियां भी निभाती हूं। अब कार मेरे लिए केवल एक साधन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहचान बन गई है।

इस पूरी यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। परिस्थितियां जब बदलती हैं, तो हमें भी अपने भीतर बदलाव लाना पड़ता है। परिवार का सहयोग और विश्वास किसी भी नई शुरुआत को आसान बना देता है। सासू मां के साथ मेरा रिश्ता इस दौरान और भी गहरा हुआ, क्योंकि हमने साथ-साथ सीखने और आगे बढ़ने का अनुभव साझा किया।

आज जब मैं कार चलाती हूं, तो मुझे सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की जल्दी नहीं होती, बल्कि उस सफर का आनंद भी मिलता है, जिसने मुझे आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनाया। मेरी कार सीखने की यात्रा वास्तव में मेरे नए जीवन की दिशा तय करने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा बन चुकी है।

-अपर्णा, कानपुर

काम की बात

सर्दियों में क्यों 'नखरे' दिखाती है बाइक ?

सर्दियों की सुबह बाइक सवारों के लिए अक्सर एक परीक्षा बन जाती है। तापमान गिरते ही कई बाइक्स सेल्फ और किक दोनों पर सुस्त प्रतिक्रिया देने लगती हैं। बार-बार कोशिशों के बाद भी इंजन का स्टार्ट न होना न केवल समय की बर्बादी करता है, बल्कि बाइक की मैकेनिकल सेहत पर भी असर डालता है। ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ठंड में बाइक स्टार्टिंग की समस्या पूरी तरह तकनीकी है और सही समझ के साथ इसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है।

ठंड का बाइक पर असर

कम तापमान में इंजन ऑयल गाढ़ा हो जाता है, जिससे क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को घूमने में अधिक प्रतिरोध झेलना पड़ता है। दूसरी ओर, लेड-एसिड बैटरी की केमिकल रिएक्शन क्षमता ठंड में कमजोर हो जाती है, जिससे सेल्फ स्टार्ट का आउटपुट घट जाता है। यही कारण है कि सर्दियों में सुबह के समय बाइक स्टार्ट होने में दिक्कत करती है, जिससे बाइक सवार को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, खासकर उन वाहनों में जिनका मेंटेनेंस नियमित नहीं होता।

स्टार्टिंग समस्या से निपटने के स्मार्ट तरीके

- **स्पार्क प्लग की भूमिका अहम-** ठंड और नमी के कारण स्पार्क प्लग पर कार्बन डिपॉजिट या नमी जमा हो सकती है, जिससे स्पार्क कमजोर पड़ जाता है। यदि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले स्पार्क प्लग की जांच जरूरी है। प्लग को साफकर दोबारा फिट करने से करंट फ्लो बेहतर होता है और इंजन आसानी से जान पकड़ता है।
- **क्लच ट्रिक से घटेगा लोड-** सर्दियों में गियरबॉक्स ऑयल भी गाढ़ा हो जाता है। बाइक को न्यूट्रल में रखकर क्लच पूरी तरह दबाने से गियरबॉक्स इंजन से अलग हो जाता है। इससे किक मारते समय इंजन पर कम लोड पड़ता है और स्टार्टिंग आसान हो जाती है।
- **चोक का सही और सीमित उपयोग-** कार्बोरेटर वाली बाइक्स में चोक ठंडे इंजन के लिए बेहद उपयोगी है। चोक खींचने से एयर-फ्यूल मिक्सचर रिच हो जाता है, जिससे इंजन जल्दी स्टार्ट होता है। हालांकि इंजन चालू होने के 20-30 सेकंड बाद चोक बंद कर देना चाहिए, वरना फ्यूल कंजम्पशन बढ़ सकता है।
- **इग्निशन ऑफ रखकर प्री-किक तकनीक-** ऑटो मैकेनिक्स के अनुसार, इग्निशन बंद रखकर 3-4 बार खाली किक मारने से सिलेंडर के भीतर गाढ़ा ऑयल फैल जाता है। इससे इंजन के मूविंग पार्ट्स लुब्रिकेट हो जाते हैं और स्टार्टिंग के समय कम प्रतिरोध पैदा होता है।
- **लगातार फेल स्टार्टिंग का नुकसान-** बार-बार सेल्फ मारने से बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती है और स्टार्ट मोटर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वहीं, ठंडे इंजन को जबरदस्ती स्टार्ट करने से पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट पर अनावश्यक घर्षण बढ़ता है, जिससे लंबे समय में इंजन की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है।
- **एक्सपर्ट्स की मेंटेनेंस सलाह-** ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों में बाइक को खुले में खड़ा करने से बचना चाहिए। कवर का इस्तेमाल बैटरी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को नमी से सुरक्षित रखता है। साथ ही मौसम के अनुसार सही ग्रेड का इंजन ऑयल और समय-समय पर बैटरी हेल्थ चेक करना बेहद जरूरी है।
- **आने वाला कल-** ऑटो इंडस्ट्री ठंडे मौसम के लिए बेहतर बैटरी टेक्नोलॉजी और लो-विस्कोसिटी इंजन ऑयल पर काम कर रही है। जब तक ये तकनीकें आम नहीं होतीं, तब तक सही ड्राइविंग हैबिट्स और बेसिक मेंटेनेंस से सर्दियों में बाइक स्टार्टिंग की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

अमृत विचार
कानपुर, सोमवार, 2 फरवरी 2026
उन्नाव

माघ पूर्णिमा पर हर-हर गंगे के उद्घोष से गूंज उठे गंगा तट

प्रातःकाल से ही घाटों पर उमड़ पड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, तटों व घरों में सत्यनारायण की कथा सुनी गई, दान-दक्षिणा देकर आस्थावानों ने कमाया पुण्य

संवाददाता शुक्लागंज (उन्नाव)

अमृत विचार: माघ पूर्णिमा के दौरान रविवार को गंगा तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने पतित पावनी मां गंगा में डुबकी लगा कर तटों पर भगवान सत्यनारायन की कथा सुनी। वहीं घरों और मंदिरों में भी भगवान विष्णु की पूजा व कथा का श्रवण किया गया। सुबह से लेकर दोपहर बाद तक गंगा तटों पर हर हर गंगे के उद्घोष से गुजते रहे।

गंगा स्नान के दौरान उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ● अमृत विचार

माघ मास की पूर्णिमा स्नान के दौरान नगर व ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में नगर के आनंद घाट और जाजमऊ चंदन घाट में स्नानर्थियों की भारी भीड़ उमड़ी। कुछ श्रद्धालु एक दिन पहले से ही गंगाघाट क्षेत्र आ गये और रात को ही स्नान करने के लिये घाटों पर आ गये थे लेकिन तड़के पांच बजे से ही घाटों पर स्नान का क्रम शुरू हो गया जो दोपहर तक चलता रहा। माघ पूर्णिमा के अवसर पर गंगा तटों पर श्रद्धालुओं ने भागवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इसलिये घरों में भी प्रभु सत्यनारायण की कथा सुनी गई। गंगा के तटों पर भी कथा सुनने वालों की भीड़ लगी रही। माघ पूर्णिमा कि मान्यता है कि इस दिन दान-पुण्य करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और हनुमान जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं सुरक्षा को लेकर घाटों पर पुलिस फोर्स तैनात रहा। वहीं कोतवाली प्रभारी अजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही नावें, नाविक और गोताखोर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैनात रहे।

माघ पूर्णिमा पर नानामऊ गंगा तट पर हजारों ने लगाई आस्था की डुबकी

बांगरमऊ: माघ पूर्णिमा के पावन पर्व पर रविवार को नानामऊ गंगा तट पर श्रद्धा और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। भीषण शीतलहर के बावजूद हजारों श्रद्धालुओं ने मां गंगा की पावन धारा में आस्था की डुबकी लगाई और पूजन-अर्चन किया। क्षेत्र में यह मान्यता है कि जहा कार्तिक पूर्णिमा पर बिठूर घाट का महत्व है, वहीं माघ पूर्णिमा पर स्नान और दान के लिए नानामऊ गंगा घाट का विशेष स्थान है। तड़के से ही कानपुर, हरदोई और लखनऊ समेत कई जिलों से श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। गंगा स्नान के पश्चात श्रद्धालुओं ने तट पर ही श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण किया और अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न व धन का दान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मेले का मुख्य आकर्षण गंगा की रेती पर श्रद्धालुओं द्वारा बनाया गया पारंपरिक भोजन रहा। दूर-दराज से आए परिवारों ने गोबर के कंडों की आग सुलगाकर चोखा-बाटी, खिचड़ी और तहरी तैयार की। भगवान को भोग लगाने के बाद सभी ने सामूहिक रूप से प्रसाद ग्रहण किया, जिससे पूरा तट एक उत्सव के माहौल में रंगा नजर आया। गंगा तट पर आयोजित मेले में बच्चों ने चाट-पकौड़ों और झूलों का आनंद लिया, तो वहीं महिलाओं ने श्रृंगार सामग्री की जमकर खरीदारी की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अखिलेश चंद्र पांडेय के नेतृत्व में पुलिस बल चप्पे-चप्पे पर तैनात रहा। तहसील प्रशासन ने करीब एक दर्जन राजस्व कर्मियों को व्यवस्था संभालने के लिए तैनात किया।

न्यूज ब्रीफ

साहू समाज की बैठक में मां कर्मा बाई जयंती पर हुई चर्चा

संवाददाता शुक्लागंज (उन्नाव)

अमृत विचार : रविवार को ऋषि नगर स्थित अध्यक्ष सुनील साहू के निवास पर साहू समाज की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में मां कर्मा बाई जी की जयंती मनाने को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर रामजी गुप्ता ने बताया कि होली मिलन समारोह के दौरान समाज के शिक्षित व योग्य युवाओं के साथ बुजुर्गों को भी सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी से सहयोग की अपील की गई। बैठक में अजय साहू, रामकरण साहू, जयपाल साहू, कैलाश साहू, रोहित साहू, मोनू साबू, महेश गुप्ता, अनिल साहू, फरीराम साहू सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

सड़क हादसे में विक्षिप्त युवक की मौत

उन्नाव, अमृत विचार : अजगैन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर रविवार सुबह एक सड़क हादसा हो गया। नवाबगंज कस्बे के पास नहर मोड़ पर एक अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी। जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रविवार सुबह जब कोहरे और धुंध के बीच तेज रफ्तार वाहन ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। वाहन चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच कर शव को कब्जे में लिया। नवाबगंज चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रहा था, जिसे पिछले कुछ दिनों से राजमार्ग के आसपास घूमते हुए देखा गया था।

सड़क हादसे में दो की मौत व पांच घायल

कार्यालय संवाददाता उन्नाव

● दो ट्रकों के बीच पिसी ईको कार फंसना बना हादसे की वजह

अमृत विचार: अजगैन थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिचपरी गांव के पास लखनऊ-कानपुर राजमार्ग पर अयोध्या से दर्शन कर मथुरा लौट रहे श्रद्धालुओं की ईको कार दो ट्रकों के बीच फंस गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 10 फीट लंबी कार सिमट कर महज 2 फीट के लोहे के मलबे में तब्दील हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो मासूम बच्चों और एक महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं इलाज के दौरान एक बच्चे की भी मौत हो गई।

मथुरा जिले के थाना गोवर्धन के ग्राम अडींग निवासी खजेन्द्र पंडित (40) अपने साथियों और परिजनों के साथ 29 जनवरी को प्रयागराज और अयोध्या दर्शन के लिए निकले थे। 31 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद सभी ईको कार से वापस मथुरा लौट रहे थे। हादसा उस वक्त हुआ जब बिचपरी गांव के पास सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से ईको कार पीछे से टकरा गई। अभी चालक कुछ संभल पाता, तभी पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। दो ट्रकों के बीच दबने से कार पूरी तरह पिचक गई। मौके पर पहुंचे लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पास के गैराज से कटर और औजार मंगाकर कार की बॉडी को कटवाया, जिसके बाद करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला जा सका। हादसे के बाद सभी को सीएचसी नवाबगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने खजेन्द्र पंडित को मृत घोषित कर दिया। वहीं, अन्य घायलों निशा देवी, मासूम जितेन्द्र (9), पूनम (12), राजा पचौरी, शंकर सैनी और चालक ओमप्रकाश को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भेजा गया। फिर वहां से कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां महिला और दोनों बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इलाज के दौरान जितेन्द्र की भी मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों ट्रक चालक मौके से भाग निकले। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात युवक की मौत

संवाददाता शुक्लागंज (उन्नाव) **अमृत विचार :** गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के गोपीनाथपुरम के सामने रविवार सुबह रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अप लाइन पर पोल संख्या 66/11 और 66/13 के बीच करीब 22 वर्षीय युवक का शव पेट्रोलिंग कर रहे प्वाइंटमैन आदित्य ने देखा। उन्होंने इसकी सूचना गंगाघाट रेलवे स्टेशन मास्टर और आरपीएफ को दी। आरपीएफ ने मेमो के माध्यम से गंगाघाट कोतवाली पुलिस को अवगत कराया। सूचना पर पश्चिमी चौकी इंचार्ज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने से पूर्व 72 घंटे तक पहचान के इंतजार में उन्नाव मोर्चरी में रखवाया है।

नेपाल से मुंबई तक के क्रिएटर्स का संगम

संवाददाता, उन्नाव

● सोशल मीडिया के दिग्गजों का किया गया सम्मान

अमृत विचार: शहर के एक होटल में रविवार को टर्बो इवेंट्स की ओर से आयोजित टॉप 25 नेशनल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड क्रिएटर्स अवार्ड 2026 में देश के विभिन्न राज्यों और शहरों से आए प्रतिभाशाली डिजिटल क्रिएटर्स को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भानु मिश्रा एवं कार्यक्रम संरक्षक शैलेन्द्र शुक्ला ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। जिसके बाद मंच पर प्रतिभाओं के सम्मान का सिलसिला शुरू हुआ। समारोह में मनोरंजन, फिटनेस और सोशल अवेयरनेस जैसे क्षेत्रों में प्रभाव डालने वाले क्रिएटर्स को नवाजा गया। नेपाल से सोनी राणा और मुंबई से निर्भय शुक्ला आकर्षण का केंद्र रहे। लखीमपुर से जूनियर ऋषि कपूर, लखनऊ से प्रहलाद जैक्स, एंकर जैन, एलेक्स जुहैब, शिवम कुमार और मशहूर जोमैटो वाला शायर व चाय वाला शायर को सम्मानित किया गया। कानपुर से फिटनेस सेलिब्रिटी करण कपूर, डॉ. मीत कमल और उन्नाव से रुचि सिंह, रौनक तिवारी, आरजे कामरान, पुनीत शुक्ला अवधि पॉडकास्ट एवं गंगा पारी बकैत टीम सेवेंजर्स को बेस्ट इन्फ्लुएंसर अवार्ड से नवाजा गया।

परिचय : कार्यक्रम में सम्मानित हुए क्रिएटर्स के साथ आयोजक। ● अमृत विचार

हाईकोर्ट के आदेश पर संग्रह अमीन को मिलेगी पेंशन

कार्यालय संवाददाता उन्नाव, अमृत विचार : सदर तहसील से वर्ष 2019 में सेवानिवृत्त हुए संग्रह अमीन दिलीप कुमार अवस्थी को पेंशन भुगतान का मार्ग प्रशस्त हो गया है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने उनके पेंशन भुगतान के आदेश जारी कर दिए हैं। राजकीय पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स संघर्ष समिति के संरक्षक के.के. मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दो सप्ताह के भीतर दिलीप कुमार अवस्थी के खाते में पेंशन की धनराशि पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार तहसील सफीपुर के संग्रह अमीन की वर्ष 2012 में सेवारत मृत्यु के बाद उनकी पत्नी रजनी गौड़ को पारिवारिक पेंशन नहीं मिल पा रही थी। इस मामले में उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका पर आदेश मिलने के बाद कुछ माह पूर्व जिलाधिकारी के निर्देश पर उन्हें भी पारिवारिक पेंशन उपलब्ध करा दी गई है। के.के. मिश्रा ने बताया कि जनपद में सेवानिवृत्त अथवा मृत संग्रह अमीनों एवं संग्रह अनुसेवकों को पेंशन न मिलने के प्रकरणों की जांच के लिए जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी कृति राज की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की है। समिति से 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। इसकी दो बैठकें 21 और 27 जनवरी को हो चुकी हैं। जिलाधिकारी की इस पहल से जनपद के पेंशनरों में खुशी का माहौल है और उनके प्रति सम्मान की भावना बढ़ी है।

पीडी नगर में दो सड़कों का लोकार्पण

उन्नाव, अमृत विचार : नगर पालिका परिषद् द्वारा रविवार को वार्ड 18 पीडी नगर में दो विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता भानू मिश्रा ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद नवनिर्मित नाली एवं इंटरलॉकिंग सड़कों का उद्घाटन कर उन्हें जनता को समर्पित किया। लोकार्पण कार्यक्रम के पहले चरण में पीडी नगर स्थित पॉवर हाउस के सामने दुर्गेश ट्रेडिंग से सौरभ पटेल के आवास तक नवनिर्मित इंटरलॉकिंग सड़क व नाली का उद्घाटन किया गया। लंबे समय से क्षेत्रवासी इस मार्ग की बदहाली से परेशान थे। वही दूसरे में अन्नू सिंह के आवास से आशु सिंह के आवास होते हुए चौहान ट्रेडर्स तक नवनिर्मित मार्ग का लोकार्पण हुआ। अध्यक्ष श्वेता भानू मिश्रा ने कहा नगर के प्रत्येक वार्ड में बुनियादी ढांचा मजबूत करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम जनहित के कार्यों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।

रविदास जयंती पर जगह-जगह हुए कार्यक्रम

संवाददाता शुक्लागंज (उन्नाव)

अमृत विचार: रविवार को संत शिरोमणि रविदास की 649वीं जयंती नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में मनाई गई। इसके साथ ही पंचशील बौद्ध विहार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसके बाद प्रसाद बांटा गया। इसके साथ ही रविदास पार्क में भी कार्यक्रम आयोजित किये गये।

पंचशील बौद्ध विहार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूरन दादा ने रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के साथ ही माल्यार्पण कर पूजा वंदना की। इस दौरान समिति के अध्यक्ष राजेन्द्र गौतम ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास ने दलितों के प्रति समाज की विचारधारा को बदलने की दिशा में जो कार्य किया उसी की वजह से आज दलितों को समाज में स्थान मिला है। उनके कहे वचन 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वहीं तहरी वितरण भी किया गया। इसके साथ ही इंद्रा नगर में रविदास पार्क स्थित रविदास जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किये गये। जिसके बाद खीर का प्रसाद बांटा गया। इस मौके पर संतराम, रमाकांत, पुत्तन लाल, अमन गौतम, मुकेश गौतम, केडी बाबू, देवीचरण, एमएल कुरील, श्याम बिहारी, अजय पाल, रेखा गौतम, मालती गौतम, राजकुमारी गौतम, माधुरी, संगम देवी मौजूद रहे।

रविदास जयंती पर माल्यार्पण संस्थान के पदाधिकारी। ● अमृत विचार

'दीप-मन की देहरी पर' पुस्तक का विमोचन

संवाददाता शुक्लागंज (उन्नाव) **अमृत विचार :** रविवार को गंगा नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में कवयित्री दीपिका पटेल के काव्य संग्रह 'दीप-मन की देहरी पर' का भव्य विमोचन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन दीपिका पटेल एवं रवि वर्मा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन व पुष्पार्चन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त आईएएस अनुराग पटेल (कानपुर नगर) ने अध्यक्ष व विशिष्ट अतिथियों के साथ पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक राकेश कुमार ने की। विशिष्ट अतिथियों में राम सुमेर सिंह एडवोकेट (पूर्व अध्यक्ष, उन्नाव बार एसोसिएशन), डॉ. राजीव मिश्रा (संपादक व कवि), मदन सिंह, मुख्य वक्ता डॉ. अनुपम सिंह, कवि अनिल वर्मा, डॉ. रामनरेश व आदित्य कटियार शामिल रहे। लेखिका ने कहा कि पुस्तकें समाज में ज्ञान व विचारों के आदान-प्रदान का सशक्त माध्यम हैं। डॉ. राजीव मिश्रा ने काव्य पाठ से समां बांधा। संचालन साहिल ने प्रभावी ढंग से किया। समारोह में बड़ी संख्या में साहित्यप्रेमी उपस्थित रहे।

पुस्तक का विमोचन करते मुख्य अतिथि।

हनुमंत धाम में सवामनी हवनोत्सव में झूमे भक्त

संवाददाता शुक्लागंज (उन्नाव) **अमृत विचार :** पोनी रोड श्रीनगर स्थित उच्च प्राथमिक जूनियर स्कूल रामलीला मैदान के पास बने हनुमंत धाम श्री संकट मोचन बालाजी मंदिर में रविवार को सवामनी हवनोत्सव एवं विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और बाबा बालाजी का मनमोहक श्रृंगार किया गया। दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर में 25 जनवरी से चल रहे धार्मिक अनुष्ठानों के क्रम में रविवार को विशेष पूजन, हवन और भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ। भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ भजनों पर झूमते हुए बाबा के जयकारे लगाए। सुबह 11 बजे से हवन एवं सुंदरकांड पाठ संपन्न हुआ, जबकि शाम को आयोजित विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान विनोद महाराज, पुरुषोत्तम अवस्थी, राजकुमार अवस्थी, राजकुमार निषाद, श्रीकांत पांडेय, शिवम सिंह, अनुराग बाजपेई, पप्पू सोनकर, संजय पांडेय, मोनू पांडेय सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया।

सजाया गया बाबा का दरबार। ● अमृत विचार

34 केंद्रों पर हुईं इंटर की प्रयोगात्मक परीक्षा

कार्यालय संवाददाता उन्नाव

अमृत विचार: माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की इंटरमीडिएट कक्षाओं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं रविवार को जनपद के 34 इंटर कॉलेजों में संपन्न हुईं। वहीं 178 विद्यालयों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, भूगोल सहित अन्य विषयों की सभी प्रयोगात्मक परीक्षाएं पूरी कर ली गईं।

जनपद के कुल 208 विद्यालयों के छात्र-छात्राओं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं निर्धारित थीं। इनमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, भूगोल, व्यावसायिक ट्रेड व सिलाई आदि विषय शामिल रहे। कंट्रोल प्रभारी रामचंद्र सिंह ने बताया कि 34 केंद्रों पर रविवार को परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुईं, जबकि 30 केंद्र ऐसे हैं जहां कुछ विषयों की परीक्षाएं अभी शेष हैं। गृह विज्ञान के परीक्षक के अनुपस्थित रहने के कारण कई विद्यालयों में परीक्षा नहीं हो सकी। संबंधित प्रधानाचार्यों ने बताया कि परीक्षकों से संपर्क का प्रयास किया जा रहा है। कुछ परीक्षक अन्य विद्यालयों में परीक्षा ले रहे हैं, जहां से कार्य समाप्त होने के बाद वे शेष विद्यालयों में पहुंचेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम के प्रभारी ने बताया कि बोर्ड सचिव द्वारा फरवरी के प्रथम सप्ताह तक सभी प्रयोगात्मक परीक्षाएं पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। शेष विद्यालयों में जल्द परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी।

कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्रों से जानकारी लेते शिक्षक।

● 208 विद्यालयों में से 178 विद्यालयों में हो गई संपूर्ण विषय की प्रयोगात्मक परीक्षाएं

मेडिकल कॉलेज में दाखिले को जेल अधीक्षक से 50 लाख ठगे

कार्यालय संवाददाता उन्नाव, अमृत विचार : बेटी को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। उन्नाव के जेल अधीक्षक पंकज कुमार सिंह से कथित काउंसलिंग एजेंसी संचालकों ने लगभग 50 लाख रुपये की ठगी कर ली। अधीक्षक की शिकायत पर सदर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। पीड़ित के अनुसार उन्होंने अपनी बेटी के नीट काउंसलिंग के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए जस्ट डायल के जरिए एक स्टडी कंसल्टेंसी से संपर्क किया था। एजेंसी संचालक ने बाराबंकी स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने का भरोसा दिलाया। इसी के एवज में किस्तों में बड़ी धनराशि ले ली। बताया गया कि अलग-अलग तिथियों में बैंक ड्राफ्ट व आरटीजीएस से 50 लाख रुपये का भुगतान किया गया। कुछ समय बाद जब पीड़ित ने प्रवेश की स्थिति जानने के लिए संपर्क किया तो संबंधित लोगों के फोन बंद मिले। इसके बाद लखनऊ स्थित बताया गया कार्यालय भी बंद मिला। बाद में खुलासा हुआ कि संबंधित व्यक्ति एक संगठित ठग गिरोह के सदस्य हैं। इसके विरुद्ध विभिन्न जिलों में पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोप है कि फर्जी कार्यालय और बैंक खातों के माध्यम से लोगों को गुमराह कर ठगी की जाती थी। सदर कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्रा ने बताया रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

● शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की कार्रवाई

राजकीय वाहन चालक संघ उन्नाव की नई कार्यकारिणी घोषित

उन्नाव, अमृत विचार: राजकीय वाहन चालक संघ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जनपद शाखा का द्विवार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव रविवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया के बाद सर्वसम्मति से विजयकान्त शुक्ला को जिला अध्यक्ष और इन्द्रेन्द्र कुमार को जिला मंत्री चुना गया है। अधिवेशन को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष विजयकान्त शुक्ला ने कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों के हितों की रक्षा करना और विभाग के साथ सामंजस्य बिठाकर उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराना होगा। उन्होंने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए संगठन की मजबूती पर बल दिया। चुनाव अधिकारियों द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार, मोहम्मद महमूद को संरक्षक, मुंशीलाल को वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राकेश कुमार सिंह को जिला उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अन्य पदाधिकारियों में रत्नेश कुमार संगठन मंत्री, रहीस संयुक्त मंत्री, मुनेश्वर प्रचार मंत्री, मनोज कुमार कोषाध्यक्ष, विनोद कुमार वरिष्ठ ऑडिटर और राजू को ऑडिटर के रूप में चुना गया है।

भंडारे के साथ श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ और भागवत कथा का समापन

संवाददाता शुक्लागंज (उन्नाव) **अमृत विचार :** पोनी रोड श्रीनगर स्थित रामलीला मैदान में आयोजित 17वें श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत कथा का रविवार को विधि-विधान के साथ समापन हो गया। श्री भगवती यज्ञ सेवा समिति के तत्वावधान में चल रहे इस धार्मिक आयोजन में सुबह यज्ञ वेदियों में आहुतियां दी गईं और पूर्णाहुति के साथ जनकल्याण की कामना की गई। इसके बाद कन्या पूजन किया गया तथा विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। भंडारे में आसपास के क्षेत्र के लोगों सहित राहगीरों ने भी पूड़ी-सब्जी का प्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर यज्ञ यजमान राजेश बाजपेई, सुरेश दीक्षित, राजकुमार अग्रवाल, निर्भय मिश्रा, उमेश त्रिपाठी, सुरेश शुक्ला, हरीशंकर शुक्ला, उमेश तिवारी, अशोक कुमार दुबे, विनय तिवारी, भरत भुवनेश तिवारी, अनिल अवस्थी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

कथा स्थल पर होता श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ।

आम बजट

सभी वर्ग को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया केन्द्रीय बजट

किसानों व व्यापारियों को राहत, विपक्ष बोला- हवाहवाई

संवाददाता शुक्लागंज (उन्नाव)

अमृत विचार: रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 9वें बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखते हुये अनेक घोषणाएं की है। जिसमें युवाओं को रोजगार, किसानों के हित की योजनाएं, महिलाओं व सीनियर सिटीजन के लिए अनेक योजनाओं का ऐलान किए गए। बजट को दूरदर्शी सोच बताया गया, इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, आत्मनिर्भर भारत और तकनीकी सशक्तिकरण के साथ ही एआई को प्रमुखता दी गई है। आपके अपने अखबार अमृत विचार ने नगर के व्यापारी और आम लोगों से राय जानी। जिस पर व्यापारियों ने बजट को राहत भरा बताया। इसके साथ ही किसानों के लिये कई योजनाएं चालू की गई हैं। जिससे किसानों को राहत मिलेंगी। इसके साथ ही कैंसर की दवाइयों में भी कस्टम ड्यूटी घटने से इलाज कराने वालों को कुछ राहत मिलेगी। वहीं विपक्ष ने बजट को लॉलीपॉप बताया है। क्योंकि इस बजट से छोटे व्यापारी संतुष्ट दिखे। वहीं बड़े व्यापारियां को राहत न मिलने से बजट को हवा हवाई बताया। वहीं सपा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सिर्फ लोगों को भ्रम में रखकर अपना बजट पेश किया है।

बजट पर व्यापारियों और लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रियाएं

बजट में आम लोगों के लिये कुछ नहीं है, यह बजट सिर्फ हवा हवाई है। जिससे लोगों को बजट में कुछ नहीं मिला और आम जनमानस विरोधी है यह बजट किसानों को उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिले, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नये चिकित्सा शिक्षा शोध कैसे होंगें।

वीरेन्द्र शुक्ला समाजसेवी

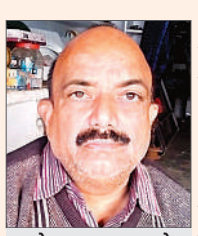

अमरेन्द्र गुप्ता भाजपा नेता

सभी वर्गों को बजट में राहत दी गई है। अगर बजट को अमलीजामा पहनाया गया तो लोगों के हित में होगा। सरकार ने हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखते हुये बजट पेश किया है। जिससे लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा।

शुभ गुप्ता, जिला सचिव समाजवादी पार्टी

हमेशा की तरह इस बार भी बजट निराशाजनक रहा, पहले ही दिन शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया, मजदूर, छोटा दुकानदार, अपने लिए मिली राहत को दूरबीन लेकर भी नहीं ढूंढ पा रहा, उच्च शिक्षा का बजट पहले टोटल बजट का 2.5 प्रतिशत था जिसे घटा कर 0.9 प्रतिशत कर दिया, आज का बजट सिर्फ भ्रमित बयानबाज़ी, और बौद्धिक बतोलेबाजी का रहा।

बाइक हटाने के विवाद में अधेड़ को मारी गोली

शुक्लागंज, उन्नाव : गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र की जाजमऊ चौकी अंतर्गत कल्लू पुरवा निवासी ओम प्रकाश (50) पुत्र बुद्धिलाल रविवार रात को अपने बेटे के साथ ससुराल से बहू को विदा कराने जा रहे थे। गांव के पास स्थित चौराहे पर कुछ युवक सड़क के बीच बाइक खड़ी कर नशेबाजी करते हुए हंगामा कर रहे थे। ओम प्रकाश द्वारा युवकों से बाइक किनारे हटाने को कहने पर उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढ़ने पर युवकों ने अचानक फायरिंग कर दी। गोली ओम प्रकाश के गले और कंधे को छूते हुए निकल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आशीष कुमार कश्यप पुत्र छोटे लाल कश्यप है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है ट्रुटिवश मेरे ड्राइविंग लाइसेन्स मे मेरा नाम आशीष कुमार पुत्र छोटे लाल अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य मे मुझको मेरे सही नाम आशीष कुमार कश्यप पुत्र छोटे लाल कश्यप के नाम से जाना व पहचाना जाये। आशीष कुमार कश्यप पुत्र छोटे लाल कश्यप निवासी मकान नम्बर 8/286. सीताराम कालोनी, शुक्लागंज जिला उन्नाव-209861

जेफरी एपस्टीन फाइल : ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू से पूछताछ का बढ़ा दबाव

लंदन, एजेंसी

- पूर्व प्रिंस पर महिला ने लगाया है यौन संबंध बनाने का आरोप

ब्रिटेन के पूर्व प्रिंस एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर पर यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के अपराधों के स्तर की जांच कर रही अमेरिकी समिति के समक्ष पूछताछ के लिए पेश होने का दबाव बढ़ गया है। विंडसर की शाही स्थिति उनके भाई और ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय ने रद्द कर दी थी।

मामले में एक महिला ने आरोप लगाया है कि एपस्टीन उसे 2010 में तत्कालीन प्रिंस एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए ब्रिटेन ले गया था। महिला का दावा है कि वह विंडसर कैसल एस्टेट स्थित एंड्रयू के शाही निवास में गई थी। ब्रिटिश राजपरिवार के पूर्व सदस्य पर इस तरह का आरोप लगाने वाली यह दूसरी महिला है।

एंड्रयू लगातार आरोपों से इनकार करते रहे हैं। हालांकि, नवीनतम मामले में उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जापान की यात्रा पर गए ब्रिटिश प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने रविवार को इस संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि मैंने हमेशा एपस्टीन के कृत्यों से पीड़ित लोगों को प्राथमिकता देते हुए मामले पर विचार किया है।

एपस्टीन के पत्राचार में मैक्रों का भी जिक्र

वाशिंगटन। जेफरी एपस्टीन ने कथित तौर पर अपने पत्राचार में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का जिक्र किया था, जो एक प्रगतिशील एजेंडा को बढ़ावा देने की संभावनाओं में रुचि रखते थे। नए दस्तावेज़ों में रविवार को यह दावा किया गया। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा प्रकाशित एपस्टीन मामले में एक ई-मेल की कॉपी में यह कहा गया है। यह पत्र सितंबर 2018 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे को एक ऐसी ई-मेल से भेजा गया था।

चिकित्सकों ने तलाश ली घातक सल्फास विषाक्तता की काट

- चंडीगढ़ पीजीआई के डॉक्टरों को मिली बड़ी सफलता

चंडीगढ़, एजेंसी

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा एंव अनुसंधान (पीजीआईएमईआर) के चिकित्सकों ने एल्युमिनियम फॉस्फाइड (जिसे आमतौर पर सल्फास के नाम से जाना जाता है) नामक घातक कीटनाशक से होने वाली विषाक्तता के उपचार में एक बड़ी सफलता हासिल की है।

पीजीआईएमईआर ने एक बयान में बताया कि संस्थान के आंतरिक चिकित्सा विभाग द्वारा किये गए अनुसंधान में पहली बार प्रदर्शित किया गया कि सल्फास की विषाक्तता के इलाज में इंट्रावेनस लिपिड इमल्शन प्रभावी जीवन रक्षक तरीका है। बयान के मुताबिक इन महत्वपूर्ण निष्कर्षों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पत्रिका यूरोपियन रिव्यू ऑफ मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल साइंसेज में प्रकाशित किया गया है, जिससे इस अध्ययन को वैश्विक मान्यता मिली है। पीजीआईएमईआर के मुताबिक अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट होता कि इस इलाज पद्धति को तुरंत इस्तेमाल करने से एल्यूमीनियम फॉस्फाइड विषाक्तता के इलाज में अहम बदलाव आ सकता है। इसमें कहा गया कि अध्ययन के परिणाम बेहद उत्साहजनक थे। जिन रोगियों को मानक चिकित्सा उपचार के अतिरिक्त अंतःशिरा लिपिड इमल्शन दिया गया, उनमें मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई, साथ ही गंभीर चयापचय अम्लता का तेजी से सुधार हुआ, हेमोडायनामिक स्थिरता में सुधार हुआ तथा सदमे और हृदय संबंधी जटिलताओं से पीड़ित रोगियों सहित गंभीर रूप से बीमार रोगियों में बेहतर परिणाम प्राप्त हुए।

कम लागत में अब आसानी से मिलेगा उपचार

चिकित्सकों के मुताबिक इस नवीन उपचार का एक प्रमुख लाभ इसकी व्यावहारिकता है, क्योंकि इंट्रावेनस लिपिड इमल्शन सस्ता है, व्यापक रूप से उपलब्ध है, और पहले से ही भारत भर के अधिकांश अस्पतालों में, जिनमें जिला अस्पताल और परिधीय स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं, स्टॉक में मौजूद है। बयान में कहा गया है कि इसकी कम लागत और आसानी से उपलब्धता के कारण, इस चिकित्सा पद्धति में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों की जान बचाने की क्षमता है, जहां सेल्फ़ोस विषाक्तता का बोझ सबसे अधिक है और उन्नत गहन देखभाल तक पहुंच अक्सर सीमित होती है। संस्थान ने कहा कि कम लागत और आसानी से उपलब्धता के कारण, इस चिकित्सा पद्धति में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी लोगों की जान बचाने की क्षमता है, जहां सेल्फ़ोस विषाक्तता के मामले सबसे अधिक आते हैं और उन्नत गहन देखभाल तक पहुंच सीमित होती है।

गंभीर जन स्वास्थ्य के लिए था चुनौती

इसमें कहा गया कि एल्युमिनियम फॉस्फाइड विषाक्तता एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में, जहां अनाज को संरक्षित रखने के लिए इस यौगिक का व्यापक इस्तेमाल होता है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए एक प्रभावी, किफायती और साक्ष्य-आधारित उपचार की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। बयान के अनुसार, यह अध्ययन पीजीआईएमईआर के आंतरिक चिकित्सा विभाग के डीन (अकादमिक), प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. संजय जैन के मार्गदर्शन में किया गया था।

वर्ल्ड ब्रीफ

सिंगापुर में हिंदुओं ने मनाया थाईपुसम

सिंगापुर। सिंगापुर के संस्कृति मंत्री दिनेश वासु दास ने यहां श्रद्धालुओं के साथ एक धार्मिक उत्सव में भाग लिया। मंत्री ने रविवार को थाईपुसम उत्सव में भाग लिया। उत्सव के तहत श्रीनिवास पेरुमल मंदिर से श्री थेंदायुतुपानी मंदिर तक शोभायात्रा निकाली गई और इस दौरान श्रद्धालुओं ने 3 .2 किलोमीटर तक यात्रा की। श्रद्धालु अपने साथ पालकुडम (दूध के पात्र) लिए हुए थे। हिंदू एंडोमेंट्स बोर्ड (एचईबी) ने बताया कि शोभायात्रा शनिवार देर रात शुरू हुई और रविवार तक जारी रही। शोभायात्रा में सिंगापुर के संस्कृति, समुदाय और युवा एवं श्रमशक्ति मंत्री दिनेश वासु दास और उनकी पत्नी डॉ. रथीगा वेलाइथन भी शामिल थीं।

आइवरी कोस्ट में हादसे में 14 की मौत

अबिजान। आइवरी कोस्ट में शनिवार को एक सड़क हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए। परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह हादसा सुबह करीब पांच बजे कबाडूगू इलाके में हुआ और इसमें एक ट्रक शामिल था जो अनाज ले जा रहा था और जिसमें अवैध रूप से 69 यात्री सवार थे। परिवहन मंत्री अमादौ कोन ने कबाडूगू क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारियों को हादसे की शुरुआती जानकारी इकट्ठा करने के लिए तुरंत मौके पर जाने का निर्देश दिया है।

अमेरिका में गोलीबारी में पांच लोग घायल

न्यूयॉर्क। अमेरिका में लुइसियाना राज्य के क्लिंटन में शनिवार को "मार्डी ग्रास इन द कंट्री परेड के दौरान हुई गोलीबारी में पांच लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह घटना क्लिंटन में पूर्वी फेलिसियाना पैरिश कोर्टहाउस के बाहर हुई। पूर्वी फेलिसियाना पैरिश के शेरिफ जेफ ट्रैविस ने स्थानीय समाचार आउटलेट डब्ल्यूएएफबी को बताया कि घायलों में एक छह साल का बच्चा भी शामिल है। ट्रैविस ने कहा कि तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है और पुलिस गोलीबारी के संबंध में एक गाड़ी की तलाश कर रही है।

थाईलैंड में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू

बैंकॉक। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए पूर्व मतदान रविवार को शुरू हुआ जिसमें 20 लाख से ज्यादा पात्र मतदाता हिस्सा ले रहे हैं, जो आठ फरवरी को आधिकारिक मतदान के दिन अपना वोट नहीं डाल पाएंगे। मतदान शाम 5 बजे समाप्त होगा और आठ फरवरी के बाद सभी मतपत्रों की गिनती की जाएगी। चुनाव में पांच करोड़ से ज्यादा मतदाता कुल 500 सदस्य चुनेंगे।

अमेरिका ने युद्ध छेड़ा तो इस बार पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आएगा

ट्रंप की जंग की धमकी पर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई ने दी चेतावनी

- खामेनेई ने दोहराया, ईरान पर हमलावरों को देंगे कड़ा जवाब

दुबई, एजेंसी

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकी पर पलटवार करते हुए रविवार को चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने हमला किया, तो पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय युद्ध भड़क सकता है। अमेरिकी विमानवाहक पोत अब्राहम लिंकन और इससे जुड़े युद्धपोत फिलहाल अरब सागर में तैनात हैं, जिन्हें ट्रंप ने तेहरान में व्यापक विरोध प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के बाद भेजा था। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप सैन्य ताकत का उपयोग करेंगे या नहीं।

उन्होंने कई बार कहा है कि ईरान बातचीत चाहता है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हल होते हुए देखना चाहते हैं। हालांकि, खामेनेई ने राष्ट्रीय स्तर पर जारी विरोध प्रदर्शनों को तख्तापलट जैसा बताया और कहा कि इससे सरकार का रुख और कड़ा हो गया है। विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद से लाखों लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। ईरान में राजद्रोह के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान है। इससे यह चिंता फिर से बढ़ गई है कि तेहरान गिरफ्तार लोगों को सामूहिक रूप से फांसी दे सकता है। ईरान ने रविवार और सोमवार को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य में सैन्य अभ्यास करने की योजना भी बनाई है। होर्मुज जलडमरूमध्य से बड़ी मात्रा में दुनियाभर में तेल की ढुलाई होती है। खामेनेई ने कहा, अमेरिकियों को यह समझ लेना चाहिए कि यदि वे युद्ध शुरू करते हैं, तो इस बार यह एक क्षेत्रीय युद्ध होगा। खामेनेई ने कहा, हम न तो उकसाने वाले हैं और न ही किसी देश पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन ईरान पर जो कोई भी हमला करेगा उसे ईरानी जनता कड़ा जवाब देगी।

ईयू सेनाओं को आतंकवादी समूह मानता है ईरान

दुबई। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने रविवार को कहा कि इस्लामी गणराज्य अब यूरोपीय संघ की सभी सेनाओं को आतंकवादी संगठन मानता है। उनका यह कड़ा बयान उस फैसले के बाद आया है, जिसमें यूरोपीय संघ ने देशभर में हुए विरोध प्रदर्शनों पर की गई कार्रवाई को लेकर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर क़ालिबाफ द्वारा की गई यह घोषणा मुख्यत: प्रतीकात्मक मानी जा रही है। ईरान 2019 में पारित एक कानून के तहत पहले भी अमेरिका द्वारा रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के जवाब में अन्य देशों की सेनाओं को आतंकवादी संगठन करार दे चुका है।

हालिया प्रदर्शन तख्तापलट जैसा

दुबई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने देशभर में जारी उन विरोध-प्रदर्शनों की तुलना एक तख्तापलट से की, जिनसे वहां की धार्मिक शासन व्यवस्था को चुनौती मिली है। ईरान के सर्वोच्च नेता 86 वर्षीय खामेनेई की ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब विरोध प्रदर्शनों के बाद देश में कथित तौर पर हजारों लोगों को हिरासत में लिया गया है। ईरान में राजद्रोह के आरोपों में मौत की सजा तक का प्रावधान है। ईरान में 28 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे। शुरुआत में ईरानी मुद्रा रियाल के पतन के विरोध में हुए थे। जल्द ही ये खामेनेई शासन के लिए चुनौती बन गए।

फोन टैपिंग मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम से पूछताछ

हैदराबाद। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) रविवार को बीआरएस की पूर्ववर्ती सरकार के दौरान फोन टैपिंग से संबंधित एक मामले में तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) के समक्ष अपने आवास पर पूछताछ के लिए पेश हुए। पूछताछ से कुछ घंटे पहले, राव हैदराबाद से लगभग 70 किलोमीटर दूर येर्रावल्ली स्थित अपने फार्म हाउस से निकले और एसआईटी के सामने पेश होने के लिए नंदी नगर स्थित अपने आवास पर पहुंचे। एसआईटी अधिकारियों का एक दल भी बीआरएस अध्यक्ष के आवास पहुंचा। राव के आवास के पास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, भारी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था और गली को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया था। केसीआर के नाम से चर्चित राव ने शनिवार को एसआईटी से कहा था कि वह एक फरवरी को पूछताछ के लिए पेश होंगे। उन्होंने नोटिस जारी करने में जांच अधिकारी पर कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किए जाने का भी आरोप लगाया। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने रविवार को कांग्रेस सरकार द्वारा उनके नेता के राजनीतिक उत्पीड़न के विरोध में तेलंगाना में प्रदर्शन किया।

सरकारों के हाथ से निजी कंपनियों को जा रही सत्ता

- संरा महासचिव ने किया शांति, न्याय, सतत विकास का आह्वान

न्यूयॉर्क, एजेंसी

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बढ़ते वैश्विक तनाव के बीच शांति, न्याय और सतत विकास के लिए नए प्रयासों का आह्वान किया है। गुटेरेस ने यहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि दुनिया शायद हमारे समय के सबसे बड़े सत्ता हस्तांतरण से गुजर रही है। सत्ता सरकारों से निजी तकनीकी कंपनियों के हाथों में जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी, जब व्यवहार, चुनाव, बाजार और यहां तक कि संघर्षों को आकार देने वाली तकनीकें बिना किसी सुरक्षा घेरे के काम करती हैं, तो प्रतिक्रिया नवाचार नहीं, अस्थिरता होती है।

महासचिव ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष यानि 2026 की प्राथमिकताओं की रूपरेखा पेश करते हुए कहा कि 2026 'अभी से निरंतर आश्चर्य और उथल-पुथल वाले वर्ष के रूप में आकार ले रहा है।' उन्होंने कहा कि अत्यधिक बदलाव के समय में वह उन सिद्धांतों की ओर लौटते हैं, जो बताते हैं कि ताकतें कैसे काम करती हैं। इसमें न्यूटन का तीसरा नियम भी है, जो कहता है कि हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गुटरेस ने कहा, इस वर्ष की शुरुआत में, हम ऐसी कार्रवाइयों को चुनने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं जो ठोस और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करें। हमारे संकटपूर्ण समय में शांति, न्याय, जिम्मेदारी और प्रगति की प्रतिक्रियाएं। महासचिव ने चैन रिएक्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि आज दंड न मिलने का भाव संघर्षों को बढ़ावा दे रहा है, अविश्वास गहरा रहा है और हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।

संरचनाएं पुरानी हो सकती हैं, मूल्य नहीं

संयुक्त राष्ट्र की ओर इशारा करते हुए गुटेरेस ने कहा कि संरचनाएं पुरानी हो सकती हैं, लेकिन मूल्य नहीं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर लिखने वाले लोग समझते थे कि हमारे संस्थापक दस्तावेजों में निहित मूल्य केवल ऊंचे विचार नहीं थे बल्कि स्थायी शांति और न्याय के लिए अनिवार्य शर्त थे।

तुर्किये में बस दुर्घटना में आठ लोगों की मौत

इस्तांबुल। तुर्किये के अंताल्या प्रांत में एक यात्री बस के सड़क से फिसलकर पलट जाने से इसमें सवार आठ लोगों की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकारी प्रसारक टीआरटी द्वारा प्रसारित तस्वीरों में बस डोसेमेल्टी जिले में एक राजमार्ग से फिसलकर पलटती दिखती है। प्रांतीय गवर्नर हुलुसी साहिन ने बताया कि इस दुर्घटना में 26 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर है। समाचार एजेंसी डीएचए के अनुसार, बस के पलटने के बाद कुछ यात्री इसमें से बाहर निकलने में सफल रहे। भूमध्य सागर के किनारे स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल अंताल्या में हाल के दिनों में भारी बारिश हुई है।

धोखाधड़ी में 36 भारतीयों सहित दो हजार गिरफ्तार

नोम पेन्ह, एजेंसी

- कंबोडिया में कैसिनो में छापामारी के दौरान की गई कार्रवाई

कंबोडिया में ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ नवीनतम कार्रवाई के दौरान कुल 2,044 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 36 भारतीय भी शामिल हैं। यह जानकारी कंबोडियाई गृह मंत्रालय ने रविवार को दी। शनिवार को दक्षिणपूर्वी स्वे रींग प्रांत के बावेत शहर में 22 इमारतों वाले एक कैसिनो पर छापेमारी के दौरान आठ अलग-अलग देशों के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार कुल 2,044 विदेशी नागरिकों में 1,792 चीनी, 177 वियतनामी, 179 म्यांमारी, 30 नेपाली, पांच ताइवानी, एक मलेशियाई, दो लाओसी, 36 भारतीय और एक मैक्सिकन नागरिक हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता टच सोखाक ने कहा कि कंबोडियाई सरकार ऑनलाइन धोखाधड़ी में शामिल अपराधियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई में कभी ढील नहीं देगी। उन्होंने कहा कि कंबोडिया अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं बल्कि नरक है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश ने सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था एवं सामाजिक सुरक्षा को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ अभूतपूर्व राष्ट्रव्यापी कार्रवाई शुरू की है। पिछले सात महीनों में 23 देशों के कुल 5,106 धोखाधड़ी के संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया।

इजराइल ने रफाह सीमा को प्रायोगिक तौर पर खोला

काहिरा। इजराइल ने फलस्तीनियों के सीमित आवागमन के मद्देनजर गाजा की मिस्र के साथ रफाह सीमा क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोलने की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद रफाह सीमा क्रॉसिंग पर रविवार को चहल-पहल देखी गई। रफाह सीमा क्रॉसिंग को दोबारा खोलना इजराइल-हमास संघर्षविराम के आगे बढ़ने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इजराइल ने रविवार को घोषणा की कि रफाह क्रॉसिंग को प्रायोगिक तौर पर खोल दिया गया है। गाजा को मानवीय सहायता के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली इज़राइली सैन्य एजेंसी सीओजीएटी ने एक बयान में कहा कि क्रॉसिंग को पूर्ण संचालन के लिए सक्रिय रूप से तैयार किया जा रहा है।

ट्रंप का दावा, भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से खरीदेगा तेल

न्यूयॉर्क, एजेंसी

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा तेल के लिए चीन भी कर सकता है सौदा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब ईरान के बजाय वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। ट्रंप ने शनिवार को फ्लोरिडा के पाम बीच जाते समय एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी इस सवाल के जवाब में की कि क्या चीन वेनेजुएला को दिए गए कर्ज की भरपाई तेल आपूर्ति के बदले कर पाएगा।

ट्रंप ने कहा कि चीन का स्वागत है और वह तेल के मामले में एक बड़ा सौदा कर सकता है। हम चीन का स्वागत करते हैं। हम पहले ही एक सौदा कर चुके हैं। भारत आ रहा है और वह ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। हमने पहले ही यह सौदा कर लिया है, कम से कम इस सौदे की अवधारणा तो तय हो चुकी है। ट्रंप की इन टिप्पणियों पर नई दिल्ली की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भारत 2019 तक ईरानी तेल का एक प्रमुख खरीदार रहा है, लेकिन तेहरान पर अमेरिकी प्रतिबंध दोबारा लगाए जाने के बाद भारत ने ईरान से तेल आयात में काफी कटौती कर दी थी।

ट्रंप के ये बयान ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिकी प्रतिबंधों और इन देशों से कच्चा तेल न खरीदने को लेकर प्रमुख ऊर्जा आयातक देशों पर बनाए जा रहे दबाव की पृष्ठभूमि में आए हैं। हाल के वर्षों में भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल की खरीद में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है, जिससे रूस भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है। अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत तक शुल्क लगाया है, जिसमें रूसी तेल की खरीद के कारण लगाया गया 25 प्रतिशत शुल्क भी शामिल है।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से टेलीफोन पर बातचीत की, जिसमें दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा एवं विस्तृत करने पर सहमति जताई।

आज का भविष्यफल

-पं. मनोज कुमार द्विवेदी

आज की ग्रह स्थिति : 2 फरवरी, सोमवार 2026 संवत-2082, शक संवत 1947 मास-फाल्गुन, पक्ष-कृष्ण पक्ष, प्रतिपदा 3 फरवरी 01 .52 तक तत्पश्चात द्वितीया।

आज का पंचांग

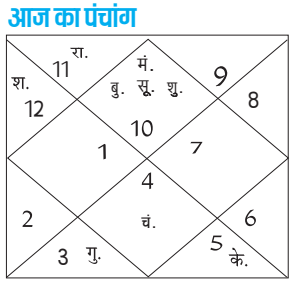

दिशाशूल- पूर्व, **ऋतु**- शिशिर।
चन्द्रबल- वृषभ, कर्क, कन्या, तुला, मकर, कुंभ।
ताराबल- अश्विनी, भरणी, रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, हस्त, स्वाति, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा, उत्तराभाद्रपद, रेवती।
नक्षत्र-अश्लेशा 22 .47 तक तत्पश्चात मघा।

मेष — आज आयात-निर्यात के कारोबार में तेजी आएगी। अधिकारी वर्ग आपकी अनदेखी कर सकते हैं। विरोधियों को हल्के में न लें। अपनी जीवनशैली को सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। धार्मिक साहित्यों की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है।

वृष — आज तीर्थ यात्रा सुखद रहेगी। व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। आप अपनी योजनाओं को लेकर थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में नए दोस्त बन सकते हैं। परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा। धर्म-कर्म के प्रति विश्वास बनाए रखें।

मिथुन — आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को प्रोफेशनल जीवन से अधिक महत्व देंगे। जीवनसाथी से अपने मन की बातें शेयर करने के लिए दिन उत्तम है। प्रेम संबंधों को लेकर परिवार में चर्चा हो सकती है। वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखद रहेगा।

कर्क — आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण करने का दबाव रहेगा। अपने व्यवहार में लचीलापन बनाए रखें। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। आपके ऊपर काफी जिम्मेदारियां रहेंगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में उत्तम सफलता मिल सकती है।

सिंह — आज दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रहेगी। व्यवसाय में आपको कड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। धन लाभ के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। विदेश से जॉब के अवसर मिलने की संभावना है। बुद्धिमान लोगों के बीच आपका दायरा मजबूत होगा।

कन्या — आज दिन का शुरुआती भाग आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आप कुछ नया सीखने को लेकर प्रेरित हो सकते हैं। आपके ऊपर पुराने ऋण को चुकाने का दबाव हो सकता है। संपत्ति के क्रय-विक्रय से बेहतरीन लाभ मिलेगा। शाम को सिरदर्द की शिकायत होगी।

तुला — आज इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का काम बढ़ने वाला है। गुप्त शत्रुओं की वजह से कार्यक्षेत्र में कुछ समस्या हो सकती है। रचनात्मक कार्यों में आप रुचि लेंगे। दूसरों के झगड़ों में मध्यस्थता न करें। ऑनलाइन कारोबार में आपको बड़ा लाभ होगा।

वृश्चिक — आज आय के नए स्रोत विकसित होने के योग बन रहे हैं। उच्च अधिकारियों से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों का भरपूर आनंद लेंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा में शिक्षकों का सहयोग मिलेगा।

धनु — आज आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में वृद्धि होगी। मेहनत के बल पर आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र की राजनीति के कारण आपको समस्या होगी। जॉब में आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है। अपने खर्चों को नियंत्रित रखने का प्रयास करें।

मकर — आज शाम को आपके कुछ काम बिगड़ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके साथ अच्छा करें वही आपको महत्व न दें। नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है। नजदीकी व्यक्तियों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे।

कुंभ — आज फाइनेंस और लोन से जुड़े हुए अटके काम शुरू हो सकते हैं। नए कारोबार की शुरुआत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आपकी इच्छाशक्ति आपके लिए विपरीत परिस्थितियों में ढाल के रूप में काम करेगी।

मीन — आज सहकर्मियों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखें। संपत्ति विवादों का समाधान निकल सकता है। अपने विचारों को दूसरों पर थोपने से बचें। नौकरीपेशा लोगों को अपनी जॉब की चिंता हो सकती है। संतान की चिंता हो सकती है।

सुडोकू-49

सुडोकू एक तरह का तर्क वाला खेल है, जो एक वर्ग पहेली की तरह होता है। जब आप इस खेल को खेलना सीख जाते हैं तो यह बहुत ही सरलता से खेला जा सकता है। सुडोकू खेल में बॉक्स में 1 नंबर से 9 नंबर तक आने वाले अंक दिए हैं। इसमें कुछ बॉक्स खाली हैं, जिन्हें आपको भरना है। कोई भी अंक दोबारा नहीं आना चाहिए। एक सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन तथा बॉक्स में नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए।

			6				8	
	8	9			4			5
3			2			7		
	2			8	9			6
		7				3	9	
9				1			4	
		1			7			8
4			1			9	5	
	9				5			

सुडोकू - 48 का हल

7	6	5	9	3	1	2	4	8
9	4	3	6	2	8	1	5	7
8	2	1	5	7	4	3	9	6
5	9	6	8	1	3	7	2	4
3	7	4	2	5	9	8	6	1
1	8	2	7	4	6	9	3	5
4	3	7	1	6	2	5	8	9
6	1	9	3	8	5	4	7	2
2	5	8	4	9	7	6	1	3

मुझे लगता है कि हमारी टीम को अलग-अलग तरह की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना होगा। चेन्नई में हम तीन मैच खेलेंगे और हो सकता है कि वहां की पिच यहां की पिच की तुलना में अलग हो या फिर वैसी ही हो। और अगर ऐसा होता है, तो हमें पता है कि कैसे खेलना है।
-मिचेल सैंटनर

स्टेडियम

कानपुर नगर, सोमवार, 2 फरवरी 2026

अमृत विचार

www.amritvichar.com

हाईलाइट

लवलीना, पूजा करेंगी भारतीय मुक्केबाजी टीम की अगुवाई

ला नुसिया (स्पेन)। ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और ओलंपियन पूजा रानी मंगलवार को स्पेन के एलिकांटे के ला नुसिया में होने वाले बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 में भारत की 33 सदस्यीय मुक्केबाजी टीम की अगुवाई करेंगी। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल के स्वर्ण पदक विजेता हितेश गुलिया और सचिन सिवाच भी इस टीम का हिस्सा हैं। निकहत ज़रीन (51 किग्रा) ने मार्च के आखिर में होने वाली एशियन चैंपियनशिप जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन के रास्ते में एक अहम कदम है - की तैयारी पर ध्यान देने के लिए इस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है।

गुकेश ने नीमैन को बराबरी पर रोका

विक आन जी (नीदरलैंड्स)। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने टाटा स्टील मास्टर्स के 12वें चरण में रविवार को यहां हांस मोके नीमन के खिलाफ ड्रॉ खेला, जबकि नोडिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने मैथियास ब्लूबाउम पर दमदार जीत दर्ज कर एकल बढ़त कायम करते हुए खिताब की ओर कदम बढ़ा दिया। जावोखिर सिंदारोव ने आर प्रज्ञानानंदा के खिलाफ कोई जोखिम नहीं लिया जिससे उन्हें ड्रॉ पर संतोष करना पड़ा। वह 7.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गए। वह अपने हमवतन अब्दुसत्तोरोव से आधा अंक पीछे हैं। टूर्नामेंट में अब सिर्फ एक दौर का खेल बचा है और उज्बेकिस्तान के इन दोनों खिलाड़ियों ने शीर्ष दो स्थान के साथ साल के पहले सुपर-टूर्नामेंट में अपने देश का दबदबा कायम किया।

विदर्भ से हारकर यूपी रणजी ट्रॉफी से बाहर

नागपुर। गत चैंपियन विदर्भ ने रविवार को यहां उत्तर प्रदेश को चार विकेट से हराकर ग्रुप ए से आंध्र के साथ एलीट रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विदर्भ की टीम ग्रुप ए में आंध्र के बाद दूसरे स्थान पर रही। दोनों टीम ने सात मैच में समान 31 अंक हासिल किए लेकिन आंध्र की टीम बेहतर नेट रन रेट के कारण शीर्ष पर रही। उत्तर प्रदेश के 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विदर्भ की टीम ने चौथे और अंतिम दिन चार विकेट पर 91 रन से आगे खेलते हुए छह विकेट गंवाकर 58.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज अमन मोखाडे 150 गेंद में 83 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके मारे।

देविका सिहाग ने जीता पहला सुपर 300 खिताब

बैंकॉक, एजेंसी

भारत की युवा शटलर देविका सिहाग ने रविवार को यहां 250,000 डॉलर इनामी थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के फाइनल में मलेशिया की गोह जिन वेई के मैच के बीच से हट जाने के बाद अपना पहला बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 खिताब जीता।

हरियाणा की रहने वाली 20 वर्षीय खिलाड़ी देविका तब 21-8, 6-3 से आगे चल रही थी, जब विश्व में 68वें नंबर की खिलाड़ी और दो बार की विश्व जूनियर चैंपियन गोह ने हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया। इससे भारतीय खिलाड़ी अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीतने में सफल रही। उन्होंने कहा मैंने शुरुआत से ही अच्छी गति बनाने की योजना बनाई थी और वह कारगर रही। मेरा मानना है कि वह थकी हुई थीं और उन्हें ऐंठन भी थी। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं। देविका इस जीत के साथ सुपर 300 महिला एकल खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गईं। इससे पहले यह उपलब्धि केवल पीवी सिंधू और साइना नेहवाल ने हासिल की थी। विश्व रैंकिंग में 63वें स्थान पर काबिज देविका बेंगलुरु के पादुकोण-द्रविड़ सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में कोच उमेंद्र राणा के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रही हैं। इसके साथ ही वह इंडोनेशिया के रहने वाले कोच इरवानस्याह आदि प्रतामा की देखरेख में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू के साथ अपने खेल को निखार रही हैं। भारतीय खिलाड़ी क्रॉस कोर्ट और सीधे स्मैश लगाने की अपनी क्षमता और साथ ही बड़ी कुशलता से ड्रॉप शॉट लगाने से जल्द ही 9-2 से आगे हो गईं। इंटरवल तक उन्होंने 11-4 की बढ़त हासिल कर ली। गोह को देविका ने उन्हें कोर्ट पर खूब दौड़ाया।

प्रतिद्वंद्वी मलेशिया की गोह जिन वेई बीच से हटीं

देविका के लिए फाइनल शानदार रहा लेकिन उनकी प्रतिद्वंदी गोह को पीड़ा झेलनी पड़ी। वह फाइनल से पहले तीन गेम तक चले चार मैच खेलने के बाद थकी हुई लग रही थीं और उन्हें कोर्ट को कवर करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पिछले दो वर्षों से फॉर्म और फिटनेस के लिए संघर्ष कर रही गोह ने शनिवार को भी थकान की शिकायत की थी और उन्हें कोर्ट में चलने-फिरने में परेशानी हो रही थी। उनका बायां पैर हिल नहीं पा रहा था और वह परेशान दिख रही थीं। देविका ने फाइनल में शानदार शुरुआत की। उन्होंने अपने दमदार रिटर्न और बेहतरीन स्ट्रोक के दम पर 4-0 की बढ़त बना ली। एक नेट कॉर्ड की बदौलत गोह ने अपना पहला अंक हासिल किया। बाद में उन्होंने मुकाबला बीच में छोड़ दिया।

देविका ने चैंपियन बनने के बाद कहा आज मैं बेहद खुश हूं क्योंकि यह मेरा पहला सुपर 300 खिताब है। मैं भविष्य में और टूर्नामेंट खेलने को लेकर काफी उत्साहित हूं। उन्होंने कहा मैंने यहां बहुत अच्छे मुकाबले खेले। मैंने काफी कुछ सीखा है। यहां मिली सीख को मैं अपने खेल में लागू कर गलतियों को सुधारूंगी। मैच में उतरते समय मैंने जीत या हार के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपना 100 प्रतिशत देने पर ध्यान रखा। इससे मुझे आत्मविश्वास मिला।
-देविका सिहाग

थाईलैंड मास्टर्स

कार्लोस अल्कारेज ने रचा इतिहास

ऑस्ट्रेलियाई ओपन : करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करने वाले बने सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी

मेलबर्न, एजेंसी

कार्लोस अल्कारेज रविवार को यहां फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब अपने नाम करके करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंडस्लैम-ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लेता है तो उसे करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करना कहते हैं।

रिकॉर्ड 25वें ग्रैंडस्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रहे जोकोविच की मेलबर्न पार्क में फाइनल में यह पहली हार है। इससे पहले उन्होंने यहां अपने सभी 10 फाइनल में जीत दर्ज की थी। शीर्ष रैंकिंग वाले खिलाड़ी अल्कारेज ने रविवार को पहला सेट गंवाया लेकिन इसके बाद वापसी करते हुए 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से जीत हासिल की। जीत दर्ज करने के बाद कोर्ट से जाते हुए अल्कारेज ने टीवी कैमरा के लैंस पर हस्ताक्षर करते हुए लिखा, 'काम पूरा हुआ। चार में से चार पूरे हुए।'

बाइस साल के स्पेन के खिलाड़ी ने 38 साल के जोकोविच पर दबाव बनाए रखा। जीत पक्की करने के बाद अल्कारेज ने हाथ से रैकेट छोड़ दिया और वह पीठ के बल जमीन पर गिर गए और अपने हाथ सिर पर रख लिए। जोकोविच से हाथ मिलाने के लिए नेट पर जाने से पहले वह कुछ सेकेंड वहीं रुके। दोनों खिलाड़ियों ने कुछ बातें कीं और जोकोविच स्पेन के खिलाड़ी को बधाई देते हुए मुस्कुराए। इसके बाद नया चैंपियन कोर्ट के एकतरफ लगी कुर्सियों पर बैठे अपने कोच को गले लगाने के लिए दौड़ा और बाद में स्टैंड में अपने पिता और टीम के दूसरे सदस्यों को भी गले लगा। पिछले सत्र के आखिर में अल्कारेज अपने पुराने कोच जुआन कार्लोस फरेरो से अलग हो गए थे और सैमुअल लोपेज उनकी कोचिंग टीम के प्रमख बने।

जोकोविच ने मजाक में कहा कि यह मुकाबला अगले 10 वर्षों के लिए अल्कारेज के साथ उनकी प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत करेगा। उन्होंने हालांकि बाद में कहा कि नए चैंपियन को आगे आने देना ही सही था। दोनों खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में पांच सेट में कड़ी जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। अपनी ऐतिहासिक उपलब्धियों की तलाश में तीन घंटे से अधिक समय तक दोनों ने जबरदस्त फिटनेस, खेल और स्टेमिना का नजारा दिखाया। कोई भी खिलाड़ी बड़े अंकों पर हार मानने को तैयार नहीं था। स्पेन के खिलाड़ी ने 16 ब्रेक प्वाइंट में से पांच का फायदा उठाया जबकि जोकोविच छह ब्रेक प्वाइंट में से सिर्फ दो को ही अंक में बदल सके।

कोई नहीं जानता कि मैं यह ट्रॉफी पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं। मैंने इस पल का बहुत पीछा किया। हमने बस सही काम किया, आप मुझे हर दिन सही काम करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। मैं उन सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं जो अभी मेरे साथ हैं।
-कालोस अल्कारेज

सबसे पहले एक शानदार टूर्नामेंट और शानदार दो हफ्तों के लिए बधाई। आप जो कर रहे हैं उसे बताने के लिए सबसे अच्छा शब्द ऐतिहासिक, दिग्गज है इसलिए बधाई। मैं आपके बाकी करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
-नोवाक जोकोविच

- नोवाक जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराया

करियर ग्रैंडस्लैम

जब कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंडस्लैम-ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकी ओपन का खिताब जीत लेता है तो उसे करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करना कहते हैं।

जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम एकल खिताब का इंतजार बढ़ा

नोवाक जोकोविच के 25वें ग्रैंडस्लैम एकल खिताब जीतने के अभियान पर एक बार फिर अल्कारेज और यानिक सिनर में से एक ने रोक लगाई। इन दोनों ने मिलकर पिछले नौ ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल में सिनर को हराया था और ओपन युगल में ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनने की राह पर थे लेकिन अल्कारेज ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जोकोविच और स्पेन के रफेल नडाल ने कुछ जबरदस्त मैच खेले जिसमें 2012 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का अब तक का सबसे लंबा मैच भी शामिल है जो पांच सेट का फाइनल था और लगभग छह घंटे तक चला था।

अंडर-19 में शॉट लगाते वेदांत त्रिवेदी। एजेंसी

पाकिस्तान को हराकर भारत सेमीफाइनल में

बुलावायो, एजेंसी

वेदांत त्रिवेदी (68) की अर्धशतकीय पारी और निचलेक्रम के बल्लेबाजों की जुझारू पारियों के बाद गेंदबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने अंडर-19 विश्वकप के 36वें मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है।

भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रनों का लक्ष्य दिया। पाकिस्तान 33.3 ओवर में यह लक्ष्य हासिल कर ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच सकता था। जिसमें वह विफल रहा। भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 46.2 ओवर में 194 के स्कोर पर समेट कर उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने समीर मिन्हास (नौ) का विकेट गंवा दिया। खिलन पटेल ने मिन्हास को पगबाधा आउटकर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद उस्मान खान और हम्जा जहूर ने पारी को संभाला और 88 के स्कोर तक ले गए।

17वें ओवर में आयुष म्हात्रे ने उस्मान खान (66) को आउट कर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद कप्तान फरहान यूसफ ने मोर्चा संभाला। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को 151 तक ले गये। पाकिस्तान 35.3 ओवरों तक पांच विकेट पर 168 रन ही बना सका।

अंडर-19 विश्वकप

- भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 252 रन
- पाक को सेमीफाइनल के लिए 33.3 ओवर में हासिल करना था लक्ष्य

भारत के खिलाफ टी-20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करेगा पाकिस्तान

करांची, एजेंसी

- लेकिन टूर्नामेंट में भाग लेगा बांग्लादेश का ले रहा पक्ष

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ आईसीसी टी20 विश्व कप के अपने बहुप्रतीक्षित ग्रुप लीग मुकाबले के बहिष्कार के फैसले की रविवार को औपचारिक घोषणा कर दी, लेकिन सरकार ने सात फरवरी से शुरू हो रहे टूर्नामेंट के बाकी मैचों में राष्ट्रीय टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। यह एक ऐसा कदम, जिसके दूरगामी असर पड़ने की संभावना है।

सरकार के एक आधिकारिक बयान के माध्यम से दिए गए इस निर्णय को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। विश्व निकाय ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के भारत से श्रीलंका में मैच स्थानांतरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पहले कहा था कि वह इस फैसले के बाद टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी की समीक्षा करेगा, क्योंकि वह बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखा रहा है। पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान में कहा कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है, लेकिन टीम 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगी। इस फैसले के साथ टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर चल रही अटकलों का दौर समाप्त हो गया है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हो रहे इस टूर्नामेंट के बीच यह फैसला क्षेत्र में बढ़े राजनीतिक तनाव के माहौल में सामने आया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा पाकिस्तान की सरकार आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भागीदारी को मंजूरी देती है, हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी। भारत-पाकिस्तान मुकाबला किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट का सबसे बहुप्रतीक्षित मैच माना जाता है, जिसे वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दर्शक, प्रायोजकों की रुचि और प्रसारण राजस्व मिलता है। इस मुकाबले के बहिष्कार से आईसीसी के सामने लॉजिस्टिक और नियामकीय चुनौतियां खड़ी होने की आशंका है, क्योंकि टूर्नामेंट के कार्यक्रम, विपणन और व्यावसायिक रणनीति का बड़ा हिस्सा इसी मुकाबले के इर्द-गिर्द तैयार किया गया है। पाकिस्तान सात फरवरी को नीदरलैंड, 10 फरवरी को अमेरिका और 18 फरवरी को नामीबिया से भिड़ेगा।

नॉकआउट चरण की स्थित स्पष्ट नहीं

पीसीबी या सरकार ने हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि अगर प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने आते हैं तो क्या रुख अपनाया जाएगा।

बहिष्कार के नतीजे

प्रतिबंध, नुकसान की भरपाई, पीएसएल पर रोक या अंक नहीं

नयी दिल्ली। आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कई सजा देने वाले कदम उठा सकता है। इसमें इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के आगामी सत्र से टीम पर प्रतिबंध लगाया जाना भी शामिल है। अन्य सजा में शीर्ष सदस्य देशों का पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार करना, भारी वित्तीय जुर्माना और साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग में विदेशी खिलाड़ियों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। आईसीसी बोर्ड के एक सूत्र ने बताया पीसीबी ने अभी तक आईसीसी को आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया है लेकिन चूंकि आधिकारिक घोषणा हो चुकी है इसलिए आईसीसी के कुछ सख्त कार्रवाई करने की उम्मीद है। आईसीसी बोर्ड आज वर्चुअल बैठक करेगा और तय करेगा कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं। अगर उन्हें इजाजत दी जाती है तो पीसीबी को कुछ सख्त सजा हो सकती है। तो पीसीबी के खिलाफ क्या संभावित सजा हो सकती है? सूत्र ने कहा वे एक बाध्यकारी अनुबंध का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए आईसीसी के सदस्य बोर्ड द्विपक्षीय सीरीज के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर सकते हैं। अगर वे द्विपक्षीय सीरीज खेलते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि नतीजों का सभी प्रारूप में आईसीसी रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश की कप्तान मेग लानिंग का विकेट लेने के बाद जश्न मनातीं शिनेल हेनरी।

यूपी का सफर हार के साथ समाप्त

वडोदरा, एजेंसी

मैरीजान कप्प (तीन विकेट), शिनेल हेनरी और श्री चारणी (दो-दो विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के बाद लॉरा वुलफर्ट (47), जेमिमाह रॉड्रिग्स (नाबाद 34) और शेफाली वर्मा (29) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के 20वें मुकाबले में यूपी वॉरियर्ज को आठ गेंद शेष रहते पांच विकेट से हराकर एलिमिनेटर में जगह बना ली है। लगातार तीन सीजन फाइनल खेलने वाली मुंबई की टीम बाहर हो चुकी है।

यूपी का सफर भी हार के साथ खत्म हुआ है। दिल्ली ने एलिमिनेटर में जगह बना ली है। उनके पास लगातार चौथी बार फाइनल खेलने का मौका है। 123 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 11 रन पर अपना पहला विकेट लिजेल ली (10) के रूप में गिरा दिया। इसके बाद लॉरा वुलफर्ट और शेफाली वर्मा की जोड़ी ने 73 रन जोड़े। 13वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने लॉरा वुलफर्ट को आउटकर इस साझेदारी को तोड़ा। लॉरा वुलफर्ट ने 36 गेंदों में सात चौकों की मदद से 47 रन बनाए।

महिला प्रीमियर लीग

- दिल्ली कैपिटल्स पांच विकेट से जीतकर एलिमिनेटर में पहुंची

बढ़ा मनोबल

न्यूजीलैंड के खिलाफ शृंखला में सर्वाधिक रन बना बनाकर टी-20 विश्व कप के लिए जता दिए अपने इरादे

ब्रेक और बल्लेबाजी में कुछ बदलाव से फॉर्म में लौटे सूर्यकुमार

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी

भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि पिछले साल दक्षिण अफ्रीका शृंखला के बाद मिले ब्रेक और बल्लेबाजी में किए गए कुछ बदलाव से उन्हें अपनी फॉर्म में वापसी करने में मदद मिली। सूर्यकुमार ने शनिवार से शुरू होने वाले टी20 विश्व कप से ठीक पहले न्यूजीलैंड पर भारत की 4-1 से जीत में आगे बढ़कर नेतृत्व करते हुए कुछ उम्दा पारियां खेली।

सूर्यकुमार पिछले साल रन बनाने के लिए जूझ रहे थे। वह इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं बना पाए थे लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करके न्यूजीलैंड के खिलाफ शृंखला में सर्वाधिक रन बनाए और उन्हें शृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शृंखला के बाद सूर्यकुमार ने आत्मचिंतन किया और अपने खेल में कुछ बदलाव किए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चार पारियों में वह केवल 34 रन बनाए थे, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 12 रन था। सूर्यकुमार ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत की 46 रन से जीत के बाद कहा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शृंखला के बाद मुझे ब्रेक मिला। मैंने घर लौटने पर अपना किट बैग एक तरफ रखा और नौ-दस दिन तक आराम किया। उन्होंने कहा नए साल की शुरुआत से ही मैंने फिर से अभ्यास करना शुरू कर दिया और पिछले साल की कमियों पर विचार किया। विशेष रूप से शुरुआती ओवरों में मेरे स्ट्राइक रेट पर मैंने चिंतन किया।

सूर्यकुमार ने कहा मैं 2021-23 में शुरुआती पांच-दस गेंदों पर आक्रामक बल्लेबाजी करता था और मेरा स्ट्राइक रेट 200-250 रहता था। अब मैं शुरुआती पांच-सात गेंदों पर संभलकर खेलता हूं और उसके बाद अपना स्ट्राइक रेट दोगुना कर लेता हूं। नागपुर में खेले गए पहले ही मैच से यह रणनीति कारगर साबित हुई, जिससे मुझे लय मिली और मेरी फॉर्म में सुधार हुआ।

भारत के सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाजों में से एक सूर्यकुमार को कप्तानी संभालने के बाद से लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में संघर्ष करना पड़ा था। उन्होंने 2025 में 21 मैचों में केवल 218 रन बनाए। उनका औसत 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 रहा। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पांच मैचों में 80.66 के औसत और 196.74 के स्ट्राइक रेट से 242 रन बनाए। भारत की निगाहें अब लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप जीतने पर टिकी हैं।

टीम संयोजन को बनाया गया है बेहतर

सूर्यकुमार ने कहा कि गेंदबाजी से समझौता किए बिना बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए टीम संयोजन को भी बेहतर बनाया गया है। उन्होंने अपने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा हर खिलाड़ी अपनी अनूठी पहचान लेकर आता है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, संजू सैमसन, सभी राज्य और फ्रेंचाइजी स्तर पर अपनी शैली के अनुरूप बल्लेबाजी करते हैं। मैंने उन्हें अपनी शैली पर बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। सूर्यकुमार ने कहा कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर विकेटकीपर-बल्लेबाज को लेकर अंतिम फैसला शनिवार को वानखेड़े स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ विश्व कप के पहले मैच से पहले लिया जाएगा।